



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

HM
27/9/89

सं० 15]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 15, 1989/ चैत्र 25, 1911

No. 15]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 15, 1989/CHAITRA 25, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than
the Ministry of Defence)

विधि एवं न्याय मंत्रालय

elected candidate, the words "Sponsored by Sikkim Sangram
Parishad" may be inserted.

(विधायी विभाग)

[F. No. 13 (3)/88-Leg. II]

शुद्धि-पत्र

VANAJA N. SARNA, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1989

(विधि कार्य विभाग)

सूचनाएं

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1989

का.आ. 674:—विधि और न्याय मंत्रालय की, भारत के राजपत्र,
असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 30 मार्च, 1988
में प्रकाशित अधिसूचना, संख्या का.आ. 328(अ) दिनांक 30 मार्च,
1988 के पृष्ठ 2 पर, निर्वाचित अर्थार्थी के नाम व पते के पश्चात्:—
शब्द "जो सिक्किम संग्राम परिषद् द्वारा खड़े किए गये हैं", रखे
जायें।

[फा.सं. 13(3)/88-विधायी-II]

वनजा एन. सरना, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th February, 1989

S.O. 674.—In Ministry of Law and Justice, Legislative
Department's Notification No. S.O. 328(E), dated 30th
March, 1988 published in the Gazette of India, Extraordi-
nary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 30th
March, 1988, on page 3 after the name and address of the

910 GI/89-1

का.आ. 675:—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण
में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री रघुवीर सिंह
यादव, अधिवक्ता ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के
अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उन्हें बहरोर में व्यवसाय
करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार
का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप
में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. फा. 5(18)/89-न्याय.]

(Department of Legal Affairs)

NOTICES

New Delhi, the 28th February, 1989

S.O. 675.—Notice is hereby given by the Competent
Authority in pursuance of rule 5 of the Notaries, 1956, that
application has been made to the said Authority, under rule

(859)

4 of the said Rules, by S. L. Raghbir Singh Yadav for appointment as a Notary to practise in Behror.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(18)/89-Judl.]

का.आ. 676:—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सशम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री नानक चन्द गुप्ता, अधिवक्ता ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उन्हें सदर बाजार दिल्ली में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. फा. 5(15)/89-न्याय.]

S.O. 676.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Nanak Chand Gupta, Advocate, for appointment as a Notary to practise in Sadar Bazar area, Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to be undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(15)/89-Judl.]

का.आ. 677:—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सशम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री बी. राजीव हेग्दे, अधिवक्ता ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उन्हें बंगलूर में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. फा. 5(17)/89-न्याय]

S.O. 677.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Sh. B. Rajeeva Hegde, Advocate, for appointment as a Notary to practise in Bangalore.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(17)/89-Judl.]

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1989

का.आ. 678:—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सशम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री अहमद काबर भाई हरानी, अधिवक्ता ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के

अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे ग्रेटर बोम्बे में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. फा. 5(19)/89-न्या.]

कृष्ण दत्त सिंह, सशम प्राधिकारी

New Delhi, the 3rd March, 1989

S.O. 678.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Ahmed Kadarbhai Hirani, Advocate for appointment as a Notary to practise in Greater Bombay.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(19)/89-Judl.]

K. D. SINGH, Competent Authority

गृह मंत्रालय

(प्रान्तरिक सुरक्षा विभाग)

(पुनर्वास प्रभाग)

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1989

का.आ. 679:—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं जी.पी.एस. माही, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त एतद्वारा बन्दोबस्त आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग कर रहे श्रीलंका शरणार्थियों के पुनर्वास आयुक्त तथा तमिलनाडु सरकार के आयुक्त एवं सचिव, लोक विभाग को निम्नलिखित शक्तियों सौंपता हूँ:—

- (1) उक्त अधिनियम की धारा 23 के अधीन अपील सुनने की शक्तियाँ।
- (2) उक्त अधिनियम की धारा 24 के अधीन संशोधन सुनने की शक्तियाँ।
- (3) उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन मामलों के हस्तान्तरण की शक्तियाँ।

2. हमसे भूगर्भय श्रम एवं पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) की दिनांक 23/29-11-1982 की अधिसूचना संख्या-1(19)/विशेष सैन 82-एस.एस.-II (ख) का अधिकरण किया जाता है।

[संख्या: 1(5)/विशेष सैन/88-एस.एस.-II(क)]

जी.पी.एस. माही, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Internal Security)

(Rehabilitation Division)

New Delhi, the 9th February, 1989

S.O. 679.—In exercise of the powers conferred on me under subsection (2) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation), Act, 1954 (44 of

1954) I, G.P.S. Sahi, Chief Settlement Commissioner do hereby delegate to Commissioner of Sri Lanka Refugees' Rehabilitation and Commissioner and Secretary to Government of Tamil Nadu, Public Department, exercising the powers of Settlement Commissioner, the following powers:

- (i) To hear appeals under Section 23 of the said Act.
- (ii) To hear revisions under Section 24 of the said Act.
- (iii) To transfer cases under Section 28 of the said Act.

2. This supersedes Notification No. 1(19)/Spl. Cell/82-SS.II(B) dated 23rd/29th November, 1982 of erstwhile Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Rehabilitation), New Delhi.

[No. 1(5)/Spl. Cell/88-SS.II(A)]

G.P.S. SAHI, Chief Settlement Commissioner

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1989

का.आ. 680:—केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 420 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 120 ख और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम 2) की धारा 5(1) (घ) के साथ पठित धारा 5(2) के अधीन यू. राजेन्द्र भट्ट, प्रबन्धक, आन्ध्र बैंक, गांधी नगर शाखा, बंगलूर और अन्य के विरुद्ध प्रधान सेशन न्यायाधीश, बंगलूर के न्यायालय में मामला सं. आर. सी. 3/85-के.आर.ब्यू., एस.पी.ई., ए.सी.यू. (1) के विचारण का संचालन करने के लिए श्री एल. श्रीनिवासन रेड्डी, अधिवक्ता को विशेष लोक अधिव्योजक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. 225/10/88-ए.वी.डी.-II]

जी. सीतारामन, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS

(Deptt. of Personnel & Training)

New Delhi, the 3rd March, 1989

S.O. 680.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Sh. L. Srinivasa Reddy, Advocate as Special Public Prosecutor for the purpose of conducting the trial of Case No. RC 3/85-CBI, SPE, ACU. I against Sh. U. Rajendra Bhatt, formerly Manager, Andhra Bank, Gandhi Nagar Branch, Bangalore and others under section 120-B read with section 420 of Indian Penal Code (45 of 1860) and section 5(2) read with 5(1)(d) of Prevention of Corruption Act (Act-II of 1947) in the Court of Principal Sessions Judge, Bangalore.

[No. 225/10/88-AVD. II]

G. SITARAMAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1989

का.आ. 681:—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसार में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के नीचे लिखे कार्यालय को, जिसके कर्मचारीबृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:—

1. सीमा शुल्क समाहृतिय (निवारक) बम्बई, बेलाई दरदेट बम्बई-400038.

[सं. 1/89-प्रशा. 4क/फा.सं.ई.-11017/1/89-प्रशा.-4क]

शिव प्रसाद कुण्डु, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 24th February, 1989

S.O. 681.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official purposes of the union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following office of the Central Board of Excise and Customs, the staff where of have acquired working knowledge of Hindi:—

1. Collectorate of Customs (Preventive)
Ballard Estate,
BOMBAY-400038.

[No. 1/89—Admn./F. No. E-11017/1/89-Ad. IV.A]

S. P. KUNDU, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1989

स्टाम्प

का.आ. 682:—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मोदनी भारत इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता को मात्र दो लाख पच्चीस हजार रुपये के उस समेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी करने की अनुमति देती है, जो उक्त कम्पनी द्वारा जारी किए जाने वाले तीन करोड़ रुपये के कुल मूल्य के सौ-सौ रु. के 15% आरक्षित विमोच्य असम्परिवर्तनीय ऋण पत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी के कारण प्रभावी है।

[सं. 10/89-स्टाम्प-फा.सं. 33/72/88-बि. कर]

ORDER

New Delhi, the 27th February, 1989

STAMPS

S.O. 682.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits McNally Bharat Engineering Co. Ltd., Calcutta to pay consolidated stamps duty of rupees two lakhs twenty five thousands only chargeable on account of the stamp duty on 15% Secured Redeemable Non-Convertible Debentures of Rs. 100 each bonds in the form of debentures of the total value of rupees three crores to be issued by the said company.

[No. 10/89-Stamps F. No. 33/72/88-ST]

आदेश

स्टाम्प

का.आ. 683:—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों, का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो तमिलनाडु विद्युत बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले मात्र बीस करोड़ आठ लाख तथा पचास हजार रुपये मूल्य के "10.50% तमिलनाडु विद्युत् बोर्ड ऋण 1996" के रूप में उल्लिखित प्रामिसरी नोट के स्वरूप के बन्ध-पत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी है।

[सं. 11/89-स्टाम्प-फा.सं. 33/39(ख)/88-बि.कर.]

बी.आर. मेहमी, अवसर सचिव

ORDER

STAMPS

S.O. 683.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of Promissory notes described as "10.50% Tamil Nadu Electricity Board Loan, 1996" of the value of rupees twenty crores eight lakhs and fifty thousand only to be issued by Tamil Nadu Electricity Board are chargeable under the said Act.

[No. 11/89-Stamps-F. No. 33/39(B)/88-ST]

B. R. MEHMI, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1989

का.आ. 684:—यतः बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उसके अनुसार केन्द्रीय सरकार ने नेशनल बैंक आफ लाहौर लि. दिल्ली के भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय के लिए 20 फरवरी 1970 को एक योजना मंजूर की थी।

यतः उक्त योजना के खण्ड 6 के उपखण्ड (IX) के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नेशनल बैंक आफ लाहौर लि., दिल्ली की परिसम्पत्तियों का अंतिम रूप से मूल्यांकन नियत तारीख से बारह वर्षों की समाप्ति के पश्चात् अपेक्षित था जो कि नियत तारीख को अनन्तिम रूप से मूल्यांकित कर लिया गया है।

यतः भारतीय स्टेट बैंक ने यह अभ्यवेदन किया है कि बड़ी संख्या में परिसम्पत्तियाँ अन्तर्ग्रस्त होने और बैंक के प्रयासों के बावजूद अधिकांश मदों की वसूलियाँ अभी बाकी होने के कारण बैंक, विलय योजना के खंड 6 के उपखंड (IX) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर परिसम्पत्तियों का अंतिम रूप से मूल्यांकन करने में असमर्थ रहा है।

और यतः केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के बाद इस बात से संतुष्ट है कि विलय योजना को लागू करने में कठिनाई पैदा हो गई है और उतना समय बढ़ा कर जितने में परिसम्पत्तियों का अंतिम रूप से मूल्यांकन अपेक्षित है, उक्त कठिनाई को दूर करना जरूरी है।

अतः अब, नेशनल बैंक आफ लाहौर लि., दिल्ली के भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय की 20 फरवरी 1970 की विलय योजना के खण्ड 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्-

द्वारा निदेश देती है कि भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तथा उसके अनुमोदन से नेशनल बैंक आफ लाहौर लि., दिल्ली की उन परिसम्पत्तियों का, जिनकी वसूली और मूल्यांकन नहीं हुआ है, नियत तारीख से बीस वर्षों की अवधि के भीतर मूल्यांकन करेगा।

[संख्या 17/6/82-बी.ओ.-III]

प्राण नाथ, अवसर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 22nd February, 1989

S.O. 684.—Whereas on 20th February, 1970 a scheme of amalgamation of the National Bank of Lahore Ltd., Delhi with the State Bank of India was sanctioned by the Central Government in exercise of the powers conferred by and in accordance with section 45 of the Banking Regulation Act, 1949.

Whereas under sub-clause (ix) of Clause 6 of the said Scheme, the State Bank of India was required to make a final valuation of the assets of the National Bank of Lahore Ltd., Delhi which have been provisionally valued on the prescribed date, on the expiry of twelve years from the prescribed date.

Whereas the State Bank of India has represented that in view of the large number of assets involved and the recovery of most of the items yet to be realised in spite of its efforts, it has not been able to make the final valuation within the time specified in sub-clause (IX) of Clause 6 of the Scheme of amalgamation.

And whereas the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India is satisfied that a difficulty has arisen in giving effect to the scheme of amalgamation which it is necessary to remove by extending the time within which the final valuation of assets is required to be made.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause 21 of the Scheme of amalgamation dated 20-2-1970 of the National Bank of Lahore Ltd., Delhi with the State Bank of India, the Central Government hereby directs that the State Bank of India shall in consultation with and with the approval of the Reserve Bank of India value the assets of National Bank of Lahore Ltd., Delhi which have not been realised and valued, within a period of twenty years from the prescribed date.

[No. 17/6/82-B.O.III]

PRAN NATH, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1989

का.आ. 685:—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1980 के खण्ड 9 के उप-खण्ड (2) के साथ पठित खण्ड 3 के उप-खण्ड (ख) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री बी. कोटेश्वर राव, विशेष सहायक, आंध्रा बैंक, बैंक स्ट्रीट गुरुकुल (जिला अनन्तपुर) को दिनांक 28-2-1989 से 3 वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वे आंध्रा बैंक के एक कर्मचारी के रूप में अपनी सेवा छोड़ नहीं देते हैं, इसमें से जो भी पहले हो, आंध्रा बैंक के निदेशक बोर्ड में निदेशक नियुक्त करती है।

[संख्या एफ. 15/2/88-आई.आर.]

सतपाल भाटिया, अवसर सचिव

New Delhi, the 28 February, 1989

S.O. 685 :—In pursuance of sub-clause (b) of Clause 3 read with sub-clause (2) of clause 9 of the Nationalised Banks (Management and Miscel-

lanecous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government hereby appoints Shri, V. Koteswara Rao, Special Assistant, Andhra Bank, Bank Street, Guntakal (Anantpur Distt.) as a Director on the Board of Directors of Andhra Bank with effect from 28-2-1989 for a period of 3 years or until he ceases to be an employee of Andhra Bank whichever is earlier.

[No. F. 15/2/88-IR]
S.P. BHATIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1989

का.आ. 686.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खंड 8 के उपखंड (1) के साथ पठित खंड 3 के उपखंड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करते के पश्चात् श्री प्रेमजीत सिंह को 1 अप्रैल, 1989 से आरम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए बैंक आफ बड़ोदा के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करती है।

[संख्या एफ. 9/59/88-बी.ओ.-I(1)]

New Delhi, the 3rd March, 1989

S.O. 686.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3, read with sub-clause (1) of clause 8, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India, hereby re-appoints Shri Premjit Singh as the Managing Director of Bank of Baroda for a period commencing on April 1, 1989 and ending with 31st March, 1990.

[F. No. 9/59/88 BO.I(1)]

का.आ. 687.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खंड 7 के साथ पठित खंड 5 के उपखंड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करते के पश्चात् श्री प्रेमजीत सिंह को जिन्हें 1 अप्रैल, 1989 से बैंक आफ बड़ोदा के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से बैंक आफ बड़ोदा के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या एफ. 9/59/88-बी.ओ.-I(2)]

S.O. 687.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri Premjit Singh who has been re-appointed as Managing Director of Bank of Baroda with effect from April 1, 1989 to be the Chairman of the Board of Directors of Bank of Baroda with effect from the same date.

[No. F. 9/59/88-BO-I(2)]

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1989

का.आ. 688.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध एवं प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खंड 3 के उपखंड (ज) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गयी सारणी के कालम (2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को उक्त सारणी के कालम (3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के स्थान पर कालम (1) में निर्दिष्ट राष्ट्रीयकृत बैंकों का निदेशक नियुक्त करती है:—

सारणी

1	2	3
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	श्री एम.ए. हुसैन, प्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक हैदराबाद	श्री डी.एन. समर्थ
बैंक आफ महाराष्ट्र	श्री एन. डी. परमेश्वरन, संयुक्त मुख्य अधिकारी, डी.पी.ओ.डी., भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई।	श्री एम.के. कपूर

[संख्या 9/12/89-बी.ओ.-I(1)]

New Delhi, March 6, 1989

S.O. 688.—In pursuance of sub-clause (g) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints the persons specified in column (2) of the Table below as Directors of the nationalised banks specified in column (1) thereof in place of the persons specified in column (3) of the said Table:

TABLE

(1)	(2)	(3)
United Bank of India	Shri S.A. Hussain, Manager, Reserve Bank of India, Hyderabad.	Shri D. N. Samarth
Bank of Maharashtra	Shri N.D. Permeshwaran, Joint Chief Officer, DBOD, Reserve Bank of India, Central Office, Bombay.	Shri S.K. Kapur

[No. 9/12/89-BO-I(1)]

का.आ. 689.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना, 1980 की धारा 3 की उपधारा (छ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री आर. रामानुजम, संयुक्त मुख्य अधिकारी, बैंकिंग परिसापन और विकास विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई-400 005 को श्री एम.ए. हुसैन के स्थान पर एतद्द्वारा आन्ध्रा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. एफ. 9/12/89-बी.ओ.-I(2)]

S.O. 689.—In pursuance of sub-clause (g) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government hereby appoints Shri R. Ramanujam, Joint Chief Officer, DBOD, Reserve Bank of India, Central Office, Bombay-400005 as a Director of Andhra Bank vice Shri S. A. Hussain.

[No. F. 9/12/89-BO-I(2)]

का.भा. 690—राष्ट्रीय बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दिनांक 22 मई, 1991 को समाप्त अवधि के लिये, एतद्वारा श्री युवराज करण, वर्तमान महा प्रबन्धक, युनियन बैंक आफ इण्डिया को उसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक के रूप में पदनामित) के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या एफ 9/63/88-बी.ओ-I]

एम.एस. सीतारामन, अधर सचिव

S.O. 690.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3 read with sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri Yuvraj Karan presently General Manager, Union Bank of India, as a whole-time Director (designated as the Executive Director of the same bank for the period commencing with the date of his taking charge and ending with 22nd May, 1991.

[No. F. 9/63/88-BO-I]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय

मध्य प्रदेश

अधिसूचना सं. 38/1989

इन्दौर, 27 फरवरी, 1989

का.भा. 691:—समाहर्तालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, इन्दौर के श्री के.एल. गौड़ प्रशासनिक अधिकारी समूह "ख" नियंत्रण की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31-1-1989 को अपरानुत्त में शासकीय सेवा से निवृत्त हो गए।

[प.सं. II(3)/5 गोप/89]

वासुदेव अग्रवाल, समाहर्ता

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE : M.P.

NOTIFICATION NO. 38/1989

Indore, the 27th February, 1989

S.O. 691.—Shri K. L. Gour, Administrative Officer, Central Excise Group 'B' of Indore Collectorate having attained the age of superannuation retired from Government service on 31-1-1989.

[C. No. II(3)5-Con/89]

B. K. AGARWAL, Collector

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1989

का. भा. 692:—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोजन तथा कर्मचारियों का अनुमन उदा धन से सहगत हो गए है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध निम्नलिखित स्थापनाओं पर लागू किए जायें।

क्रम सं.	स्थापना का नाम व पता	स्थापना की तिथि
1	2	
1.	मै० पान्डीचेरी ट्रीजरी इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि. चीफ सेक्रेटरीट बिल्डिंग, गवर्न एवेन्यू पान्डीचेरी-1	1-9-87
2.	मै० मद्रास थियटर गारमेंट्स, 91, मीर स्ट्रीट मद्रास-600001.	1-11-87
3.	मै० श्री रामा डार्टिंग 1 सेकेण्ड फाइन बीज मद्रास-600001. तथा इसका प्रशासनिक कार्यालय मद्रास-1 और शाखा निवास 2 में स्थित।	1-10-87
4.	मै० गामिना इण्डियाइजेन 300 ए.बी. कम्बाकम रोड पनवटी, मद्रास और इसकी शाखा मद्रास 34 में स्थित	1-2-87
5.	मै० डामु मेडल फिनिशर्स, नं. 57-जी., एन.पी.एम. आई., टी.सी.पी. इन्डस्ट्रीयल स्टेट अम्बेडोर मद्रास- 600098.	1-9-87
6.	मै० सफाई ट्रांसपोर्ट्स, नं. 177 तीमरा मेन रोड, एन.बी. शास्त्री नगर टुनडीवार पट्ट, मद्रास-600081 और इसका प्रशासनिक कार्यालय 58, तीम नार्थ बीच रोड मद्रास-1	1-1-88
7.	मै. आर.के.बी. ट्रांसपोर्ट्स 3 जकर सिरिंग स्ट्रीट मद्रास-1	1-9-87
8.	मै. हर्षस्ट्रो बिल्डिंग एण्ड निटिंग प्रा. लि. 46, मुंगोपेर इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, पाटी पुथुनगर, मद्रास-101	1-1-88
9.	मै. लक्ष्मी पैकेजिंग, अग्रहराम थीपरमनापुर (पोस्ट) कुम्बाकोनम-610022.	1-2-88
10.	मै. श्री काटग मिल्स लि. 46 टी.पी.के. रोड, पल्लनथम मद्रास-3.	1-1-88
11.	मै. ममबलम कोप. रोड, 33 थमबई रेड्डी स्ट्रीट, मद्रास-33	1-11-87
12.	मै. टाई स्टार कमिकल प्रा. लि., 37 एफ., बेलचेरी रोड मद्रास-42 और इसकी शाखा: (i) मद्रास 17 (ii) गुंदूर और (iii) विलारी (कनडिका) में स्थित.	1-10-87
13.	मै. अनुरा फार्मिंग लि., नं. 1, डा. थोसपुथी नगर, पहली गली मद्रास-341	1-6-87
14.	मै. धुमना इन्डस्ट्रियल प्रा. लि., 472, कलगराज रोड, पीलीमडु कोयम्बटूर-641004.	1-9-87
15.	मै. बेंकदेशा रिकार्डरीस 6/61 मुनानूर रोड बेलाकोटा-638111 तमिलनाडु तथा इसकी शाखा: सेमंडलामनाम रोड बेलाकोटा-638111 में स्थित.	1-7-87
16.	मै. प्रिमियर मेडल इण्डस्ट्रीज, 664/1, टी.एच. रोड मद्रास-101	1-3-87
17.	मै. ए.-2566, मुन्नीवालय कोष, मिना प्रोड्यूसर्स सोसाइटी लि. मुन्नीवालय, बटीपार्टी (टी.के.) मन्नेर-जिला.	1-5-87

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम, की धारा (1) की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं को जो जा या उदा प्रशासकीय अधिकारियों को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के नामने धर्मायी गयी है।

[संख्या . क.भ नि.आ./1(4)/तमिलनाडु/31/89]

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND
COMMISSIONER

New Delhi, the 9th March, 1989

S.O. 692 :—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishments namely :—

S. No.	Name and address of the establishment	Date of Coverage
1	2	3
1.	M/s. Pondicherry Tourism Development Corporation Limited, Chief Secretariat Building, Goubert Avenue, Pondicherry-1.	1-9-1987
2.	M/s. Madras Leader Garments, 91, Moore Street, Madras-6600 001.	1-11-1987
3.	M/s. Sri Rama Dye Chem, 4-Second Line Beach, Madras-600 001, including its Adm. office at Madras-1 and branch at Shevapat, Salem-2.	1-10-1987
4.	M/s. Shamsama Enterprises, 300-AB, Kumbakonam Road, Panruti, and its branch at Madras-34.	1-2-1988
5.	M/s. Dandu Metal Finishers, No. 57-G, N.P.S.I.D.C.O. Industrial Estate, Ambattur, Madras-600 098.	1-9-1987
6.	M/s. Safari Transports, No. 177, IIIrd Main Road, L.B. Sastri Nagar, Tonliarpet, Madras-600 081, and its Adm. office at 58, 3rd North Beach Road, Madras-1.	1-1-1988
7.	M/s. R.K.B. Transports, 3, Jaffar Syrang Street, Madras-1.	1-9-1987
8.	M/s. Elasto Weaving & Knitting Mills Pvt. Ltd., 46, Mugappair Indl. Estate, Padi Pouthu Nagar, Madras-101.	1-1-1988
9.	M/s. Lakshmi Packagings, Agraharam, Thepperumanallur (Post), Kumbakonam-4612204	1-2-1988
10.	M/s. Sree Cotton Mills Ltd., 46, T.P.K. Road, Palanganatham, Madurai-3.	1-1-1986
11.	The Mumbalium Cooperative Centre, 33, Thambiah Reddy Street, Madras-33.	1-11-1987

1	2	3
12.	M/s. Tristar Chemicals Pvt. Ltd., 37-F, Velacherry Road, Madras-42 and its branch at (i) Madras-17, (ii) Guntur-3 and (iii) Bellary (KN)	1-10-1987
13.	M/s. Anura Finance Ltd., No. 1, Dr. Thirumurthy Nagar, 1st Street, Madras-34.	1-6-1987
14.	M/s. Sukshma Dynamics Pvt. Ltd., 472, Kamarajar Road, Pzalemdu, Coimbatore-641 004.	1-9-1987
15.	M/s. Venkatesa Refineries, 6/51, Mulanur Road, Vellakoil-638111, Tamil Nadu. Including its branch at Semmandapalayam road, Vellakoil-638111.	1-7-198
16.	M/s. Premier Metal Industries, 664/1, T.H. Road, Madras-19.	1-8-1987
17.	M/s. A 2566, Millipallam Cooperative Milk Producers Society Ltd., Mullipallam, Vadipatti (TK) Madurai, District.	1-5-1987

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section I of the said Act, The Central Provident Fund Commissioner hereby applies the Provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the dates mentioned against the name of each of the said estts.

[No. CPFC/1(4)/TN/(31)/89]

का.प्र. 693 :—केन्द्रीय भविष्य निधि प्रायुक्त को जहां यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं में सश्रद्धा नियोजन तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हो गए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध निम्नलिखित स्थापनाओं पर लागू किए जायें।

क्र.सं.	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3
01	मै. स्पारर इन्टरनेशनल मार्केटिंग सर्विसेज लि., ई.-240, ईस्ट ऑफ कैलाश नदी दिल्ली-65. और इसका रजि. आफिस बंगलूर-58 और शाखाएँ इन्दौर और जयपुर में स्थित	1-7-87
02	मै. बीनीज टीआईन स्ट्रेचियो प्रा. लि. 22 फिरोज गांधी रोड, लाजपत नगर-III नई दिल्ली-21	1-1-88
03	मै. रामायण हैडक्वार्टस एन-12 मार्केट ग्रेटर कैलाश-1 नई दिल्ली-48	1-4-88
04	मै. ओरडे इन्वेस्टमेंट्स लि. 1/11 बी पाहुवा मेनसन आसफ अली रोड, नई दिल्ली-2	1-11-87

क्र.सं. संस्थान का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि	S. Name & address of the Establishment No.	Date of Coverage
05. मै. विशाल मेन्टेनेन्स कम्पनी इ-211 श्रमर कालोनी वाजपय नगर-4 नई दिल्ली-24	1-1-88	05. M/s. Visha Maintenance Company, E-211, Amar Colony, Lajpat Nagar-IV, New Delhi-24.	1-1-88
06. मै. पेस्टिंग हाउस सी-41, 42 (फ्लैट पलीर डी.डी.ए. रोड, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-20	1-6-88	06. M/s. Pasting House, C-41, 42, (First Floor), DDA Sheds, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-20.	1-6-88
07. मै. अग्रो डायनमिक्स प्रा. लिमिटेड बी.-213 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, नई दिल्ली-20 और इसका रजि. ऑफिस 12, मिथिया हाउस, कनाट सर्कस, नई दिल्ली में स्थित।	1-6-88	07. M/s. Agro Dynamics (P) Ltd., B-213, Okhla Indl. Area, Phase-I, New Delhi-20 including its Regd. Office at 12, Scindia House, Connaught Circus, New Delhi-1.	1-6-88
08. मै. भारत एंटरप्राइजेज 5/71 कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली-15।	1-3-88	08. M/s. Bharat Enterprises, 5/17. Kirti Nagar, Industrial Area, New Delhi-15.	1-3-88
09. मै. कार्पेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल डी 2/21, शोपिंग कम्प्लेक्स, सफरजंग एन्क्लेव नई दिल्ली-29, और इसका रजि. ऑफिस जी-27, सेक्टर-9 नोयडा जि. गाजियाबाद (उ.प्र.)	1-12-83	09. M/s. Carpet Export Promotion Council, B-2/21, Shopping Complex, Safdarjung Enclave, New Delhi-29, including its Regd. Office at G-27, Sector 9, NOIDA, Dist. Ghaziabad (UP)	1-12-83
10. मै. एच.बी.डी. पैकेजिंग (प्रा.) लि. सी-41 डी.डी.ए. रोड, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-20	1-6-88	10. M/s. HBD Packaging (P) Ltd., C 41, DDA Sheds Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-20.	1-6-88

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं को उस तिथि से या प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

[संख्या: के.भ.नि.प्रा./1(4)/बी. एल./32/89]

S.O. 693 :—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employers' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishments namely :—

Sl. Name & Address of the Establishment No.	Date of Coverage
01. M/s. Sparr International Marketing Service Ltd., E-240, East of Kailash, New Delhi-65 including its Regd. Office at Bangalore-58 and branches at Indore and Jaipur.	1-7-87
02. M/s. Bonnies Design Studio Pvt. Ltd., 22, Feroze Gandhi Road, Lajpat Nagar-III, New Delhi-24	1-1-88
03. M/s. Ramayana Handicrafts, N-12, Market Greater Kailash-I, New Delhi-48.	1-4-88
04. M/s. Orde Investments Ltd., 1/11, -B, Pahwa Mansion, Asaf Ali Road, New Delhi-2.	1-11-87

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section I of the said Act, The Central Provident Fund Commissioner hereby applies the Provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the dates mentioned against the name of each of the said establishments.

[N : CPFC/1(4)/DL(32)/89]

का. प्रा. 694 :—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोजन तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हो गए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध निम्नलिखित स्थापनाओं पर लागू किए जायें।

क्र.सं.	संस्थान का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
01.	मै. सैनवलि क्लीनिक, आरएण्ड आर ले-आउट, सतमुर्गा थियेटर के पीछे, मट्ट पञ्चायतम रोड, कोयम्बटूर-2	1-1-88
02.	मै० फोर्टम (इंडिया) फार्मैस्युटिकल्स, IV-55 फेरीट एवेन्यू, मद्रास-96	1-12-87
03.	मै. इंडरफैक्स, फ्ल. 4, टिप्पू रोड, मुम्बई-2	1-9-87
04.	मै. होमर बायर नोडक्टस, 133-बी, मिपकट इण्डस्ट्रियल पोम्पवैक्स, होमूर-26	1-1-86
05.	मै. स्वीफ्ट ओटोमोबिलिजिओ इन्टरटेनमेन्टस (प्रा.) लि., 197, 24 बी पृष्ठ स्ट्रीट, धीरुवन्मसिम्बर मद्रास-41	1-12-87
06.	मै. कटफास्ट पोलीमर्स प्रा. लि., पल्लीकरनई मद्रास-73	1-1-88

क्र.सं.	संस्थान का नाम व पता	व्यक्ति की तिथि	1	2	3
07.	मै. निलगिरीस वेस्ट कट्टोण एजेन्सीस, 258 बी, गोलाई हिन्द इटीन्स रोड, ओनटाकमंड (निलगिरी)	1-3-88	3.	M/s. Inter Flex, No. 4, Trichy Road, Suler-2.	01-09-87
08.	मै. ग्रिफिन टच, 13, मैकन्ड लाईन बीच, मद्रास-1 तथा इसकी फैंक्ट्री, 18 ए. स. एस. मैन्शन, 15, पुरासावाळिम हाई रोड, मद्रास-7	1-2-88	4.	M/s. Hosur Wire Products, 133-B, Sipeut Industrial Complex, Hosur-26.	01-01-86
09.	मै. मोडर्न सिक्योरिटी सर्विस, 480, नन्दनाम, मद्रास-35	1-7-87	5.	M/s. Swift Audio Video Entertainments (P) Ltd., 197, 24th East Street, Thiruvannmiyur, Madras-41.	01-12-87
10.	श्री प्रोविडेंट फंड इम्प्लाइज कोप. सोसायटी लि., 20, रोजपट्टा हाई रोड, मद्रास-14	1-2-88	6.	M/s. Cutfast Polymers (P) Ltd., Pallikaralai, Madras-73.	01-01-88
11.	मै. कोटन ऐपरल कोप., नं. 9, ब्रॉडवे, फर्स्ट फ्लोर, मद्रास-8	1-12-87	7.	M/s. Nilgiris Pest Control Agencies, 258, B, Gulai Hind, Ettiness Road, Onetacamund (Nilgiri).	01-03-88
12.	मै. इंडियन इंजिनियरिंग एजेन्सीस, 237, गोविन्दप्पा नायकन, स्ट्रीट, मद्रास-1 तथा इसकी शाखा एवेन्यु रोड, बैंगलूर-2 में स्थित	1-2-88	08.	M/s. Griffins Touch, 13, Second Line, Beach, Madras-1, including its factory at 18, S.S. Mansion 15, Purasawalkim, High Road, Madras-7.	1-2-88
13.	मै. दि पालिकोन्डा कोप. प्रारबन बैंक लि., पालिकोन्डा, नार्थ अर्कोट जिला	1-3-88	09.	M/s. Modern Security Service, 480, Nandanam, Madras-35.	1-7-87
14.	मै. फ्री स्टाइल गार्मेन्ट्स, 226, थम्बु चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-1	1-1-88	10.	The Provident Fund Employees' Cooperative Society Ltd., 20, Royapettah High Road, Madras-14.	1-2-88
15.	मै. ह्यूमान रिप्रोडक्शन रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सरकारी प्रार. एस. प्रार. एम. लाईंग हॉस्पिटल में रायपुरम, मद्रास-13	1-1-88	11.	M/s. Cotton Apparel Corporation No. 19 Broadway, 1st Floor, Madras-8.	1-12-87
16.	मै. श्री अन्नपुर्णा फूड्स, 15/9, रंगास्वामी रोड, प्रार. एस. पुरम, कोयम्बटूर-2	1-1-88	12.	M/s. Indian Engineering Agencies, 237, Govindappa Naicken Street, Madras-1, including its branch at Avenue Road, Bangalore-2.	1-2-88
17.	मै. सिगुल सिक्योरिटी इग्नो 226, थम्बु चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-1	1-10-87	13.	M/s. The Pallikonda Co-op. Urban Bank Ltd., Pallikonda, North Arcot Distt.	1-3-88
18.	मै. इरिकसन एण्ड रिचर्ड्स मद्रास प्रा. लि., राजाजी साला, पहली मंजिल, मद्रास-1	1-3-88	14.	M/s. Free Style Garments, 226, Thambu Chetty Street, Madras-1.	1-1-88
			15.	M/s. Human Reproduction Research Centre Indian Council of Medical Research, Govt. RSRM Lying in Hospital, Royapuram, Madras-13.	1-1-88
			16.	M/s. Sree Annapoorna Foods, 15/9, Rengaswamy Road, R.S. Puram, Coimbatore-2.	1-1-88
			17.	M/s. Scagull Security Bureau 226, Thambu Chetty Street, Madras-1.	1-10-87
			18.	M/s. Erricson & Richards (Madras) Pvt. Ltd., 48. Rajaji Salai, First Floor, Madras-1.	1-3-88

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि प्रायुक्त, उक्त अधिनियम की धारा I की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं को उस या उस प्रकाशित तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

[सं : के. अ. नि. प्रा. / 1 (4) टी एन (33) / 89]

S.O. 694:- Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishments namely :-

Sl. No.	Name and Address of the Establishment	Date of Coverage
1	2	3
1.	M/s. Senthil Clinic, R & R Layout, behind Shanmugar Theatre, Mettupalayam Road, Coimbatore-2.	01-01-88
2.	M/s. Fourts (India) Pharmaceuticals, IV/55, Facit Avenue, Madras-96.	01-12-87

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Provident Fund Commissioner hereby applies the Provisions of the said Act to the above-mentioned establishments from and with effect from the dates mentioned against the name of each of the said establishments.

[No. CPFC/1(4)/TN/(33)/89]

का. आ. 695.—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित निर्देशना तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हो गए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध निम्नलिखित स्थापनाओं पर लागू किए जायें।

क्र. सं.	संस्थान का नाम व पता	स्थापित की तिथि
01.	मै. कुमार मेटल इन्डस्ट्रीज, 266, मत्तुपालायम रोड, कायंबटूर-641043	1-2-88
02.	मै. स्कोरपियन सिक्योरिटी सर्विस कबोलिव नैन्टर, 64, अरमेनियन स्ट्रीट, मद्रास-600001	1-10-87
03.	मै. एसोसियेटेड मिलर्स प्रा. लि., 27, आनन्दा रोड, अलवरपट, मद्रास-10 तथा उसकी शाखा (1) सं. 22, राजगीर चैम्बरस, तीसरी मंजिल, 12/14, शाहीद भगतसिंह मार्ग, पुराने कस्टम हाऊस के पीछे, बम्बई-400023 (2) एम ए 169, सुपरवाइजरी फ्लैट, गर्ल्स ग्रेजुएट स्कूल के सामने साक्वी जमशेदपुर-831001 (3) आनन्द, निवास, प्रजोक्त मार्ग, "सी" स्कीम, जयपुर स्थित	1-11-87
04.	मै. ए. ए. पी. एसोसियेटेड, 184-ग, तीसरी गली सेन्ट पैट्रिक चर्च रोड, सेन्ट थोमस मार्केट, मद्रास-16, तथा इसका प्रशासनिक कार्यालय नं. 29, मार्केट पुनामली रोड, नन्दाबैकम, मद्रास-600087 में स्थित	1-1-88
05.	मै. जर्नेल मोल्डर्स, 25, गणेश नगर, अलपाकम, मद्रास-602104 तथा इसका कार्यालय नं. 49, ए. वी. एम. एवेन्यू, मद्रास-92 में स्थित	1-1-88
06.	मै. श्री रामचन्द्रा एजुकेशनल एण्ड हेल्थ ट्रस्ट, नं. 1, रामचन्द्रा नगर, पोन्नर, मद्रास-602104	1-12-87
07.	मै. विनोद कप्रा एन्टरप्राइजेज, सं. 16, विश्वलुर्ब स्ट्रीट, मनाली, मद्रास-68	1-1-88
08.	मै. आर्टो क्राफ्ट, 29-वी, मार्केट पुनामली, रोड, नन्दाबैकम, मद्रास-89	1-1-88
09.	मै. जितकन लैटर बोयर्स इंडिया, 684, मार्केट, रोड, हूखरो मंजिल, मद्रास-6 और इसका कार्यालय—56-सी, सिडहम्स रोड, पेरियामैट, मद्रास-3 में स्थित.	1-12-87
10.	मै. सेंट्स परिसीमन प्रोडक्श, उलावगम, गणपति, कोयम्बटूर-6	1-2-88
11.	मै. हिन्दु सीड्स (प्रा.) लि., नं. 30 लाथी रोड, कोयम्बटूर-40 तथा इसकी शाखा मिनाकी जिनिंग फैक्ट्री प्रीमियेस परिसलयुई रोड, सेठे-2 में स्थित	1-2-88
12.	मै. अरुण एन्टरप्राइजेज, 16, पहली स्ट्रीट, कामराज नगर, एन्नोर, मद्रास-57	1-2-88
13.	मै. मधुरई इम्प्लाइज प्रो. फन्ड इम्प्लाइज कोप, कौन्टीन लि. एल. डी. सी. रोड, मन्गुरे-2	1-5-88
14.	मै. टी. एम. स्पीनर्स एंड डबलर्स, सी-24, कोयम्बटूर प्रा. इण्डस्ट्रियल इस्टेट, कोयम्बटूर-64-1021	1-7-87

क्र. सं.	संस्थान का नाम व पता	स्थापित की तिथि
15.	सेन्ट सेरीम मैट्रीकुलेशन स्कूल नं. 200, बड़ा बाजार स्ट्रीट, अरनी नार्थ ग्रामकोट जि.	1-11-87
16.	मै. महर्डी बिस्टा प्रा. लि., 69, विन्नेज रोड, नुगमवैकम, मद्रास-600034 तथा इसका प्रशासनिक कार्यालय 7-ए, मेरिम गेट रोड, अलवरपट, मद्रास-18	1-1-88

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त स्थापनाओं को उक्त या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करने के जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

[सं. के. भ. नि. आ. 1(4)/टी. एन. (34)/89]

S.O. 695.....:—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishments namely :—

Sl. No.	Name & Address of the Estt.	Date of Coverage
1	2	3
01.	M/s. Kumar Metal Industries, 266, Mettupalayam Road, Coimbatore-641043	1-2-88
02.	M/s. Scorpion Security Service Catholic Centre, 64, Armenian Street, Madras 600001.	1-10-87
03.	M/s. Associated Millers Pvt. Ltd., 27, Ananda Road, Alwarpet, Madras-18 and its branches at : (1) No. 22, Rajgir Chambers, 3rd Floor, 12/14, Shahid Bhagat Singh Marg, Opp. Old Custom House, Bombay-400023. (2) SA 169, Supervisory Flat, Opp. Girls Graduate School Sakhi, Jamshedpur-831001. (3) Anand Niwas, Ashok Marg, 'C' Scheme Jaipur.	1-11-87
04.	M/s. A.A.P. Associates, 164-A, 3rd Street, St. Patrick Church Road, St. Thomas Mount, Madras-16 including its administrative Office at No. 29, Mount Poonamallee Road, Nandambakkam, Madras-600087.	1-1-88
05.	M/s. General Moulders, 25, Ganesh Nagar, Alapakkam, Madras-602104, and office at No. 49, A.V.M. Avenue, Madras-92.	1-11-87

1	2	3
06. M/s. Sri Ramachandra Educational and Health Trust, No. 1, Ramachandra Nagar, Porur, Madras-602104.	1-12-87	
07. M/s. Vinod Kanna Enterprises, No. 16, Thiruvalluvar Street, Manali, Madras-68	1-1-88	
08. M/s. Auto Craft, 29-B, Mount Poonamallee Road, Nandambakkam, Madras-89.	1-1-88	
09. M/s. Linton Leather Wear India, 684, Mount Road, 11nd Floor, Madras-6 and its office at 56-C, Sydenhams Road, Periament, Madras-3.	1-12-87	
10. M/s. Roots Precision Products, Ulavagam, Ganapathy, Coimbatore-6	1-2-88	
11. M/s. Hindu Seeds (P) Ltd., No. 30, Lawley Road, Coimbatore-40, and branch at Meenakshi Ginning Factory Premises, Parialthurai, Road, Sathy-2.	1-2-88	
12. M/s. Arun Enterprises, 16, First Street, Kamaraj Nagar, Ennore, Madras-57.	1-2-88	
13. M/s. Madurai Employees' Provident Fund Employees' Co-op. Canteen, Ltd., L.D.C. Road, Madurai-2.	1-5-88	
14. M/s. T.M. Spinners & Doublers, C-24, Coimbatore Pvt. Industrial Estate, Coimbatore-641021.	1-7-87	
15. M/s. St. Marry's Matriculation School No. 200, Big Bazar Street, Arni North Arcot Distt.	1-11-87	
16. M/s. Multi Vista Pvt. Ltd., 69, Village Road, Nurgambakkam, Madras-600034 and its Adm. Office at 7A, Murrays Gate Road, Alwarpt, Madras-18.	1-1-88	

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section I of the said Act, the Central Provident Fund Commissioner hereby applies the Provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the dates mentioned against the name of each of the said establishments.

[No : CPFC/1(4)/TN(34)89]

का. आ. 696.—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हो गए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध निम्नलिखित स्थापनाओं पर लागू किए जायें।

क्र. सं.	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	मे. फेलिक्स ब्रक्समेयर एण्ड कं., 105, हनुमान इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, 42/बी, जी. डी. आंबेडकर मार्ग, बडाला, बम्बई-400031.	1-1-79

1	2	3
2.	मे. इंडियन ड्रग मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन, 102-बी, पुनम चैम्बर्स, डा. ए. बी. रोड, वरली, बम्बई-400018, तथा इसकी शाखा: एस.-1866, चित्रंजन पार्क, नई दिल्ली स्थित.	1-7-79
3.	मे. शिवाजी-नगर सहकारी बैंक लि., 26/5 "गीतांजली" नरवीर तानाजीवाड़ी, शिवाजी नगर, पुणे-411005.	1-3-88

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1, की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं को उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाये गये हैं।

[संख्या. के. भ. नि. आ./1(4) महा. (35)/89]

S.O. 696. —Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishments namely :—

S.No.	Name & address of the Establishment	Date of Coverage
01.	M/s. Felix Braxmeier & Co., 105, Hanuman Industrial Estate, 42/B, G.D. Ambedkar Marg, Wadala, Bombay-400 031.	1-1-1979
02.	M/s. The Indian Drug Manufacturers' Association, 102-B, Poonam Chambers, Dr. A.B. Road, Worli, Bombay-400 018 including its branch at S-1866, Chitrangan Park, New Delhi.	1-7-1979
03.	M/s. Shivaji-nagar Sahakar Bank Ltd., 26/5, Gitanjali, Narveer Tanajiwadi, Shivajinagar, Pune- 411005.	1-3-1988

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section I of the said Act, The Central Provident Fund Commissioner hereby applies the Provisions of the Act to the above mentioned establishments from and with effect from the dates mentioned against the name of each of the said establishments.

[No. CPFC/1(4)MH/(35)/89]

का. आ. 697.—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हो गए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध निम्नलिखित स्थापनाओं पर लागू किए जायें।

क्र. सं.	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	मे. वैशन्वी इंडस्ट्रीज, ए. 16, सिडको इंडस्ट्रीयल इस्टेट, कोडुनगूर, मद्रास-51.	1-6-88

क्र. सं.	स्थापना का नाम या पता	व्याप्ति की तिथि
2.	मै. आर. टी. सी. लॉज (होटल), नं. 9, नन्धी कोइल स्ट्रीट, त्रिची-620002.	1-1-88
3.	मै. एम. कुमारसामी चेट्टियार एण्ड कं., साउथ III स्ट्रीट, पुडुकोटाई.	1-6-88
4.	मै. दी सल्वेशन आर्मी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर द फिजिकली हैंडिकेपड, वेट्टूरनीमायम, नागरकोइल-629003, जिला—कन्याकुमारी.	1-9-88
5.	मै. वेल मिल्क डिपो, माजिद बिल्डिंग्स, 50, संवायपट रोड, धर्मापुरी-2.]	1-5-88
6.	मै. आईट सिन्योरिटी एण्ड डिडेक्टिव, ब्यूरो, एल.—92, हुडको कालोनी, टेम्पल लैंड, होसूर-635125, जिला—धर्मपुरी.]	1-8-88
7.	मै. मुथिया पालायकट कंपनी, 36, मरियम्मम कोइल स्ट्रीट, विजापाल्लम, कुरन्जीपाडी-607302. इसकी शाखा अमर नगर, पेपर मिल रोड, पालीपलायम, इरोड.	1-1-88
8.	मै. बी. ओ. जिम्मी कैशेव प्रा. लि., 290-बी, कुम्बाकोणम रोड, पनकुडी-6.	1-4-88
9.	मै. कास राईस मिल, गुण्डुसलाई रोड, आलपट्टाई मंजाकुप्पम, कुडालोर-607001.	1-7-88
10.	मै. जी. के. आर. इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, ए.-16, मिडको इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, आरुमबाक्कम, मद्रास-600106.	1-7-88
11.	मै. वेलमुगन इण्डस्ट्रीज, डेवलपड, प्लॉट नं. ई. 53-54, थुवाकुडी, त्रिची-15.	1-3-88
12.	मै. श्रीबालाजी इण्डस्ट्रीज, टी.-78, डेवलपड प्लॉट्स, थुवाकुडी, त्रिची-15.	1-4-88
13.	मै. श्री वेंकटेश्वारा ऑयल मिल्स, 9ए, पीयरीआम्मन कोइल स्ट्रीट, तिरुकोयलूर, साउथ आरकोट जिला,	1-6-88
14.	मै. टी. एस. आर. लसिंग होम, 127, थिरु-वी-का रोड, विल्लुपुरम, साउथ आरकोट जिला.]	1-4-88
15.]	म. वेबो करिया इंजीनियरिंग वर्क्स, प्लॉट नं. 1, कुमारामंगलम इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, माथुर, त्रिची—जिला.] तमिलनाडु.	1-4-88

अतः केन्द्रीय सविष्य निधि प्रायुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं को उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

[गंध्या : सी. पी. एफ. सी./1(4)ममिलनाडु/(36)/89]

S.O. 697.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishments namely :—

S.No.	Name and address of the establishments	Date of Coverage
1.	M/s. Vaishnavi Industries, A.16, Sidco Industrial Estate, Kodungaiyur, Madras-51.	01-06-88
2.	M/s. R.T.C. LODGE (Hotel), No. 9, Nandhi Koil Street, Trichy-620002.	01-01-88
3.	M/s. S. Kumarasamy Chettiar and Co., South III Street, Pudukkottai.	01-06-88
4.	M/s. The Salvation Army Vocational Training Centre for the Physically Handicapped, Vettoornimadam, Nagercoil-629 003. Kanyakumari District.	01-09-88
5.	M/s. Vel Milk Depot, Majid Buildings, 50, Sandaipet Road, Dharampuri-2	01-05-88
6.	M/s. Bright Security and Detective Bureau, L-92, Hudco Colony, Temple Land, Hosur-635 125 Dharampuri District.	01-08-88
7.	M/s. Muthia Palaykat Company, 36, Mariamman Koil Street, Vizhapallam, Kurinjipady-607302 and its branch at Amman Nagar, Paper Mill, Pallipalayam, Erode.	01-01-88
8.	M/s. B.O. Jimmi Cashew Pvt. Ltd., 290-B, Kumbakonam Road, Panruti-6	01-04-88
9.	M/s. Kannan Rice Mill, Gundusalai Road, Allpettai, Manjakuppam, Cuddalore-607001.	01-07-88
10.	M/s. G.K.R. Engineering Industries, A.16, SIDCO Indl. Estate, Arumbakkam, Madras-600106.	01-07-88
11.	M/s. Velmurugan Industries, Developed Plot No. E-53-54, Thuvakudi, Trichy-15.	1-3-88
12.	M/s. Sri Balaji Industries, D.78, Developed Plots, Thuvakudi, Trichy-15.	01-04-88
13.	M/s. Sr. Venkateswara Oil Mills, 9A, Pedariamman Koil Street, Tirukoilur, South Arcot District.	01-06-88
14.	M/s. T.S.R. Nursing Home, 127, Thiru-vi-ka Road, Villupuram South Arcot District.	01-04-88

1	2	3	क्र.सं.	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
15.	M/s. Devi Kripa Engineering Works, Plot No. 1, Kumaramargalam Industrial Estate, Mathur, Trichy-District, Tamil Nadu.	01-04-88	11.	मै. पद्माजा एप्लिक इन्डस्ट्री, 3-1-299, नीम्बोली घाट्टा, हैदराबाद-77	22-11-1976
			12.	मै. रेस्मू इरम (प्रा.) लि. 3-4-802, बर्कतपुरा, हैदराबाद-27	01-10-1986
			13.	मै. हैदराबाद ओप्टिकल इन्डस्ट्रीज, 4-1-869 मूगा विलेज, निरफ रोड, हैदराबाद।	01-01-1985
			14.	मै. जय एजेंसिज (डेक्कन) 53378/10 चप्पल रोड, हैदराबाद।	01-06-1984
			15.	मै. एटनय जनरल इन्डस्ट्रीज 371105, इयाभिया बाजार, हैदराबाद।	01-10-1983
			18.	मै. मैक्समलर अवन, रामकोट, हैदराबाद।	01-01-1987
			17.	मै. प्रियदर्शनी लिजिंग एण्ड फाइनेंस लि., श्रीनगर कालोनी, हैदराबाद-500073.	01-04-1987
			18.	मै. ए. पी. टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड, चौथी मंजिल, बी ब्लॉक, गोवर्धनमेंट आफिशियल कम्प्लेक्स, प्रटेक्शन रोड, हैदराबाद-500029.	01-08-1988
			19.	मै. एम्. सी पिकनिक कोटेज, मायर गांव, दिसंबर, 1984 गार्डपेट, हैदराबाद।	
			20.	मै. भद्रवल्लभ पब्लिक स्कूल, सारापाका, भद्रवल्लभ, जिला-खानम	1-1-83
			21.	मै. बैकटेरावरा बस सर्विस, हनासकोंडा, बारंगल.	1-5-85
			22.	मै. इस्टीम्यू ऑफ वार्टर्ड फार्मिगियल एनालिसिस ऑफ इंडिया, रोड नं. 3 बंजारा हिस्सा, हैदराबाद-500037	1-4-87
			23.	मै. पोला एजेंसिज, गुन्टाकम, अन्तर्पुर जिला (ए. पी.)	[30-5-88
			24.	मै. लेजर डॉट (प्रा.) लिमिटेड, 3-4-480/3, मामन: रेड्डी यूनिवर्स कोलेज, नारायणगुडा, हैदराबाद, और इसकी शाखा: मै. लेजर डॉट (प्रा.) लि., 114, एवेन्यू रोड, बंगलौर.	1-12-86
			25.	मै. सुसरन ऑप्टोकम इंडस्ट्रीज, 4-1-838, पहली मंजिल, आबिद रोड, हैदराबाद (ए. पी.).	1-1-85
			अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 को अनुधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं को उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के नामने दर्जगी गयी हैं।		
			[संख्या : सी. पी. एफ. गी./1(4)/आंध्र प्रदेश/(87)/89]		

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section I of the said Act, The Central Provident Fund Commissioner hereby applies the Provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the dates mentioned against the name of each of the said establishments.

[No. CPFC/1(4)/TN(36)/89]

कॉ. अ. 698.-केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियंत्रण तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हो गए है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण अनुदान अधिनियम, 1952 (1952 का 14) के उपबन्ध निम्नलिखित स्थापनाओं पर लागू किए जाएंगे।

क्र.सं.	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
01.	मै. श्री सर्वशायी शास्त्रम इन्स्टीट्यूट को आप. क्रेडिट सोसायटी लि. चम्पुलू र्ट. जी। जिला 533261	01-10-1988
02.	मै. नायमनोक्तम एण्ड कम्पनी ती एण्ड एफ एजेंसिज फोर निव्जन इन्डिया लिमिटेड, गुंटु।	30-07-1988
03.	मै. मास्टर रबर प्रोडक्शन, 106, इन्डस्ट्रियल एस्टेट, फाटेटन, हैदराबाद-500252	01-04-1985
04.	मै. कमल राजिग, प्लॉट नं. 12, रोड नं. 8, फाटेटन, हैदराबाद-500252	01-03-1985
05.	मै. प्रीतिवर्मा रोड ड्रासम, कुशाईगुडा, हैदराबाद।	01-05-1987
06.	मै. बी. बी. सी. फेरो अलायज लिमिटेड, रुताराम बिजेज संग रेड्डी लुका मेडक जि. तथा इसका पंजीकृत कार्यालय बी. बी. सी. फेरो अलायज लि. 8-3-1047 श्रीनगर कालोनी हैदराबाद-500073	01-01-1988
07.	मै. काकाटीया सी भेस्ट सपन पाइप कम्पनी, अरेपल्ली (पाय्प) बारंगल जिला।	01-03-1986
08.	मै. लिंक एडवर्टाइजिंग सर्विस, डी. नं. 5-2-13, एन. एम. रोड, हैदराबाद-1	01-06-1982
09.	मै. लक्ष्मी फाइनन्स एण्ड इन्व्स्टीगेशन कार्पोरेशन लि., प्लॉट नं. 42, रोड नं. 2, अर्ह. डी. ए. बाला नगर, हैदराबाद-37 और कार्यालय वेगमपेट, हैदराबाद-66 में स्थित।	01-01-1989
10.	मै. नायकी इंस्टीट्यूट एण्ड डिमेंटरिंग (प्रा.) लि., डॉ. नं. 4-2-432, कांछीगुडा, अरा रोड, हैदराबाद-27	01-08-1983

S.O. 698 -Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishments namely :—

Sl.No.	Name & Address of the establishments	Date of coverage
1.	M/s. Sri Sarvaraya Sugars Employees Co-op. Credit Society Ltd. Chelluru E. G. Dist.—533261.	1-10-1988
2.	M/s. Nagamanjyam & Company C & F Agents for Lipton India Ltd, Gooty.	30-6-1988
3.	M/s. Master Rubber Products, 106, Industrial Estate, Kateelan, Hyderabad-500 252	1-4-1985
4.	M/s. Kamal Sizing, Plot No. 12, Road No. 8, Katturam, Hyderabad-500252.	1-3-1985
5.	M/s. Universal Rock Drills, Kushaiguda, Hyderabad.	1-5-1987
6.	M/s. V.B.C. Ferro Alloys Ltd. Rudraram Village, Sanga Reddy Taluk Medak Dist. including Regd. Office at V.B.C. Ferro Alloy Ltd. 8-3-1047, Srinagar Colony, Hyderabad-500873 (A.P.)	1-1-1988
7.	M/s. Kakateya Cement Spun Pipe Co. Arepally (Post) Warangal District.	1-3-1986
8.	M/s. Link Advertising Service, D.No.5-2-13 N.S. Road, Hyderabad-1.	1-6-1982
9.	M/s. Lakshmi Finance and Industrial Corporation Ltd., Plot No.42, Road No.2, IDA Balanagar, Hyderabad-37 and office at Begumpet, Hyderabad-16	1-1-88
10.	M/s. Gayatri Hotels & Theatres (Pvt.) Ltd, Do. No. 4-2-432, Kachiguda Cross Road, Hyderabad-27	1-8-83
11.	M/s. Padmaja Plastic Industry 3-1-299, Nimboli Adda, Hyderabad-27	22-11-86
12.	M/s. Rescue Drugs(P) Ltd., 3-4-802, Barkatpura, Hyderabad-27	1-10-86
13.	M/s. Hyderabad Optical Industries, 4-1-869, Moosa Building, Tilak Road, Hyderabad.	1-1-85
14.	M/s. Jai Agencies (Deccan) 5-8-328/10, Chappal Road, Hyderabad.	1-6-84
15.	M/s. Atlas General Industries, 4-7-1105, Isamia Bazar, Hyderabad.	1-10-83
16.	M/s. Max Mueller Bhavan, Ramkote, Hyderabad.	1-1-87
17.	M/s. Priyadarshini Leasing and Finance Ltd., Srinagar Colony, Hyderabad-500 873	1-4 87

S.No.	Name & Address of the Establishments	Date of Coverage
18.	M/s. A.P. Technology Services Limited, 4th Floor, B Block, Govt. Offices Complex, Tankbund Road, Hyderabad-500029.	1-8-88
19.	M/s. Blue Sea Picnic Cottage, Sagar Village, Gandhipet, Hyderabad.	12-1984
20.	M/s. Bhadrachalam Public School, Saragaka, Bhadrachalam, Khannam, Dist.	1-1-83
21.	M/s. Venkateswara Bus Service, Hanamkonda, Warangal.	1-5-1985
22.	M/s. Institute of Chartered Financial Analysts of India, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad-500037.	1-4-1987
23.	M/s. Pola Agencies, Guntakal, Anantapur District (A.P.)	30-6-198 8
24.	M/s. Laser Dot (P) Ltd. 3-4-480/3 opp: Reddy Womens College, Narayanguda, Hyderabad. including its branch at M/s. Laser Dot(P) Ltd., 114, Avenue Road, Bangalore.	1-12-1986
25.	M/s. Nusrat Optical Industries, 4-1-838, 1st Floor, Abid Road, Hyderabad (A.P.)	1-1-1985

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Provident Fund Commissioner hereby applies the Provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the dates mentioned against the name of each of the said establishments.

[No.CPFC/1 (4)/AP(37)89]

का. आ. 699--केन्द्राय प्रविध्य निधि आगुक्त को जहा यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोजना तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हो गई है कि कर्मचारी प्रविध्य निधि और प्रकरण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध निम्नलिखित स्थापनाओं पर लागू किए जायें।

क्र.सं.	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति का तिथि
1.	मै. मैक मिशन कॉम्प्यूटर्स लिमिटेड, 7A, इंटरस्ट्रियल एरिया, कोरामंगला, बंगलौर-560034.	1-1-89
2.	मै. सी पी. एस. एस. के. कौन्सिलर्स डेवलपमेंट एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, पांडवपुर, रेलवे स्टेशन, मण्ड्या जिला.	31-10-86
3.	मै. कर्नाटक टेलीकॉम लि., बी आई. टी. गी. बिल्डिंग, कम्प्लेक्स रोड, बंगलौर-1,	1-9-87
4.	मै. सुरेश प्राक्विस, न 6, टेम्पल रोड, मालेश्वरम्, बंगलौर-560003.	29-2-88
5.	मै. गिन्कम्प इन्टरप्राइजिज, न. 127, नागवर्गपाल्या, ब्रिन्ड मट्टाम रोड, बंगलौर-560016.	1-8-86

क्र.सं.	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि	S.No. Name & Address of the Estt.	Date of Coverage
6.	मै. एम. एम. एस. सिस्टीमिक्स लिमिटेड, 97/ए, सन्थेपेट्स, मैसूर-570024.	1-1-88	07. M/s. S.M.S. Security Systems, 97/A. Santhepets, MSYORE-570024.	30-11-87
7.	मै. एन. एम. एस. सिस्टीमिक्स लिमिटेड, 30/1, जे. सी. रोड, बंगलौर-560002.	1-1-88	08. M/s. Generals New Trade Agency, 30/1, J.C. Road, Bangalore-560 002	1-4-1988
8.	मै. बंगलौर जो. पी. ओ. डिपार्टमेंटल कैंटीन, राजभवन रोड, बंगलौर-560001.	1-5-88	09. M/s. Bangalore GPO Departmental Canteen, Rajabhavan Road, Bangalore-560 001.	1-5-1988
10.	मै. स्फेक्ट्रम, बी. 193, पीन्या इंडस्ट्रियल इस्टेट, II स्टेज, बंगलौर-560058.	31-3-88	10. M/s. SPECTRUM, B-193, Peenya Industrial Estate, II stage, Bangalore-560 058.	31-3-1988
11.	मै. कन्नडाडुम्मा डेली, 2003, गनपथ स्ट्रीट, बेलगांव.	1-11-86	11. M/s. Kannadamma Daily, 2003, Ganapath Street, Belgaum.	1-11-1986
12.	मै. यूनिवर्सल स्पेशल अब्रेसिव्स, बी.-335, पीन्या इंडस्ट्रियल इस्टेट, बंगलौर-560058.	1-12-87	12. M/s. Universal Special Abrasives, B-335, Peenya Industrial Estate, BANGALORE-560 058.	1-12-1987
13.	मै. राधा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, प्रशासन कार्यालय 3201 पर, एच. ए. एल.-II स्टेज, इंदिरा नगर, बंगलौर-38.	1-4-88	13. M/s. Radha Engineering Industries, Admn. Office 3201, HAL 2nd stage Indiranagar, Bangalore-38	1-4-1988

अतः केन्द्रीय भविष्य तिथि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रबत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं को उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाये गये हैं।

[संख्या सी. पी. एफ. सी./1(4)/कर्नाटका/(38)/89]

[No : CPFC/1(4)/Karnataka/(38)/89]

S. O. 699--Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishments namely :

का. धा. 700.—केन्द्रीय भविष्य तिथि आयुक्त को जहाँ यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं में संबंधित नियोजक तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात में सहमत हो गए है कि कर्मचारी भविष्य तिथि और प्रतीक उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध निम्नलिखित स्थापनाओं पर लागू किए जायें।

S.No.	Name & address of the Estt.	Date of Coverage
01.	M/s. Mac Millan Computers Ltd., 78, Industrial Area, Koramangala, Bangalore 560 034.	1-1-1988
02.	M/s. The P.S.S.K. cane growers development and welfare Trust, Pandavpura Railway station, Mandya district.	31-10-1986
03.	M/s. Karnataka Telecom Ltd., VITC Building, Kasturba Road, Bangalore-1.	1-09-1987
04.	M/s. Suresh Graphics, No.6, Temple Road, Malleshwaram, Bangalore 560 003.	29-02-1988
05.	M/s. Syscomp Enterprises, No.172, Nagavarapalya, Old Madras Road, Bangalore-560 016.	1-8-1986
06.	M/s. Sri Krishna Engineering Co., 41/43, Lavelle Road, Bangalore-1	1-1-1988

क्र.सं.	स्थापनाओं का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	मै. ज्योदा लैबर एंजिनिंग, 28, बी. बी. कोहल स्ट्रीट, पेरीयामेट, मद्रास-3.	1-5-87
2	मै. श्रीनिवास, कैफे, 48, जी. एस. टी रोड, गुयीडी मद्रास-600032.	1-2-88
3	मै. रूपा शक्ती इण्डस्ट्रीज, सी./3, इण्डस्ट्रियल इस्टेट, गुयीडी मद्रास-32.	1-2-88
4	मै. कोवाटे इंटरनेशनल, 60, विष्णु चेंडी स्ट्रीट, मद्रास-600001.	1-2-88
5	मै. कोरी एल्कोट लि., प्लाट नं. 343, 12वीं पूर्वी स्ट्रीट, कामराज नगर, श्रीवास्तपुर, मद्रास-41.	1-9-87
6	मै. दो मुल्लू आदी ब्राह्मदाम "लेडीज पोलिशिंग वर्कर्स" इण्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव, सोसायटी लि., आर्च. एन. डी. नं. 1568, 231-थी, त्रिवी रोड, सूतूर-641102.	1-7-87

क्रम सं. स्थापनाओं का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
7. मै. दी तलूस इन्टरप्राइजिज बी.-23, थाली हुडको, होसुर-635109.	1-8-87
8. मै. धर्मपुरी डिस्ट्रीक्ट, पोलीथिन वर्कर्स इण्डस्ट्रीयल को-ऑपरेटिव सोसाईटी लि. एल. 3, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, धर्मपुरी-636706.	1-3-87
9. मै. एल. मारीअप्पा नादर, कम्फोर मर्चेन्ट, 74, बिग सौराष्ट्र स्ट्रीट, त्रिचुरापल्ली- 620008.	1-1-86
10. मै. जैड. ए. 72, थपालामपुलियोर एग्रीकल्चरल सर्विस को-ऑपरेटिव सोसाईटी लि., थपालामपुलियोर, तिरुवरूर तालुक तंजौर जिला	1-12-87
11. मै. आर्ट्स पैक, 17, स्मिथ रोड, मद्रास-2.	1-4-87
12. मै. सस्था कॉन्स्ट्रक्टर्स, 44, पहली स्ट्रीट, जीवा नगर, मद्रास-600081.	1-11-87
13. मै. फीडेलिटी लीजिंग प्रा. लिमिटेड, 42, व्हाइट्स रोड, मद्रास-14. तथा इसका कार्यालय 20, सेंटोफ लेन, मद्रास-18 में स्थित.	1-8-87
14. मै. आई. ई. आई. मैनशल सर्विसिज प्रा. लि. 8, मशीलामनी रोड, वालाजी नगर, रायपथ हार्डरोड, मद्रास-14.	1-6-87
15. मै. बायो-नाइस इक्विपमेंट (प्रा.) लिमिटेड, 116, राधाकृष्णन रोड, मद्रास-4, तथा इसकी शाखाएं (1) सेंट. माइकल भवन, लेडी जमशेदजी रोड, महीम, बम्बई-16. (2) 17, जे.एन.जी. हाऊस, पहली मंजिल, टैगोर मार्केट, नजफगढ़ रोड, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015. (3) 230, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कलकत्ता-20. में स्थित.	1-9-87
16. मै. डाल्टन लैबोरीज (प्रा.) लिमिटेड, 299, सिडको इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, मद्रास-98. तथा इसका कार्यालय : नं., 14, लैटिस ब्रिज रोड, आदयार, मद्रास-20 में स्थित.	1-7-87
17. मै. बीशीप डिवेल रिहैबिलिटेशन होम फोर दी ब्लाईंड, ट्रंक्यूबार हाऊस कम्पाऊंड, त्रिची-1.	1-9-87
18. मै. ग्लैक्सी लैडर एक्सपोर्ट्स, नं. 2, कोठानडम स्ट्रीट, ई.एस.आई. डिस्पेंसरी के सामने, मद्रास-44.	1-11-87

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त

स्थापनाओं को उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

[संख्या : के. भ. नि.आ./1(4) टी.एन./ (39)/89]

S. O. 700 -Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishments namely :-

S.No.	Name & Address of the Establishment	Date of Coverage
1.	M/s. Zubida Leather Agencies, 28, V.V. Koli Street, Perimatt, Madras-3.	1-5-87
2.	M/s. Srinivasa Cafe, 46, G.S.T. Road, Guindy, Madras-600 032	1-2-88
3.	M/s. Rupa Sakthi Industries, C/3, Industrial Estate, Guindy, Madras-32	1-2-88
4.	M/s. Coyate International, 60, Linghi Chetty Street, Madras-600 001.	1-2-88
5.	M/s. Kody Elcot Ltd., Plot No. 343, 12th East Street, Kamaraj Nagar, Thiruvannamiyur, Madras-41.	1-9-87
6.	M/s. The Sular Adi-Dravidas' Ladies Polythene Workers' Industrial Co-operative Society Ltd., INB No.1568, 231-B, Trichy Road, Sular-641 402	1-7-87
7.	M/s. The Tellus Enterprises, B-23, Thrilly Hudco, Hosur-635109	1-8-87
8.	M/s. Dharmapuri District Polythene Workers Industrial Co-operative Society Ltd., L-3, Industrial Estate, Dharamapur-636705	1-3-87
9.	M/s. L. Mariappa Nadar, Camphor Merchant, 74, Big Sowasthra Street, Tiruchirappalli-620008	1-1-88
10.	M/s. Z.A. 72. Thappalampuliyur Agricultural Service Co-operative Society Ltd., Thappalampuliyur, Tiruvarur Taluk Tanjore Dt.	1-12-87
11.	M/s. Arts Pack, 17, Smith Road, Madras-2	1-4-87
12.	M/s. Sashta Contractors, 44, 1st Street, Jeeva Nagar, Madras-600081	1-11-87
13.	M/s. Fidelity Leasing P. Ltd., 42, Whites Road, Madras-14 including its Regd. Office at, 20, Centopy Lane, Madras-18.	1-8-87
14.	M/s. IEI Mansel Services Pvt. Ltd. 8, Masilamani Road, Balaji Nagar, Royapettah High Road, Madras-14	1-6-87
15.	M/s. Bio-Nice Equipment(P) Ltd., 116, Radhakrishnan Road, Madras-4 including its branches at (1) St. Michael Bhavan, Lady Jamshedji Road, Mahim, Bombay-16. (2) 17, JNG, House, 1st Floor, Tagore Market, Najafgarh Road, Kirthi Nagar, New Delhi Pin : 110 015 (3) 230, Acharya Jagdish Chandra Bose Road, Calcutta-20	1-9-87

Sl.No.	Name & Address of the establishment	Date of coverage
16.	M/s. Dalton Laboratories(P) Ltd., 299, SIDCO, Industrial Estate, Madras 98 including its Office at No.14, Lattice B Nagar, Road, Adayar, Madras-20	1-7-87
17.	M/s. Bishop Dichter Rehabilitation Home for the Blind, Tranquebar House Compound, Trichy-1.	1-9-87
18.	M/s. Galaxy Leather Exports, No.2 Kothandam Street, Opp. E.S.I. Dispensary, Madras-44	1-11-87

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section I of the said Act, The Central Provident Fund Commissioner hereby applies the Provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the dates mentioned against the name of each of the said establishments.

[No. CPFC/1(4)/TN(39)/89]

का.आ. 701.—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हो गए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध निम्नलिखित स्थापनाओं पर लागू किए जाएंगे।

क्र.सं.	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	मै. दी उड़ीसा स्टेट इन्वैस्ट्मन्ट्स लि., डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., 289, साहिद नगर, भुवनेश्वर-751007	1-7-84
2	मै. ओ. एम. सी. ब्रालायम लि., बामनीपाल जि. केन्डोर (उड़ीसा) प्रधान कार्यालय : दूसरी मंजिल ओ. एम. सी. बिल्डिंग, भुवनेश्वर, जि. पुरी (उड़ीसा) तथा उसकी फैक्ट्री बामनीपाल, जि. केन्डोर (उड़ीसा) में स्थित	1-12-86
3	मै. तोलाचल ईस्टान निगम लि., आई. पी. आई. सी. ओ. एल हाऊस (चौथी मंजिल) भुवनेश्वर-751007. तथा उसकी फैक्ट्री पो. ओ. बूबरी, जि. कटक में स्थित	1-1-84

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं को उस या उसमें प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करने है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

[सं. : के.भ.नि.आ./1(4) उड़ीसा/40/89]

S.O. 701.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds

and Miscellaneous Provisions Act, (1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishments namely :—

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Date of coverage
1.	M/s. The Orissa State Electronics Development Corporation Ltd., 289, Sahid Nagar, Bhubaneswar-751007.	1-4-84
2.	M/s. O M C. Alloys Ltd., Bamnibal Distt. Keonjhar (Orissa). H.O. 2nd Floor, OMC Building, Bhubaneswar, Distt. Puri (Orissa) including Factory at Bamnibal, Distt. Keonjhar (Orissa)	1-12-86
3.	M/s. Nalanchal Ispat Nigam Ltd., IPICOL House (4th Floor) Bhubaneswar-751007, including Factory at P.O. Duburi, Distt. Cuttack.	1-4-84

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section I of the said Act, The Central Provident Fund Commissioner hereby applies the Provisions of the said Act to the above mentioned establishment from and with effect from the dates mentioned against the name of each of the said establishments.

[No. CPFC/1(4)/OR(40)/89]

का. आ. 702.—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापना से सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हो गए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध निम्नलिखित स्थापना पर लागू किए जाएंगे।

क्र.सं.	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	मै. संगम सिनेमा, रेलवे स्टेशन रोड, मलपुरा दरवाजा बाहरी, संगरौर, (जयपुर)।	1-1-87

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापना को उस या उसमें प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करने है जो उक्त स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

[संख्या : सी.पी.एफ.सी. 1(4) राजस्थान (41) 89]

S.O. 702.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the Majority of employees in relation to the following establishment has agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment namely :—

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Date of coverage
1.	M/s. Singam Cinema, Railway Station Road, Malpara Darwaja outside, Sanganer, (Jaipur).	1-1-1987

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section I of the said Act, The Central Provident Fund Commissioner hereby applies the Provisions of the said Act to the above mentioned establishment from and with effect from the date mentioned against the name of the said establishments.

[No. CPFC/1(4)/RJ(4)/89]

का. प्रा. 703.—केन्द्रीय भविष्य निधि प्रायुक्त को जहाँ यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापना संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हो गए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध निम्नलिखित स्थापना पर लागू किए जायें।

क्र. सं.	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1. मै. मुग्मा फायरब्रिक्स एण्ड इंसुलेशन वर्क्स, पो. प्रा. मुग्मा, धनबाद.		1-4-87

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि प्रायुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापना को उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

[संख्या : सी.पी.एफ.सी./1(4)/वि.र(42)/११]

S.O.703.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishment has agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishments namely :-

Sl. No.	Name and Address of Establishment	Date of Coverage
1. M/s. Mugma Firebricks and Insulation Works. P.O. Mugma. Dhanbad.		01-4-87

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section I of the said Act. The Central Provident Fund Commissioner hereby applies the Provisions of the said Act to the above mentioned establishment from and with effect from the date mentioned against the name of the said establishment.

[No. CPFC/1(4)/BR(42)89]

का. प्रा. 704.—केन्द्रीय भविष्य निधि प्रायुक्त को जहाँ तक यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हो गए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध निम्नलिखित स्थापनाओं पर लागू किए जाएँ।

क्र. संख्या	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1. मै. साइंटिफिक कम्पाउण्ड तथा प्रोसेसेस. नं. 9 जी. के. इन्डस्ट्रियल इस्टेट, पोकर इन्क्यूबरी गोडाउन एट इन्क्यूबरी कोर्टाई श्रीपेरमबुदूर, चिगलेपुर जिला।		1-4-87
2. मै. श्री राजेश्वरी अप्पारेस, 106, जी. एन. चेद्वी रोड मद्रास-17		1-11-87
3. मै. जयम कन्स्ट्रक्टर्स, 7 सैमुथम स्ट्रीट, वील्लोबकम, मद्रास-49		1-11-87
4. मै. होटल यावगार, 47, अन्ना सलाई, मद्रास-600002.		1-10-87

क्र. सं.	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
5. मैसर्स रूपम इन्टरनेशनल, एलमरग थिन्डीग, 849, माउन्ट रोड, मद्रास-600002.		1-4-87
6. मैसर्स टेक शार्प इन्वायरी सीस्टमस (प्रा.) लि. पी-39, दूसरी एवेन्यू, अन्ना नगर, मद्रास-40.		1-9-87
7. मैसर्स एम. एन. सैन्थीसीस, नं. 1, जी. के. इन्डस्ट्रियल इस्टेट, पोकर, इन्क्यूबरी गोडाउन एट इन्क्यूबरी कोर्टाई, पेराल्लूर-602105.		1-4-87
8. मैसर्स वि. शालीमार पेपर कम्पनी, रील कटींग एण्ड स्ट्रीपींग नं. 241, टी. एन. रोड, टोन्डीग्रामपेट, मद्रास-600081.		1-10-87
9. मै. न्यू सेन्चुरी लॉजिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, 481, थर्ड फ्लोर, माउन्ट रोड, नन्वनम, मद्रास-35 इन्क्यूबरी ब्रान्च एट नं. 201, सीलवर लेक टैरेस 55, रीचमीण्ड रोड, बंगलोर, फोन : 560025.		1-7-87
10. मै. प्रकाश ट्रेडिंग कम्पनी 46, ग्रामेनियन स्ट्रीट मद्रास-600001.		1-12-87
11. मै. वि. कवायल कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स सोसायटी लिमिटेड। नं. टीन्नाईरी-83, कवायल कम्प्लायस 629101, कन्याकुमारी जिला।		1-1-88
12. मै. ए-1237 कुल्लाकुण्ड एग्रोकल्चरलस सर्विस के.ओ.पी. सोसायटी कुल्लासाकुण्ड नीला क्कोट्टाईटी.के. अन्ना जिला नीला क्कोट्टाईटी.के. अन्ना जिला।		1-10-87
13. मै. बाग्यालवमी एक्सप्रेस एण्ड क्लीनिकल लेबोरेटरी, 24, रामा कृष्ण रोड सलेम-636007		1-9-87
14. मै. यूनिवर्सल क्लेरिंग एण्ड शीपींग एजेंसी, 26 तथा 27, इरुबालु चेद्वी स्ट्रीट मद्रास-600001. इन्क्यूबरी यूनिवर्सल क्लेरिंग एण्ड शीपींग एजेंसी 139, अन्नापा ना इक्कन स्ट्रीट फस्ट फ्लोर, मद्रास-600001.		1-4-88
15. मै. साल्बोस इन्जिनियरिंग (प्रा.) लिमिटेड, 4-ए, फस्ट एवेन्यू इन्दिरा नगर, मद्रास-600020. इन्क्यूबरी 1. 49-49-21, अक्यापलेम विशाखापट्टनम-530017. 2. 35/2493, देवरा रोड, अनाकुलम, कोयिन-681016.		1-4-88
16. मै. निपाली केमिकल्स, 33, इल्या मुबाली स्ट्रीट मद्रास-600021.		1-4-88
17. मै. अरुना स्टील इन्डस्ट्रीज, 30, पेद्दु नायकन स्ट्रीट मद्रास-79.		1-4-88

क्रम. सं.	संस्थान का नाम व पता	स्थापित की तिथि	1	2	3
1	2	3			
18.	मै. महादेवन इन्टरप्राइजेस, 23 तार्थमादा स्ट्रीट, बोलीवकम, मद्रास-49.	1-2-88			
19.	मै. मैसर्स: एन.हिन्डोस्पीटल 183 टी. एच. रोड, मद्रास-600081.	1-6-88			
20.	मै. बोलीवकम क्लोथिंग कम्पनी, बोलीवकम, मद्रास-49.	1-3-88			
21.	मै. स्टार प्रेस नं. 9, अ दवा स्ट्रीट, मद्रास-600050.	1-3-88			
22.	मै. यूकन ड्रवल् प्राइवेट लिमिटेड, 116, स. उन्ट रोड, मद्रास-600002. इन्क्लूडिंग ब्रांच एट यूकन ड्रवल्स प्राइवेट लिमिटेड, 32-बी, प्रीमेन्डे रोड कान्टोन्मेंट, कोचि-620001.	1-10-87			
23.	मै. पी. कांछे मिल्क प्रोड्यूसर्स को-ऑपरेटिव सोसायटी लि., बी. आर. डी. 148 काज्जथन्पीट्टरी, पी. कांछे, इरुक्कीपुरई पोस्ट, के. के. जिला।	1-2-88			
24.	मै. श्रीरक्षतर प्रीमरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, श्रीरक्षतर पोस्ट-629177 कन्याकुमारी जिला। इन्क्लूडिंग डिपो एट 1. श्रीरक्षतर प्राइमरी को-ऑप. बैंक लि. श्रीरक्षतर पोस्ट. 2. श्रीरक्षतर प्राइमरी को-ऑप. बैंक लि. श्रीरक्षतर पोस्ट.	1-2-88			
25.	मैसर्स सीमा मोटरस (प्रा.) लिमिटेड 1-ए, न्यू नाथन रोड, मडुराई-2 इन्क्लूडिंग ब्रांच एट 1. 3, पश्चिम पेरुमल स्ट्रीट मडुराई। 2. 281, गुडशोड स्ट्रीट, मडुराई।	1-7-88			
26.	मैसर्स स्टार्डल फास्टनरस, नं. 670, तिरुवेन्दुर रोड, पन्नाय, मकोट्टाई, विश्वेनवेली-627002.	1-8-85			
27.	मै. पिलयु प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक, (बीआरईजेड) वडामडुराई, वेवासन्दुर, तामुक, अरसा जिला।	1-4-88			
28.	मैसर्स एनोसिपेटेड इन्जीनियरी वर्क्स, 159, मेट्टुपलायम रोड, मध्यपालयम, कोयम्बटूर-19.	1-6-88			
29.	मैसर्स एम. बी. मुश्मलीयन, 109, एम. अट्टायपुरम रोड, टुटोकोरीन-2	1-5-88			
30.	मै. बाई. 58, परापट्टु एग्रीकल्चरल सर्विस को-ऑपरेटिव सोसायटी, परापट्टु मानविलक्करीचि पोस्ट, कन्याकुमारी जिला, इन्क्लूडिंग ब्रांच एट 1. चैरामंगलम डिपॉजिट, परापट्टु एग्रीकल्चरल सर्विस को-ऑप. सोसायटी, मानविलक्करीचि पोस्ट. 2. गोन्दाईकाट्टु डिपॉजिट, परापट्टु एग्रीकल्चरल सर्विस को. अ. प. सोसायटी, गोन्दाईकाट्टु पोस्ट।	1-4-88			
			31.	मै. कोट्टीकोनम हरिजन मिल्क प्रोड्यूसर्स को-ऑपरेटिव सोसायटी, लिमिटेड, बी आर डी-62, कोट्टीकोनम, कुलसेकम्म पोस्ट, कन्याकुमारी जिला। अन: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्था- पनाओं को उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं या उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाये गये हैं। [संख्या के. अ. नि. आयुक्त/1(4)टीएन/(43)/89] S.O. 704.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishment have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment namely :—	1-1-88
			Sl. No.	Name & Address of establishments	Date of coverage
			1	2	3
			1.	M/s. Scientific Compound and Processes, No. 9, G.K. Industrial Estate, Porur including Godown at Irungattu Kottai Sriperumbudur, Chingleput Dt.	1-4-87
			2.	M/s. Sri Rajeswari Apparels, 105, G.N. Chetty Road, Madras-17.	1-11-87
			3.	M/s. Jayam Contract Service, 7, Saimiruzan Street, Villivakkam, Madras-49.	1-11-78
			4.	M/s. Hotel Yalgar, 47, Anna Salai, Madras-600 002.	1-10-87
			5.	M/s. Roopam International, Elsons Building, 849, Mount Road, Madras-600 002.	1-4-87
			6.	M/s. Tech Sharp Enviro Systems (P) Ltd, C-39, 2nd Avenue, Anna Nagar, Madras-40.	1-9-87
			7.	M/s. S.N. Synthesis, No. 1, G.K. Industrial Estate, Porur including godown at Irungattu Kottai, Ponnallur-602105.	1-4-87
			8.	M/s. The Shalimar Paper Co; Reel Cutting & Stripping Dn, No. 241, T.H. Road, Tondiarpet, Madras-600031.	1-10-87
			9.	M/s. New Century Leasing and Investments Limited, 431, 3rd Floor, Mount Road, Naduram, Madras 35 including branch at No. 201, Silver Lake Terrace 55, Richmond Road, Bangalore-560025.	1-7-87
			10.	M/s. Prakash Trading Company, 46, Armenian Street, Madras-600001.	1-12-87
			11.	M/s. The Kadayal Co-operative Milk Producers Society Ltd, No. TYD-83, Kadayal, Kaliyal-629101, Kanyakumari District.	1-01-88

1	2	3	1	2	3
12. M/s. A. 1237 Kullalakundu Agricultural Service Co.-Op. Society, Kullalakundu Nila Kaottai Tlk, Anna District.	1-10-87		25. M/s. Chocema Motors (P) Ltd, 1-A, New Natham Road, Madurai-2, including branches at, 1. 3, West Perumal Street, Madurai. 2. 281, Goodshed Street,		1-7-88
13. M/s. Bagayalakshmi X Rays & Clinical Laboratory, 24 Ramakrishna Road, Salem-636 007.	1-9-87		26 M/s. Style Fastners, No. 670, Tiruchendur Road, Palayamkotai, Tirunelveli-6202.		1-8-85
14. M/s. Universal Clearing and Shipping Agency, 26 & 27, Errabalu Chetty Street, Madras-600 001, including Universal Clearing and Shipping Agency, 139, Angappa Nicken Street, 1 Floor, Madras-600 001.	1-4-88		27. M/s. Pilathu Primary Co. operative Bank (viz.) Vadamadurai, Vedasandur taluk, Anna District.		1-4-88
15. M/s. Salbro's Engineers (P) Ltd. 4-A, 1st Avenue Indira Nagar, Madras-600 020. including 1. 49-49-21. Akkayapalem Vishakapatnam-530017, 2. 35/2493, Thevara Road, Ernakulam, Cochin-682016.	1-4-88		28. M/s. Associated Engineering Works, 159, Mettupalayam Road, Madampalayam, Coimbatore-19.		1-6-88
16. M/s. Sipali Chemicals, 33, Ellaya Mudali Street, Madras-600 021.	1-4-88		29. M/s. M.V. Subramaniam, 109, S. Ettayapuram Road, Tuticorin-2.		1-5-88
17. M/s. Aruna Steel Industries, 30, Peddu Nicken Street, Madras-79.	1-4-88		30. M/s. Y. 58, Parappattu Agricultural Service Co-operative Society Parappattu, Manavalakurichi post, Kanyakumari District, including branches at 1. Cheramangalam Dept, Parappattu Agricultural Service Co. op. Society, Manavalakurichi Post. 2. Mondaikadu Dept. Parappattu Agricultural Mondaikadu Post.		1-4-88
18. M/s. Mahadevan Enterprises, 23, North Mada Street, Villivakkam, Madras-49.	1-2-88		31. M/s. Kottoorkonam Harijan Milk Producers Co. operative Society, Ltd., V.R.D. 62, Kottoorkonam, Kulasekaram Post. Kanyakumari District.		1-1-88
19. M/s. Ezhil Hospital, 183, T.H. Road, Madras-600 081.	1-6-88		Now, therefore in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, The Central Provident Fund Commissioner hereby applies the Provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the dates mentioned against the name of each of the said establishments.		
20. M/s. Villivakkam Clothing Company, Villivakkam, Madras-49.	1-3-88		[No. CPFC/1(4)/TN(43)89]		
21. M/s. Star Apparels, No. 9, Yadava Street, Madras-600 050.	1-3-88		का. आ. 705.—केन्द्रीय भविष्य निधि प्रायुक्त को जहां यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोजन तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हो गए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19)) के उपबन्ध निम्नलिखित स्थापनाओं पर लागू किए जायें।		
22. M/s. Ucal Travels Private Limited, 116, Mount Road, Madras-600002. including branch at Ucal Travels Private Limited, 32B. Promenade Road, Cantonment, Trichy-620001.	1-10-87		क्रम सं. स्थापना का नाम व पता व्यक्ति की निधि		
23. M/s. Pacode Milk Producers Co. operative Society Ltd., V.R.D. 148. Kazhuvanthittari. Pacode, Euzhithurai Post. K.K. District.	1-3-88		01. मै. न्यू डेकोरम, बजुआ बाजार, ठाकर शोपिंग सेंटर के पीछे, बजुआ जि. बडोदा		
24. M/s. Thiruvattar Primary Co-operative Bank Ltd., Thiruvattar. Thiruvattar Post-629177 Kanyakumari District. including Depots 1. Thiruvattar Primary Co. op. Bank Ltd., Thiruvattar Post. 2. Thiruvattar Primary Co.op. Bank Ltd. Thiruvattar Post.	1-5-88		02. मै. महेश्वरी कन्सल्टेशन, ठाकर भीखा भाई मर्द, 86 जी. चाल, बजुआ जि. बडोदा।		
			03. मै. प्रभात भाई बी-मकवाना, एट घनेरा, पी. करवरी, 87 ओ. पेद्रोकेमिकल्स, जि. बडोदा।		

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 4 के उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त स्थापनाओं को उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करने हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

[स. के. भ. नि. आ. (1) (4)/(41)गुज/89]

S.O. 705.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishments namely :—

S. No.	Name & Address of Establishments	Date of coverage
1.	M/s. New Decorum, Bajwa Bazar, Behind Thakkar Shopping Centre, Bajwa, Dist. Baroda.	Oct., 80
2.	M/s. Maheshwari Construction, Thakkar Bhikhabhai D. Chai, Bajwa, Dist. Baroda.	May, 86
3.	M/s. Prabhatbhai B. Makwana, At. Dhanera, P.O. Petrochemicals, Dist. Baroda.	February, 87

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, The Central Provident Fund Commissioner hereby applies the Provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

[No. CPFC/1(4)/GJ(44)/89]

का. आ. 706—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापना में सम्बन्धित नियोजन तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हो गए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध निम्नलिखित स्थापना पर लागू किए जायें।

क्रमसं.	स्थापना का नाम व पता	प्रभाविता का तिथि
01.	मै सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी, 47/7, सफेद कालोनी, जुही, कानपुर।	01.03.1986

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त स्थापना को उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करने हैं जो उक्त स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है।

[सं. के. भ. नि. आ. (1) (4) उ० प्र० (45)/89]

एस. पी. मेहरोत्रा, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

S. No.	Name & Address of the establishment	Date of coverage
1.	M/s. Security Service Agency, 47/7, Safed Colony, Juhi, Kanpur.	1-3-86

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Provident Fund Commissioner hereby applies the provisions of the Act to the above mentioned establishment from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishment.

[CPFC/1(4)/UP(45)/89]

S. P. MEHROTRA, Central Provident Fund Commissioner

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1989

का० आ० 707—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (व्यापार) नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैमर्स डा० रमन सी० अमीन (कार्गो सुपरिण्डेंटेन्स एण्ड सर्वेयर्स) 43-22-3 आइसक रोड, टी० एन० कोलोनी, विशाखापत्तनम-530016, को यहाँ उसमें उपबन्ध अनुसूची में निर्दिष्ट मैगनीज तथा अयस्क ग्रुप-1 का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन अभिकरण के रूप में मान्यता देती है और अभिकरण मैगनीज तथा अयस्क ग्रुप-1 के निर्यात (निरीक्षण) नियम 1965 के नियम 4 के उप-नियम (4) के अन्तर्गत निर्यात निरीक्षण परिषद/अभिकरण द्वारा अपनाई गई निरीक्षण प्रणाली की जांच करने के लिए इस संबंध में विशाखापत्तनम में तामित किसी भी अधिकारी को निरीक्षण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देगा।

अनुसूची

खानेज तथा अयस्क ग्रुप-1

1. मैगनीज अयस्क-मैगनीज डायक्साइड रहित।
2. कच्चा लोहा।
3. पीरोमैगनीज स्लेज सहित, फीरोमैगनीज।
4. कैल्सिड बाक्साइट सहित, बोक्साइट।

[फाइल नं० 5 (14)/89-ई० आई० एण्ड ई० पी०]

ए० के० चौधरी, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 15th April, 1989

S.O. 707.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a period of one year from the date of publication of this notification M/s. Dr. Raman C. Amin (Cargo Superintendents and Surveyors) 43-22-3, Isaac Road, T.S.N. Colony, Visakhapatnam—530016 as an agency for the inspection of the Minerals and Orce-Group-I specified in schedule annexed hereto prior to export at Visakhapatnam subject to the condition that the said agency shall give adequate facilities to any officer nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by the said agency in granting the certificate of inspection under sub-rule (4) of rule 4 of the Export of Minerals and Orce-Group-I (Inspection) Rules, 1965.

S.O. 706.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishment have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishments namely :—

SCHEDULE

Minerals and Ores-Group-I

1. Manganese Ore.—excluding manganese dioxide.
2. Iron Ore.
3. Ferromanganese including ferromanganese slag.
4. Bauxite, including calcined bauxite.

[File No. 5(14)/88-EI&EP]

A. K. CHAUDHURI, Director

(पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1989

का.आ. 708:—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 8(4) के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहस्र रत्न अधिसूचित करते हैं कि पूर्ति विभाग के सचिवालय में सम्बन्धित अनुभाग दिनांक 1 मार्च, 1989 से अपना अन्तर्गत कार्य हिन्दी में करेंगे।

[सं. ई.-11017/3/88 प्रकोपन]

एच. बल सुब्रमणियन, अवर सचिव

(Department of Supply)

New Delhi, 28th February, 1989

S.O. 708.—In pursuance of Rule 8(4) of Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the President is pleased to notify that the General Section in the Secretariat of Department of Supply, New Delhi, will do 100 per cent of its work in Hindi with effect from 1st March, 1989.

[No. E- 11017/3/88-Admn.]

S. BALASUBRAMANIAN, Under Secy.

अधिसूचना सं 16/9/88-एम -III का अनुलग्नक

क्रम सं उपक्रम का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण संख्या

1. मैमंग जय इलेक्ट्रिक सेक्टर भवन, न 2 1123/75
वायर कार्पोरेशन लि० 5 वीं मंजिल, न्यू

मैरिन लाइन बम्बई-

400020

2. मैमंस आइ० एं० पी० एल० यथोपरि 1163/75
इन्डस्ट्रीज लि०

3. मैमंस इन्फिन कन्स- यथोपरि 1166/75
लटेन्ड्स प्रा० लि०

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 23rd February, 1989

S.O. 709.—In pursuance of Sub-section (3) of section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of the undertakings mentioned in the Annexure to this notification, the said undertakings being undertakings to which the provisions of Part A Chapter III of the said Act no longer apply.

[No. 16/9/89-M. III]

S. B. SINGH, Dy. Secy.

Annexure to the Notification No. 16/9/89-M.III.

Sl. No.	Name of the Undertaking	Regd. Office	Registration No.
1.	M/s. Jay Electric Wire Corporation Limited.	Maker Bhawan No. 2, 5th floor, New Marine Lines, Bombay-400 020.	1123/75
2.	M/s. ISPL Industries Ltd.	-do-	1163/75.
3.	M/s. Infin Consultants Pvt. Limited.	-do	1166/75.

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1989

का० आ० 710—विकास परिषद् (प्रक्रिया नियम), 1952 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग के (का० आ० सं० 674 (अ) आदेश सं 13-24/87-सीमेंट दिनांक 6 जुलाई, 1987 में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त आदेश के क्रम सं० 6 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी :-

6. श्री सागर जैन, अध्यक्ष,
मैमंस लक्ष्मी सीमेंट्स,

[सं० 13-24/87-सीमेंट]

आ० एन० बोंहिसार, निदेशक

उद्योग मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1989

का.आ. 709:—एक अधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना के अनुलग्नक में उल्लिखित उपक्रमों के पंजीकरण के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है, क्योंकि उक्त उपक्रम ऐसे उपक्रमों में से हैं जिनपर उक्त अधिनियम के अध्याय-3 के भाग क अध्याय के उपबन्ध अमल नहीं होते हैं।

[सं. 16/9/89-एम.-III]

एच. बी. सिंह, उप सचिव

(Department of Industrial Development)

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 27th February, 1989

New Delhi, the 6th March, 1989

S.O. 710.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with the rules 2, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural Rules) 1952, and in partial modification of Order No. 13-24/87-Cem. dated 6th July, 1987 of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development S.O. No. 674(E), the existing entry at Sl. No. 6 of the said Order shall be substituted as under:—

6. Shri Sagar Jain, President,
M/s. Laxmi Cement.

[No. 13-24/87-Cem.]

R. N. BOHIDAR, Director

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संभालय

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1989

का० प्रा० 711—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संभालय की अधिसूचना का० प्रा० सं० 3358 तारीख 26-10-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और, आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करते के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

गंधार से धुवारन तक पाइन लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : जंबुसर

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
मगनाव	874	0	06	84

[सं. प्रो. 11027/171/88-प्रो०एन०जी०जी०-III]

के० विवेकानन्द, डेस्क अधिकारी

S.O. 711.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3358 dated 26-10-88 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And, whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM GANDHAR TO DHUVARAN

State : Gujarat Dist : Bharuch Taluka : Jambusar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Magnad	874	0	06	84

[No. O-11027/171/88-ONG-D.III]

K.K. VIVEKANAND, Desk Officer

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1989

का., प्रा. 712—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईप लाईन गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और, यतः, यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बतते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आशेष सक्षम प्राधिकारी गैस, अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, एच. बी. जे. पाईप लाइन उमरी हाउस, हाट रोड, गुना (म. प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुतवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम का नाम :- भुइयो :- डी आलम तहसील बड़नगर जिला :- उज्जैन राज्य मध्य प्रदेश

अनुसूची

अनु. क्र. खमरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र हेक्टर में
1. 95/4	0.069
105/1	
106/3	
कुल क्षेत्रफल	0.069

[सं. ओ. 14016/139/84 जी पी]

New Delhi, the 7th March, 1989

S.O. 712.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Barcilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of pipeline under the land to the Competent Authority, Oil Gas Authority of India Limited, HBJ Gas Pipeline Umri House, Haat Road, Guna (M.P.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPELINE PROJECT

Village Mahudi Alam : Tehsil Badnagar : Dist. : Ujjain, M.P.
(SCHEDULE)

Sl. Survey No. No.	Area to be acquired for ROU in Hectare
1. 95/4	
105/1	0.069
106/3	
Total Area	0.069

[No. O. 14016/139/84/G.P.]

का. शा. 713-यस : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में इजीरा से बरेली में जाईपुर (पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईप लाईन गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और, यह : यह प्रतीत होता है कि ऐसी बातों को विधान के प्रयोजन के लिए एतद्भावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जन करना आवश्यक है।

यस : अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जन करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बतर्क कि उक्त भूमि में हिस्सबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप करने में अधिकारी, गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, एच बी जे पाइप उमरी हाउस, हाट रोड, गुना (मं प्र०) को इस अधिसूचना की मारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुतवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच० बी० जे० गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम का नाम :- जमोदी महमूल : महुदपुर जिला :- उज्जैन राज्य : मध्य प्रदेश

(अनुसूची)

क्र० सं० सर्वे नं०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टर में
--------------------	--

1. 1378/1	0.082
1382/1	

योग : 2 0.082

[सं० ओ० 14016/387/84/जी पी]

S.O. 713.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of pipeline under the land to the Competent Authority, Oil Gas Authority of India Limited, HBJ Gas Pipeline Umri House, Haat Road, Guna (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPELINE PROJECT

अनुसूची

Village : Jagoti Tehsil : Mahidpur Distt. : Ujjain (U.P.)
SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for ROU in Hectare
1.	1378/1 1382/1	0.082
Total-2		0.082

[No.O. 14016/387/84-GP]

का० प्रा० 714.—यतः, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजिरा से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पार्श्व लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण मर्यादित लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और, यतः, यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्प्राप्त अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब, पेट्रोलियम और खनिज पार्श्व लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

अतः कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पार्श्व लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण मर्यादित उमरी हाउस, हाट रोड, गुना (म० प्र०) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच० बी० जे० गैस पार्श्व लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम-छिरवाहा तेहसील-पिछोरे जिला-शिपुरी म० प्र०

क्रमांक	खसरा नम्बर	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हे० में)
1.	556	0.084
योग-1		0.084

[गं० ओ० 14016/347/85/जी० पी०]

S.O. 714.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira to Jagdishpur in Madhya Pradesh State a pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 43 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of pipeline under the Jaid to the Competent Authority, Oil Gas Authority of India Limited, HBJ Gas Pipeline Umri House, Haat Road, Guna (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

H.B.J. Gas Pipeline Project

Village : Chirwaha Tehsil : Pichhore Distt : Shiwपुरी M.P.
SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hectares
1.	556	0.084
Total-1		0.084

[No. O.14016/347/85/GP]

का० प्रा० 715.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पार्श्व लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 उपधारा (1) के अर्धेन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का० प्रा० सं० तारीख 3301/5-11-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पार्श्व लाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अर्धेन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और, आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पार्श्व लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे, उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बावजूद भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख की निहित होगी।

अनुसूचक याद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

जिल्हा	तहसील	पारगना	ग्राम	प्लॉट नं.	क्षेत्रफल बीघा में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
बदायूं	गुनौर	राजपुरा	कृतिवा	261	0-7-0	
				262	0-5-10	
				264	0-12-0	
				248	0-0-10	
				249	0-2-0	
				258	0-0-10	
				6	1-7-10	

[सं. प्रो. 14016/478/84 जी. पी.]

S.O. 715.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. No. 3301 dated 5-11-88 under sub-section (1) of Section of the Petroleum and Natural Gas and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1950), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquire for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H B J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Bighas	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Badaun	Gunaur	Rajpura	Kritia	261	0-7-0	
				262	0-5-10	
				264	0-12-0	
				248	0-0-10	
				249	0-2-0	
				258	0-0-10	
				6	1-7-10	

[No. O. 14016/478/84-GP]

का. प्रो. 716—यह: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजौरा विजयपुर से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यह: प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आणव्य एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. विकासवीथ लगानक-- 226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति निर्निश्चितता यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूचक बांध अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

जन्मपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
रायबरेली	महाराजगंज	सेमराता	समसपुर हलोर	1506	0-5-0	

[सं. प्रो.-14016/163/84-जी. पी.]

S.O. 716.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hazira to Jagdishpur in Uttar Pradesh State, a pipeline should be laid down by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act,

1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may with 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the laid to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd., H.B.J. Pipeline Project Vikas Deep Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipeline Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Rae Bareli	Maharajganj	Semrauta	Samaspur Halor	1506	0-5-0	

[No. O-14016/163/84-G.P.]

का. प्रो. 717.—यतः पेट्रोलियम और गैस पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का. प्रो. सं. 3289 तारीख 5-11-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उन अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार कल पाईप लाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारों ने उक्त अधिनियम की धारा 6 का उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों से में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में समो बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूचक बांध अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

जन्मपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बदायूं	गतीर	भसदपुर	सुल्तान गढ़	908	0-1-0	

[सं. प्रो.-14016/462/85 जी पी]

S.O. 717.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3299 dated 15-11-88 under sub-section (1) of the Petroleum and Natural Gas and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)
H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Bigha	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Badaun	Gunaur	Asadpur	Sultangadh	908	0-1-0	

[No. O-14016/462/85-G.P.]

का. मा. 718—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रजेंट) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 उपधारा (1) के अर्वात् भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का. मा. स. गारोख 3300/5-11-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईप लाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः महान् प्राधिकारी अ उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अर्वात् सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के अन्तर्गत भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को होगा।

अनुसूची बाद अनुसूची
एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाट सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बदायूँ	गुनौर	असदपुर	मालपुर	31	0-1-0	
				30	0-1-0	
				26	0-5-0	
				41	0-6-0	
				40	0-8-0	
				5	1-2-0	

[सं. प्री. 14016/240/84 जी. पी.]

S.O. 718.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. No 3300 dated 15-11-88 under sub-section (1) of the Petroleum and Natural Gas and Mines Pipeline (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)
H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Bigha	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Badaun	Gunaur	Asadpur	Malpur	31	0-2-0	
				30	0-1-0	
				26	0-5-0	
				41	0-6-0	
				40	0-8-0	
				5	1-2-0	

[No. O-14016/240/84-G.P.]

का. भा. सं. 719--यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रजनन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 उपधारा (1) के अर्थात् भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का. भा. सं. तारीख 3359/12/11/88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईप लाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः मुख्य प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अर्थात् सरकार की रिपोर्ट दे दी है।

और प्राये यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और प्राये उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के अर्थात् भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में धोवणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच. बी. जे गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बदायूँ	बिसौली	बिसौली	फतेहपुर बिरमपुर	585	0-2-0	
				586	0-13-0	
				222	0-15-0	
				223	0-1-10	
				590	6-7-0	
				215	1-2-0	
				709	0-8-12	
				224	0-3-60	
				8	4-12-12	

[सं. भा. 14016/469/85 जी.पी.]

S.O. 719.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. No. 3359 dated 18-11-88 under sub-section (1) of section of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification considering the said report, decided to acquire the right of for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of the power conferred by the section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

Supplimentary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Badaun	Besaoli	Besaoli	Fatahapur	585	0-2-0	
			Vecrampur	586	0-13-0	
				222	0-15-0	
				233	0-1-10	
				590	1-7-10	
				215	1-2-0	
				209	0-8-12	
				244	0-3-10	
				8	4-12-12	

[No. O 14016/459/85-G.P.]

का० भा० 720—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संस्थान अधिसूचना सं० का० भा० 3360 तारीख 12-11-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आग्रह घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बदायँ	बिसौली	बिसौली	निजरा	121	0-1-4	
				124	0-2-0	
				126	0-5-0	
				122	0-8-0	
				123	0-2-10	
				127	0-14-15	
				182	0-1-15	
				199	0-1-15	
				128	0-11-0	
				64	0-1-14	
				10	2-12-13	

[सं० भो-14016/371/85-जी० पी०]

S.O. 720.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. No. 3360 dated 12-11-88 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declare its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Badaun	Besauli	Besauli	Nizra	121	0-1-4	
				124	0-2-0	
				126	0-5-0	
				122	0-8-0	
				123	0-2-10	
				127	0-14-15	
				182	0-4-15	
				199	0-1-15	
				128	0-11-0	
				64	0-1-14	
				10	2-12-13	

[No. O-14016/371/85-G.P.]

का० प्रा० 721—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 3295 तारीख 5-11-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को मिहित होगा ।

अनुसूचक नाम अनुसूची

एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल बीघा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बदायूँ	बिसौली	बिसौली	खजुरिया	140	0-2-0	

[सं० प्रो-14016/224/85—जी० पी०]

S.O. 721.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3295 dated 5-11-88 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Bighas	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Balau	Bisauli	Bisauli	Khajuria	140	0-2-0	

[No. O.14016/224/85-G.P

का० भा० 722—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० भा० 3288 तारीख 5-11-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अबः अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाना है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेदन करती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ;

अनुसूचक नाम अनुसूची

एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बबामुं	बिसौली	बिसौली	साहनपुर	11	0-7-15	
				12	0-4-10	
				13	0-3-15	
				60	0-0-15	
				61	0-4-0	
				62	0-4-0	
				6	1-4-15	

[सं० मो-14016/214/85-जी० पी०]

S.O. 722.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3288 dated 5-11-88 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
	2	3		5		7
	Bilari Beraoli	Beraoli	Sahanpur	11	0-7-15	
				12	0-4-10	
				13	0-3-15	
				60	0-0-15	
				61	0-4-0	
				62	0-4-0	
				6	1-4-15	

[No. O-14016/214/85-G.P.]

का० आ० 722—यत्, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना की सं० का० आ० 3284 तारीख 5-11-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राणय घोषित कर दिया था ;

और यत्: गक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यत्: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब: अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची वाद अनुसूची

एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जन्पद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
रायबरेली	महाराजगंज	बछरावां	बसरावां	935	0-1-0	
				936	0-1-0	
				2	0-2-0	

[सं० ओ-14016/161/84-जी० पी०

S.O. 723.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3284 dated 5-11-88 under sub-section (1) of section of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.I. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Raibareilly	Maharajganj	Bachhrawan	Bannawan	935	0-1-0	
				936	0-1-0	
				2	0-2-0	

[N.O. 14016/161/84-G.P.]

का० घा० 724—यतः पेट्रोलियम और खनिज वाह्य लाइन (भूमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का० घा० सं० 3270 तारीख दि० 5-11-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को वाह्य लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार वाह्यलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेश होती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूचक बाद अनुसूची

एच० बी० जी० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
रायबरेली	लिनोई	सेगरोता	सेगरोता	182	0-0-10	
				201	0-5-0	
				2	0-5-10	

[सं अ० — 14016/04/84-जी० सी०]

S.O. 724.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3270 dated 5-11-88 under sub-section (1) of section of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

Supplementary case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Raebareli	Tiloi	Semraota	Semraota	182	0-0-10	
				201	0-5-0	
				2	0-5-10	

[No. O-14016/04/84-G.P.]

का. आ. 725.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) 1962 का 50) की धारा 3 उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना कां० आ० सं० तारीख 3287 दि० 5-11-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अतः अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उन धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जन्पद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
रायबरेली	महाराजगंज	हरदोई	तोली	531	0-5-0	

[सं० पी०-14016/168/84—जी० पी०]

S.O. 725.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3287 dated 5-11-88 under sub-section (1) of section of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Raebareli	Maharaj Ganj	Hardoi	Taoli	531	0 5 0	

[N.O-14016/168/84-G.P.]

का० आ० 726—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का० आ० सं० 3289 तारीख दि० 5-11-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का भ्रपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में शोषण के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक वाव अनुसूची

एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
रायबरेली	महाराजगंज	बछरावाँ	मलपुर	1018	0-12-0	

[सं० ओ-14016/240/84—जी० पी०]

S.O. 726.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3289 dated 5-11-88 under sub-section (1) of section of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Raebareli	Maharaj Ganj	Bachrawan	Malpur	1018	0 12 0	

[N.O-14016/240/84-G.P.]

का. आ. 727.—यत् पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का आ.सं. 3286 दि. 5-11-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जन करने का अपना प्राण्य घोषित कर दिया था ;

और यत् मध्यम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यत् केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जन किया जाता है ;

और आगे उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूचक बाद अनुसूची
एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा नं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
रायबरेली	महाराजगंज	बछरावा	थुलन्डी	1384	0-6-0	
				1444	0-2-0	
				1348	0-4-0	
				1632	0-3-0	
				1506	0-0-5	
				1394	0-3-0	
				1392	0-5-0	
				7	1-3-5	

[सं. ओ-11016/164/84-जी.पी.]

S.O. 727.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3286 dated 5-11-88 under sub-section (1) of section of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to it a notification for purpose of laying pipelines ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)
H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Raebareli	Maharaj Ganj	Bachhrawan	Thulendi	1384	0-6-0	
				1444	0-2-0	
				1348	0-4-0	
				1632	0-3-0	
				1506	0-0-5	
				1394	0-3-0	
				1392	0-5-0	
				7	1-3-5	

[N. O-14016/164/84 G.P.]

का.आ. 728.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का.आ.सं. 3276 वि. 5-11-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियां में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन को इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूचक गांव अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	बिबरण
1	2	3	4	5	6	7
रायबरेली	तिलोई	सेगरौता	जगराबां	1721	0-0-10	
				1779	0-1-0	
				2	0-1-10	

[सं. भो. - 14016/15/84-जो. पी.]

S.O. 728.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3276 dated 5-11-88 under sub-section (1) of section of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act), 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of powers conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

Supplementary case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pragana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Raebareli	Tiloi	Semraota	Jamrawan	1721	0-0-10	
				1779	0-1-0	
				2	0-1-10	

[No. O-14016/15/84-G.P.]

का.आ. 729.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का.आ.सं. 3291 वि. 5-11-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे का केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाश्चात्ताह विधान के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी आधाराओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूचक बाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
रायबरेली	महाराजगंज	बछरावाँ	पनासा	395	0-2-0	
				269	0-6-0	
				2	0-8-0	

[सं.आ. 14016/316/84-ओ.पी.]

S.O. 729.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3291 dated 5-11-88 under sub-section (1) of section of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act), 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of powers conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

Supplementary case (Scheduled)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Raebareli	Mithraj Ganj	Bachawan	Penasa	395	0-2-0	
				269	0-6-0	
				2	0-8-0	

[No O-14016/316/84-CP]

का.आ. 730.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का.आ.सं. 3277 दि. 5-11-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को विधान के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः महम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाश्चात्ताह विधान के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की उक्त तारीख को निहित होगा।

अनुसूचक बाद अनुसूची

एच बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा स.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	4	4	5	6	7
रायबरेली	महाराजगंज	समरौता	पुरसी	366	0-5-0	
				171	0-5-0	
				345	0-2-0	
				3	0-12-0	

[सं. मो. - 14016/25/84-जी.पी.]

S.O. 730.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3277 dated 5-11-88 under sub-section (1) of section of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act), 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of powers conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H B J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot (N).	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Raebari	Maharaj Ganj	Samarota	Purasi	366	0-5-0	
				171	0-5-0	
				345	0-2-0	
				3	0-12-0	

[N. O. 14016/25/84-G.P.]

का.आ. 731 ---यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिवृत्त का.आ.सं. 3285 दि. 5-11-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिवृत्त में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पापलातों को बिलाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः संलग्न प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् स अधिवृत्त से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिवृत्त में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिलाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूचक बाढ़ अनुसूची

एन. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जन्तव	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
रायबरेली	महाराजगंज	सेमरोता	समसपुर हलौर	592	0-2-6	

[सं. ओ-14016/163/84-जी.पी.]

S.O. 731.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3285 dated 5-11-88 under sub-section (1) of section of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act), 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of powers conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

Supplementary case (Sch. dule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acers	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Raebareli	Maharaj Ganj	Sem acta	Samspurhalor	592	0-2-6	

[No. O-14016/163/84 G.P.]

का. घा. 732—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि उपयोग में अधिکار का अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का.घा.सं. 3242 दि. 5-11-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों से में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोग के लिए तद्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा दत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमि से में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकारण की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूचक बाढ़ अनुसूची

एन. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जन्तव	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
रायबरेली	तिलोई	इहोता	ठाकपुर	412	0-1-5	

[सं. ओ-14016/04/84-जी.पी.]

S.O. 732.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3247 dated 5-11-88 under sub-section (1) of section of the Petroleum and Minerals Pipelines Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

Supplimentary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Ranchareli	Tiloi	Inhona	Dedapur	412	0-10-5	

[N. O.-14016/04/84-G.P.]

का.प्रा. 733.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का.प्रा.सं. 3269 दि. 5-11-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारों ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी शर्तों से सम्बन्धित रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूचक पाइप लाइन अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	प्लॉट नं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
रायबरेली	तिलोई	इन्होनी	राजापुर	8	0-2-0	
				20	0-2-0	
				2	0-4-0	

[सं. प्रो-14016/04/84-जी.पी.]

S.O. 733.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3269 dated 5-11-88 under sub-section (1) of section of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

Supplimentary case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Raebareli	Tiloi	Inhona	Rajapur	8	0-2-0	
				20	0-2-0	
				2	0-4-0	

[No. O-14016/04/84-6 G.P.]

का.पा. 734.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम) (अधिनियम 1962 (1962 का 50)) को धारा 3 उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का.पा.सं. 3268 दि. 5-11-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट खे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूचक बांध अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जन्मपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
रायबरेली	तिलोई	इन्होना	फतेहपुर	476	0-1-10	

[सं.प्री.- 14016/04/84-जी.पि.]

S.O. 734.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3268 dated 5-11-88 under sub-section (1) of section of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And Further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Control Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from oncumbrances.

Supplimentary case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Raebareli	Tiloi	Inhona	Fatehpur	476	0-1-10	

[No. O-14016/04/84-G.P.]

का.प्रा. 735.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का.प्रा.सं. 3283 वि. 5-11-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए, एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूचक भाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल बीघा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
राय बरेली	तिलोई	इन्हौना	बनभरिया	1804	0-2-0	
				1877	0-2-0	
				1820	0-2-0	
				1865	0-2-0	
				1665	0-3-0	
				2471	0-2-0	
				6	0-13-10	

[सं. प्रो. 14016/160/84-जी.बी.]

S.O. 735.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3283 dated 5-11-88 under sub-section (1) of section of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acers	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Raebareli	Tiloi	Inhona	Binbharia	1804	0-2-0	
				1877	0-2-0	
				1820	0-2-10	
				1865	0-2-0	
				1665	0-3-0	
				2471	0-2-0	
				6	0-13-10	

[No. O-14016/160/84-G.P.]

का.भा. 736.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का प्रा.सं. 3271 दि. 5-11-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाया भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की दृष्टि तारीख को निहित होगा।

अनुसूची: गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जन्पर्व	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
रायबरेली	तिलोई	इन्हांना	रतवालिया मनझार	1119	0-2-0	
				1157	0-3-10	
				2	0-5-10	

[सं. ओ-14016/04/984-जी.पी.]

S.O. 736.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3271 dated 5-11-88 under sub-section (1) of Section of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Raebareli	Tiloi	Inhona	Ratwalia Manjhar	1149	0-2-0	
				1157	0-3-10	
				2	0-5-10	

[No : O-14016/04/84-G.P.]

का.भा. 737.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का.अ.सं. 3292 दि. 5-11-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की उस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक वाह अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जलपद	तहसील	परगना	ग्राम	काटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
रायबरेली	महाराजगंज	हर्दोई	पारा खुर्द	592	0-4-10	
				602	0-3-0	
				2	0-7-10	

[य.प्रो.-14016/318/84-गो.पं.]

S.O. 737.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3292 dated 5-11-88 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Raebareli	Maharaj Ganj	Hardoi	Parakhord	592	0-4-10	
				602	0-3-0	
				2	0-7-10	

[No. O 14016/318/84-G.P.]

का.आ. 738—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम बिभाग की अधिसूचना का.आ. सं. 303 (ई) के लिए तारीख 18-2-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार के पाइप लाइनों को बिछाने अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और अतः सभ्य प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस प्राधिकरण लि., उर्जा विभाग, नयी दिल्ली, दल रोड, बडोवरा सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन के तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

वाघोडिया से आई.पी.सी.एल. गैस पाइपलाइन

गुजरात स्टेट जिला : वडोदा

तालुका : वाघोडिया

गांव	सर्वे नं./खलाक नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
वाघोडीया	752/2	00	12	96

[सं. ओ-14016/578/87-जी बी]

S.O. 738.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 303(E) dated 16-2-88 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the

said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from cumbrances.

SCHEDULE

PIPE FROM VAGHODIYA TO IPCL

State : Gujarat, District : Vadodara, Taluka : Vaghodia.

Village	Survey No.	H ctare	Are	Centiare
Vaghodia	752/2	00	12	96

[No. O-14016/578/87-G.P.]

का.आ. 739.—यत् वैद्रीयम और अनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय वैद्रीयम विभाग की अधिसूचना का.आ.सं. 1010 तारीख 18-2-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जन करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत् केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जन करने का विनिश्चित किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा अर्जन किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की वजह से गैस प्रोसेसिंग आक इंडिया लि., दर्पण बिल्डिंग, आर.सी. दम रोड बड़ोदरा सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन कि इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

वाघोडिया से आई.पी.सी.एल. गैस पाइप लाइन

गुजरात स्टेट जिला : वडोदा

तालुका : वडोदा

गांव	सर्वे नं./खलाक नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
दशरथ	526	00	01	26
	340	00	01	60
	325	00	01	81

[सं. ओ-14016/572/87-जी पी]

S.O. 739.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1140 dated 18-2-1988 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Vaghodiya to IPCL

State : Gujarat, District : Vadodara, Taluka : Baroda

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Dasrath	526	00	01	26
	340	00	01	60
	325	00	01	81

[No. O-14016/572/87-G.P.]

का. घा. 740.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.घा.सं. 1138 तारीख 18-2-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार के रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लि., वॉशिंग्टन, डी.सी. वन रोड, बड़ोदरा, ये सभी आवाजों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

वाघोडीया से आई.पी.सी. गैस पाइप लाईन

गुजरात स्टेट जिला : बड़ोदरा तालुका : बड़ोदरा

गांव	खण्ड नम्बर	हेक्टर	घारे	सेन्टीयर
दुमाड	818	00	00	49
	977	00	00	72
	964	00	03	96
	947	00	00	90
	886	00	15	60
	889	00	11	78
	883	00	04	14
	398	00	25	20
	530 A+B	00	17	68
	529	00	07	92
	949		03	96

[सं. ओ-14016/567/87-जी.पी. 3]

S.O. 740.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1138 dated 18-2-88 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the

right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Vaghodiya to IPCL

State : Gujarat, District : Vadodara, Taluka : Vadodara

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Dumad	818	00	00	49
	977	00	00	72
	964	00	03	96
	947	00	00	90
	886	00	15	60
	885	00	11	78
	883	00	04	14
	398	00	25	20
	530 A+B	00	17	68
	529	00	07	92
	949	00	03	96

[No. O-14016/567/87-G.P.]

का.प्र. 741.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.प्र.सं. 1141 तारीख 18-2-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय गैस आथारिटी आफ इंडिया लि., वर्पण विल्डिंग, आर.सी. बत रोड, बड़ोदरा, में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन कि इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

वांछोदिया से आई.पी.सी.एल. गैस पाइप लाइन

गुजरात स्टेट जिला : बड़ोदरा

तालुका : बड़ोदरा

गांव	सर्वे ब्लॉक नम्बर	हेक्टर	घाह	सेन्टीआर
आपलीदारा	208	00	10	32

[अं. ओ. 14016/574/87-जी.पी.]

S.O. 741.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1141 dated 18-2-88 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said

lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from cumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Vaghodiyā to IPCL

State : Gujarat, District : Vaghodiyā, Taluka : Baroda

Village	Block No.	Hectare	Are	Cintiare
Emauliyara	208	00	10	32

[No. O-14016/574/87-G.P.]

का.प्र. 742.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.प्र.सं. 1139 तारीख 18-2-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस आथारिटी आफ इंडिया लि., वर्पण विल्डिंग, आर.सी. बत रोड, बड़ोदरा, में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

वाघोडिया से आई.पी.सी.एल. गैस पाईप लाइन

गुजरात स्टेट : बड़ौदा

तालुका : बड़ौदा

गांव	सर्वे नम्बर	हेक्टर	घारे	सैन्टीयर
हरनी	752/1/पायकी	00	00	50
	757/11 पायकी	00	22	86
	757/कुने	00	10	03
	757/1/पायकी	00	21	33
	757/1/पायकी	00	32	40
	757/1/पायकी	00	43	10
	757/1/पायकी	00	01	56
	757/11/पायकी	00	35	10
	757/1/पायकी	00	33	40

[सं. ओ-14016/58/87 जीपी]

S.O. 742.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1139 dated 18-2-88 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in

Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. cumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Vaghoḍiya to IPCL

State : Gujarat, District : Vaḍoḍara, Taluka : Vaḍoḍara

Village	Survey No.	Hectare	Are	Cintiare
Harani	757/1 Paiki	00	00	50
	757/1 Paiki	00	22	86
	757/1 Paiki	00	10	03
	757/1 Paiki	00	21	33
	757/1 Paiki	00	32	40
	757/1 Paiki	00	43	10
	757/1 Paiki	00	01	56
	757/1 Paiki	00	35	10
	757/1 Paiki	00	33	40

[No. O-14016/568/87-G.P.]

क्र.सं. 743 .—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना क्र.सं. 304(ई), तारीख 18-2-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अधिनियम करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अधिनियम करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अधिनियमित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय गैस आयोग लि. इंडिया लि. दर्पण थिन्डिंग, आर.सी. वस्त रोड, बड़ौदा, सभी वाधाओं को मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

वाघोडिया से आई.पी.सी.एल. गैस पाईप लाइन

गुजरात स्टेट जिना :—बड़ौदा तालुका : लुघोडोवा

गांव	सर्वे नम्बर	हेक्टर	घारे	सैन्टीयर
कुमेठा	83/2	00	09	36

[सं.ओ-14016/569/87-जी.पी.]

S.O. 743.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 304(E) dated 18-2-88 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the

said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. cumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Vaghodiya to IPCL

State : Gujarat, District : Vadodara, Taluka : Vaghodiya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Kumetha	83/2	00	09	36

[No. O-14016/569/87-G.P.]

का.भा. 744.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.भा.सं. 302(ई), तारीख 18-2-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार से उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और अतः उक्त प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दी गई है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है।

अतः, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रबल शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रबल शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय गैस अथोरिटी ऑफ इंडिया लि. दण्ड विनिर्दिष्ट, आर. सी वत रोड, बड़ोदरा सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

वाघोदीया के आई.पी.सी.एल. गैस पाइप लाइन

राज्य : गुजरात

जिला : वडोदा

तालुका : वाघोडीया

गांव	सर्वे नम्बर/ब्लॉक नम्बर	हेक्टर	घर.	सेंटियर
भादोल-खुराद	145	00	04	05

[सं. ओ 14016/87/88-जी.पी.],

S.O. 744.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 302(E) dated 18-2-88 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central

Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. cumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Vaghodiya to IPCL

State : Gujarat, District : Vadodara, Taluka : Vaghodiya

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Bhadol-Khurad	145	00	04	05

[No. O-14016/87/88-G.P.]

का.भा. 745—निम्न चूंकि गैस अथोरिटी ऑफ इंडिया लि. ने धारा 6(1) पेट्रोलियम एण्ड मिनेरल्स पाइप लाइन ऐक्ट, 1962 के अन्तर्गत पाइप लाइन डालने हेतु निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित प्राथमिक भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित किया है एवं वह उक्त प्राथमिक भूमियों में कानून 1 धारा 7/1 पेट्रोलियम

एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन एक्ट 1962 में उल्लिखित पाइप लाइन डालने का कार्य दिनांक 16 जनवरी, 1989 को पूर्ण कर लिया है। अतः मैं मोहनलाल गुप्ता सक्षम प्राधिकारी कोटा नियम 4/1 पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन नियम 1963 के अंतर्गत एतद्वारा उपरोक्त उल्लेखित दिनांक को इन ग्रामों में पाइप लाइन डालने के कार्य की समाप्ति का दिनांक अधिसूचित करता हूँ।

अनुसूची

क्रमांक	नाम	नाम तहसील	नाम जिला	का. प्रा. संख्या	कार्य समाप्ति का दिनांक
1	कवाई	अट्रु	कोटा	453(ई)	16 जनवरी, 89

[फाइल सं. मो. 14016/130/84-जी.पी.]

एम. एल. गुप्ता, सक्षम प्राधिकारी

SCHEDULE

S. O. 745—Following whereas Gas Authority of India Ltd. has acquire the right of user under Section 6(i) of the Petroleum and Minerals Pipeline Act, 1962 for laying the pipeline in the villages mentioned in the schedule given below and has completed the laying of pipeline as referred to in Clause 1 of section 7 (i) of the Petroleum and Minerals Pipeline Act 1962 in these villages on 16 Jan., 1989 I, M.L. GUPTA, Competent Authority, Kota hereby notify under Rule 4 (i) of the Petroleum and Minerals Pipeline Rules 1963 the above mentioned date as the date of termination of operation of laying the pipeline in these villages.

Sl. No.	Name of the village	Name of Tehsil	Name of District	S.O. No.	Date of termination of the operation
1	Kawai	Atru	Kota	453(E)	16th January 1989

[File No. O-14016/130/84-G.P.]
M.L. GUPTA, Competent Authority

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1989

का.प्रा. 746.—केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपायध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है।

अतः केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रयत्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. राजस्व/34/88, तारीख 10 अक्टूबर, 1988 का निरीक्षण, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स (राजस्व अनुभाग), दरभंगा हाउस, रांची के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या उपायुक्त, पालामऊ (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चाटों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, राजस्व अधिकारी सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची को भेजेंगे।

अनुसूची

कोटेक्या ब्लॉक

औरंगा कोलफील्ड्स

जिला-पालामऊ (बिहार)

(पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि की वृत्ति हुए)

क्र.सं.	ग्राम	थाना और ग्रंथल	थाना सं.	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियाँ
1.	बाजु	बाजुमठ	110	पालामऊ	128.00	भाग
2.	नवारी	सटेहर	337	"	25.50	भाग
3.	मुरप	"	339	"	225.00	भाग
4.	मात्मागड़ी	"	340	"	115.25	भाग
5.	लूटी	"	342	"	325.00	भाग
6.	बाम्हनहेरा	"	343	"	256.00	भाग
7.	पनबका	"	344	"	.08 (लगभग)	संपूर्ण
8.	कोटेक्या	"	345	"	224.00 (लगभग)	संपूर्ण
9.	कुंडी	"	346	"	339.25	भाग
10.	पतरातू	"	352	"	224.00	भाग
11.	बाताम	"	353	"	6.00	भाग
कुल क्षेत्र :					2060 एकड़ (लगभग)	
या					833.64 हेक्टेयर (लगभग)	

सीमा वर्णन :

- क-ख रेखा ग्राम नवारी ग्राम से होकर जाती है, फिर मुख्य, कुंडी और पतरातु ग्रामों से होकर ग्राम मुख्य और मांगरी ग्रामों की भागत: सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'ख' पर मिलती है।
- ख-ग रेखा लतेहर अंचल के ग्राम पतरातु और दाताम ग्रामों तथा बालूमठ अंचल के ग्राम बालू से होकर जाती है और बिन्दु 'ग' पर मिलती है।
- ग-घ रेखा, बालूमठ अंचल के ग्राम बालू और वाम्बुनहेरा, लूटी, माल्यागढ़ी ग्रामों से होकर जाती है और बिन्दु 'घ' पर मिलती है।
- घ-क रेखा माल्यागढ़ी ग्राम में से होकर बोया और मारुप ग्रामों की भागत: सम्मिलित सीमा के साथ, ग्राम नवारी से होकर जाती है और आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[सं. 43015/14/83-एन एस डब्ल्यू]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 3rd March, 1989

S.O. 746.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the land mentioned in the schedule hereto annexed.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan No. Rev/34/88 dated the 10th October, 1988 of the area covered by this notification can be inspected at the office of the Central Coalfields Limited (Revenue section), Darbhanga House, Ranchi or at the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or at the Office of the Deputy Commissioner, Palamau (Bihar).

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi, within ninety days from the date of publication of this notification.

SCHEDULE

KOTHERUA BLOCK

AURANGA COALFIELD

DISTRICT—PALAMAU (BIHAR)

(Showing land notified for prospecting)

Serial No.	Village	Thana and Anchāl	Thana Number	District	Area	Remarks
1.	Balu	Balumath	100	Palamau	128.00	Part
2.	Nawari	Latchar	337	Palamau	25.50	Part
3.	Murup	Latchar	339	Palamau	225.00	Part
4.	Bhalygari	Latchar	340	Palamau	115.25	Part
5.	Luti	Latchar	342	Palamau	325.00	Part
6.	Bamhanherua	Latchar	343	Palamau	256.00	Part
7.	Panruka	Latchar	344	Palamau	192.08	Full
					(approximately)	
8.	Kotheruwa	Latchar	345	Palamau	224.00	Full
					(approximately)	
9.	Kundri	Latchar	346	Palamau	339.25	Part
10.	Patratu	Latchar	352	Palamau	224.00	Part
11.	Datam	Latchar	353	Palamau	6.00	Part
Total area : 2067.00 acres (approximately)						
or 833.64 hectares (approximately)						

Boundary description:—

- A—B line passes through village Nawari, then passes along part common boundary of villages Murup and Mangro, through villages Murup, Kundri and Patratu and meets at point '3'.
- B—C line passes through villages Patratu and Datam of Latchar Anchāl and village Balu of Balumath Anchāl and meets at point 'C'.

- C—D line passes through village Balu of B. lumath Anchal and through villages Bannherua, Lutr, Bhalygari and meets at point 'D'.
- D—A line passes through village Bhalygari, along part common boundary of villages Chopra and Marup, through village Nawari and meets at starting point 'A'.

[No. 43015/14/88-LSW]

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1989

का.भा. 747.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जुन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 9 मई, 1987 में प्रकाशित, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का.भा. 1199 तारीख 24-4-87 द्वारा उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि के, जिसका माप 683.10 एकड़ (लगभग) या 276.43 हेक्टर (लगभग) है, अर्जुन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और बिहार सरकार से परामर्श कर लिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 683.10 एकड़ (लगभग) 6. हेक्टर (लगभग) माप वाली भूमि अर्जित की जाती चाहिए।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 683.10 एकड़ (लगभग) या 276.43 हेक्टर (लगभग) माप वाली भूमि अर्जित की जाती है।

2. इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण उप आयुक्त, हजारी बाग (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, कार्जसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में, या सेट्रल कोनक्रिट्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है।

रेखांकित सं. राजस्व/41/87

तारीख 12-8-1987

अनुसूची

पीपरवार विस्तार क्षेत्र ब्लॉक II

उत्तर करनपुरा कोयला क्षेत्र

जिला हजारी बाग (बिहार)

अर्जित की गई भूमि

ब्लॉक "क"

सभी अधिकार

क्र.सं.	ग्राम	थाना	थाना सं.	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियाँ
1.	किचटों	टोडवा	78/235	हजारीबाग	107.00	भाग
2.	बहेरा	टोडवा	79/235	हजारीबाग	308.70	भाग
3.	कनौडा	टोडवा	81/238	हजारीबाग	188.00	भाग
4.	राजघार	टोडवा	82/239	हजारीबाग	19.25	भाग
5.	कल्याणपुर	टोडवा	85/242	हजारीबाग	53.28	भाग
कुल क्षेत्र					676.20 एकड़ (लगभग)	
या					273.64 हेक्टर (लगभग)	

ग्राम किचटों में अर्जित प्लॉट संख्यांक :

1 (भाग), 2 (भाग), 3, 4, 5 (भाग), 31 (भाग), 34 (भाग), 35 से 50, 51 (भाग), 52 (भाग), 53, 54, 55, 56 (भाग), 57, 58, 59 (भाग), 60 (भाग), 73 (भाग), 74 (भाग), 75 (भाग), 76 से 90, 91 (भाग), 92 (भाग), 93 (भाग), 94 (भाग), 95, 96, 97, 98 (भाग), 9, 100 (भाग), 101 (भाग), 103 (भाग), 104 (भाग), 124 (भाग), 128 (भाग), 129 (भाग), 131 (भाग), 133 (भाग), 134 (भाग), 135, 136, 137 (भाग), 138 (भाग), 139 (भाग), 141 (भाग), 142 (भाग), 143, 144 (भाग), 145 (भाग), 148 (भाग), 150, 151 (भाग), 152 (भाग), 153 (भाग), 283 (भाग), 291 (भाग), 292 (भाग), 293 (भाग), 294 (भाग), 354 (भाग), 355 (भाग), 356 (भाग), 361 (भाग), 364 (भाग), 377 (भाग), 392 (भाग), 538 (भाग), 558 (भाग), और 664।

ग्राम बहेरा में अर्जित प्लॉट संख्यांक :

1 (भाग), 24 (भाग), 25 (भाग), 26 से 35, 36 (भाग), 62 (भाग), 71 (भाग), 76 (भाग), 78 (भाग), 79 (भाग), 80 से 264 (भाग), 265 (भाग), 266 (भाग), 267 से 270, 271 (भाग), 272 (भाग), 274 (भाग), 282 (भाग), 283 (भाग), 289 (भाग), 290 (भाग), 291 से 359, 360 (भाग), 361 (भाग), 362 (भाग), 363, 364 (भाग), 372 (भाग), 373 (भाग), 374 से 377, 378 (भाग), 379 से 390, 391 (भाग), 392 से 398, 399 (भाग), 400, 401 (भाग), 402 (भाग), 403 (भाग), 404 से 455, 456 (भाग), 457 से 467, 468 (भाग), 475 (भाग), 478 (भाग), 479 (भाग), 480, 481, 482, 483 (भाग), 484 (भाग), 485 (भाग), 486 (भाग), 487 (भाग), 509 (भाग), 574 (भाग), 576 (भाग),

577 (भाग), 579 (भाग), 590 (भाग), 711, 713, 714 (भाग), 715, 716 (भाग), 717, 719, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725 (भाग) और 726।

ग्राम कनौडा में अर्जित प्लॉट संख्यांक :

1 (भाग), 5 (भाग), 6 (भाग), 7 (भाग), 8 (भाग), 11 (भाग), 26 (भाग), 27 (भाग), 35 (भाग), 36 (भाग), 37 से 40, 41 (भाग) 42 और 43।

ग्राम राजधर में अर्जित प्लॉट संख्यांक

174 (भाग), 176 (भाग), 177 से 183, 184 (भाग), 185 से 189, 190 (भाग), 191 (भाग), 192 (भाग), 193, 194 (भाग), 195 (भाग), 204 (भाग), 205 (भाग), 206, 207, 208 और 210।

ग्राम कल्याणपुर में अर्जित प्लॉट संख्यांक :

152 (भाग), 153 (भाग), 154 (भाग), 156 (भाग), 157 (भाग), 158 (भाग), 159 (भाग), 160 (भाग), 214, 215 (भाग), 216 (भाग), 252 (भाग), 256 (भाग), 258 (भाग), 259 से 263, 264 (भाग), 265 (भाग), 273 (भाग), 271 (भाग), 275 (भाग), 276, 277 (भाग), 278 (भाग), 279 से 291, 292 (भाग), 293 और 294।

सीमा वर्णन

- क-ख रेखा ग्राम कल्याणपुर से प्लॉट संख्यांक 154, 153, 157, 153, 152, 215, 216, 252, 259, 256, 264, 265, 275 274, 273, 277 और 278 से होकर जाती है फिर ग्राम राजधर के प्लॉट संख्यांक 174, 176, 184, 174, 190, 191, 192, 195, 194 और 204 से होते हुए ग्राम बहेरा में प्लॉट संख्यांक 725 से होकर जाती है।
- ख-ग रेखा ग्राम बहेरा के प्लॉट संख्यांक 725 से होकर फिर ग्राम राजधर के प्लॉट संख्यांक 204 से होते हुए ग्राम कनौडा के प्लॉट संख्यांक 35, 36, 35, 35, 41, 7, 27, 26, 11, 7, 8, 7, 5, 1 और 6 से होकर जाती है।
- ग-घ रेखा कनौडा और बिचैन, कनौडा और पिवरवाड ग्रामों की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ साथ जाती है।
- घ-ङ-च रेखा किचटो ग्राम के प्लॉट संख्यांक 1, 2, 5, 31, 34, 56, 60, 59, 75, 74, 73, 151, 152, 153, 148, 144, 145, 144, 142, 141, 139, 137, 138, 137, 283, 134, 283, 292, 291, 294, 361, 392, 356, 354, 392, 558 और 538 से होकर जाती है।
- च-छ रेखा किचटो ग्राम के प्लॉट संख्यांक 558 और 538 से होकर जाती है।
- छ-ज-झ रेखा किचटो ग्राम के प्लॉट संख्यांक 538, 558, 392, 355 और 392 से होकर जाती है।
- झ-ञ रेखा किचटो ग्राम के प्लॉट संख्यांक 392, 377, 392 और 377 से होकर जाती है।
- ट-ड रेखा किचटो ग्राम के प्लॉट संख्यांक 377, 392 और 356 से होकर जाती है।
- ड-ड-ड-ड-ण रेखा किचटो ग्राम के प्लॉट संख्यांक 356, 392, 361, 293, 364, 124, 283, 133, 131, 129, 128, 92, 91, 93, 94, 98, 52, 101, 100, 103, 104 और 51 प्लॉट संख्यांक 37 की पूर्वी सीमा से होकर जाती है फिर ग्राम के प्लॉट संख्यांक 364, 362, 361, 360, 373, 372, 378, 391, 399, 401, 402, 403, 590, 456, 579, 577, 576, 574, 483, 484, 485, 486, 487, 478, 479, 475, 468, 509 और 1 से होकर प्लॉट संख्यांक 363 की पूर्वी सीमा के साथ साथ जाती है।
- ण-त रेखा बहेरा और कारो ग्रामों की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है।
- त-थ रेखा बहेरा ग्राम के प्लॉट संख्यांक 1, 290, 289, 290, 283, 282, 272, 274, 271, 62, 266, 265, 70, 78, 71, 79, 36, 35, 24, 714 और 716 से होकर जाती है।
- थ-द-ड-त रेखा राजधर और बहेरा ग्रामों की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ, राजधर ग्राम के प्लॉट संख्यांक 205 में से होकर, प्लॉट संख्यांक 215 की पूर्वी सीमा पर प्लॉट सं. 292 और 184 में से होकर कल्याणपुर ग्राम के प्लॉट सं. 215, 158 और 159 में से होकर जाती है।
- न-क रेखा प्लॉट संख्यांक 160, 156 से होकर प्लॉट संख्यांक 159 की उत्तरी सीमा, कल्याणपुर ग्राम के प्लॉट संख्यांक 154 की उत्तरी सीमा, कल्याणपुर ग्राम के प्लॉट संख्यांक 154 की उत्तरी सीमा के साथ साथ जाती है, और आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

क्लाक "ख"

सभी अधिकार

क्र.सं.	ग्राम	थाना	थाना सं.	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियाँ
1. किचटो		टांडवा	78/235	हजारीबाग	6.90	भाग
					कुल क्षेत्र:	6.90 एकड़ (लगभग)
					या	2.79 हेक्टर (लगभग)

ग्राम किचटो में अर्जित प्लॉट संख्यांक :

535 (भाग), 536 (भाग) और 537 (भाग)।

सीमा वर्णन :

- प-फ रेखा किचटो ग्राम के प्लाट संख्यांक 537 से होकर जाती है।
 फ-ब रेखा किचटो ग्राम के प्लाट संख्यांक 537 और 537 से होकर जाती है।
 ब-भ रेखा किचटो ग्राम के प्लाट संख्यांक 535 से होकर जाती है।
 भ-म रेखा किचटो ग्राम के प्लाट संख्यांक 535 और 537 से होकर जाती है और प्रारंभिक बिन्दु "म" पर मिलती है।

[सं. 43015/31/85 सी ए/एस एस डब्ल्यू]

बी.डी. राव, प्रवर सचिव

New Delhi, the 8th March, 1989

S.O. 747.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No.S.O. 1199 dated the 24-4-1987, published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 9th May, 1987, under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the land measuring 683.10 acres (approximately) or 276.43 hectares (approximately) in the locality specified in the schedule appended to that notification;

And whereas the Government of Bihar has been consulted;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act, has made this report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the report aforesaid is satisfied that land measuring 683.10 acres (approximately) or 276.43 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the land measuring 683.10 acres (approximately) or 276.43 hectares (approximately) described in the said Schedule are hereby acquired.

2. The plans of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh (Bihar) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the Central Coalfields Ltd. (Revenue Section), Daibhanga House, Ranchi (Bihar).

Drg. No. Rev/41/87

Dated 12-8 1987.

Schedule
 Piparwar Extension Block II
 North Kazanpura Coalfield
 District Hazaribagh (Bihar)

All Rights		Block 'A'		Showing land acquired.		
Serial No.	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Kichto	Tandwa	78/235	Hazaribagh	107.00	Part
2.	Bahera	-do-	78/236	-do-	308.70	Part
3.	Kanauda	-do-	81/238	-do-	188.00	Part
4.	Rajdhar	-do-	82/239	-do-	19.25	Part
5.	Kalyanpur	-do-	85/242	-do-	53.25	Part
					Total area:— 676.20 acres (approximately)	
					or 273.64 hectares (approximately)	

Plot numbers acquired in village Baheto—

1 (Part), 2 (Part), 3, 4, 5 (Part), 31 (Part), 34 (Part), 35 to 50, 51 (Part), 52 (Part), 53, 54, 55, 56 (Part), 57, 58, 59 (Part), 60 (Part), 73 (Part), 74 (Part), 75 (Part), 76 to 90, 91 (Part), 92 (Part), 93 (Part), 94 (Part), 95, 96, 97, 98 (Part), 99, 100 (Part), 101 (Part), 103 (Part), 104 (Part), 124 (Part), 128 (Part), 129 (Part), 131 (Part), 133 (Part), 134 (Part), 135, 136, 137 (Part), 138 (Part), 139 (Part), 141 (Part), 142 (Part), 143, 144 (Part), 145 (Part), 148 (Part), 150, 151 (Part), 152 (Part), 153 (Part), 283 (Part), 291 (Part), 292 (Part), 293 (Part), 294 (Part), 354 (Part), 355 (Part), 356 (Part), 361 (Part), 364 (Part), 377 (Part), 392 (Part), 538 (Part), 558 (Part) and 664.

Plot numbers acquired in village Bahera:—

1 (Part), 24 (Part), 25 (Part), 26 to 35, 36 (Part), 62 (Part), 71 (Part), 76 (Part), 78 (Part), 79 (Part), 80 to 264, 265 (Part), 266 (Part), 267 to 270, 271 (Part), 272 (Part), 274 (Part), 282 (Part), 283 (Part), 289 (Part), 290 (Part), 291 to 359, 360 (Part), 361 (Part), 362 (Part), 363, 364 (Part), 372 (Part), 373 (Part), 374 to 377, 378 (Part), 379 to 390, 391 (Part), 392 to 398, 399 (Part), 400, 401 (Part), 402 (Part), 403 (Part), 404 to 455, 456 (Part), 457 to 467, 468 (Part), 475 (Part), 478 (Part), 479 (Part), 480, 481, 482, 483 (Part), 484 (Part), 485 (Part), 486 (Part), 487 (Part), 509 (Part), 574 (Part), 576 (Part), 577 (Part), 579 (Part), 590 (Part), 711, 713, 714 (Part), 715, 716 (Part), 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725 (Part) and 726.

Plot numbers acquired in village Kanmauda:—

1 (Part), 5 (Part), 6 (Part), 7 (Part), 8 (Part), 11 (Part), 26 (Part), 27 (Part), 35 (Part), 36 (Part), 37 to 40, 41 (Part), 42 and 43.

Plot numbers acquired in village Rajdhar:—

174 (Part), 176 (Part), 177 to 183, 184 (Part), 185 to 189, 190 (Part), 191 (Part), 192 (Part), 193, 194 (Part), 195 (Part), 204 (Part), 205 (Part), 206, 207, 208 and 210.

Plot numbers acquired in village Kalyanpur:—

152 (Part), 153 (Part), 154 (Part), 156 (Part), 157 (Part), 158 (Part), 159 (Part), 160 (Part), 214, 215 (Part), 216 (Part), 252 (Part), 256 (Part), 258 (Part), 259 to 263, 264 (Part), 265 (Part), 273 (Part), 274 (Part), 275 (Part), 276, 277 (Part), 278 (Part), 279 to 291, 292 (Part), 293 and 294.

Boundary description:—

- A—B line passes through plot numbers 154, 153, 157, 153, 152, 152, 215, 216, 252, 258, 256, 264, 265, 275, 274, 273, 277 and 278 in village Kalyanpur then passes through plot numbers 174, 176, 184, 170, 199, 191, 190, 195, 194 and 204 in Village Rajdhar through plot number 725 in village Bahera.
- B—C line passes through plot number 725 in village Bahera then through plot number 204 in village Rajdhar, through plot numbers 35, 36, 35, 36, 41, 7, 27, 26, 11, 7, 8, 7, 5, 1 and 6 in village Kanmauda.
- C—D line passes along part common boundary of villages Kanmauda and Bijain, Kanmauda and Piprawar.
- D—E—F lines pass through plot numbers 1, 2, 5, 31, 34, 56, 60, 59, 75, 74, 73, 151, 152, 153, 148, 144, 145, 144, 142, 141, 139, 137, 138, 137, 283, 134, 283, 292, 291, 294, 361, 392, 356, 354, 392, 558 and 538 in village Kichto.
- F—G line passes through plot numbers 558 and 538 in village Kichto.
- G—H—I lines pass through plot numbers 538, 558, 392, 355 and 392 in village Kichto.
- I—J line passes through plot numbers 392, 377, 392 and 377 in village Kichto.
- J—K line passes through plot numbers 377, 392 and 356 in village Kichto.
- K—L—M—N—O lines pass through plot numbers 356, 392, 361, 293, 364, 124, 283, 133, 131, 129, 128, 92, 91, 93, 94, 98, 52, 101, 100, 103, 104, and 51, eastern boundary of plot number 37 in village Kichto then passes along eastern boundary of plot number 363, through plot numbers 364, 362, 361, 360, 373, 372, 378, 391, 399, 401, 402, 403, 590, 456, 579, 577, 576, 574, 483, 484, 485, 486, 487, 478, 479, 475, 468, 509, and village Bahera.
- O—P line passes along part common boundary of villages Bahera and Karo.
- P—Q line passes through plot numbers 1, 290, 289, 290, 283, 282, 272, 274, 271, 62, 266, 265, 76, 78, 71, 79, 36, 25, 24, 714 and 716 in village Bahera.
- Q—R—S—T lines pass along part common boundary of villages Rajdhar and Bahera, through plot number 205 in village Rajdhar through plot numbers 292 and 184 eastern boundary of plot number 215 through plot numbers 215, 158, and 159 in village Kalyanpur.
- T—A line passes along northern boundary of plot number 159 through plot numbers 160, 156, northern boundary of plot number 154 in village Kalyanpur and meets at starting point 'A'.

BLOCK 'B'

All Rights

Serial No.	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Kichto	Tandwa	78/235	Hazaribagh	6.90	Part
Total area :—6.90 acres (approximately) or 2.79 hectares (approximately)						

Plot numbers acquired in village Kichto:—

525 (Part), 536 (Part) and 537 (Part).

Boundary description:—

- U—V line passes through plot number 537 in village Kichto.
- V—W line passes through plot numbers 537 and 536 in village Kichto.
- W—X line passes through plot number 535 in village Kichto.
- X—U line passes through plot numbers 535 and 537 in village Kichto and meets at starting point 'U'.

[No. 43015/31/85-CA/LSW]

B.B. Rao Under Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1989

का. प्रा. 748—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, इस्पात और खान मंत्रालय, खान विभाग के अधीन निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उक्त उप नियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है :—

1. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, उदयपुर ।
2. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, मटून माइन्स कार्यालय, मटून (राजस्थान)
3. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, केन्द्रीय अनुसंधान व विकास प्रयोगशाला, देबारी (राजस्थान)
4. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, सम्पर्क कार्यालय, नई दिल्ली ।
5. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, एन. एच. फरीदाबाद ।
6. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जम्मू प्रचालन कार्यालय, जम्मू ।
7. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, पंजाब-हिमाचल प्रदेश प्रचालन कार्यालय, चण्डीगढ़ ।
8. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, राजस्थान प्रचालन कार्यालय, जयपुर ।
9. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, मध्यप्रदेश प्रचालन-I भोपाल ।
10. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, मध्यप्रदेश प्रचालन-II, जबलपुर ।
11. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, बिहार प्रचालन, पटना ।
12. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, हवाई खनिज सर्वेक्षण व गवेषण, पश्चिमी जोन, जयपुर ।
13. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इंजीनियरी भूविज्ञान प्रभाग-4, देहरादून
14. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, महाराष्ट्र प्रचालन, पूणे ।
15. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, हवाई खनिज सर्वेक्षण, व गवेषण, पूर्वी जोन, रांची ।
16. खनिज गवेषण निगम एरिया कार्यालय, हैदराबाद ।

[सं० ई०-11017/1188-हिंदी]

आर० चन्द्रमोहन, उप सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 24th February, 1989

S.O. 748.—In pursuance of Sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rule, 1976, the Central Government, hereby notify the following Offices under the Department of Mines, Ministry of Steel and Mines, the staff where of have acquired working knowledge of Hindi, for the purposes of the said sub-rule :—

1. The Hindustan Zinc Ltd., Corporate Office, Udaipur.
2. The Hindustan Zinc Ltd., Matoon Mines Office, Mattoon (Rajasthan).
3. The Hindustan Zinc Ltd., Central Research & Development Laboratory, Debari (Rajasthan).
4. The Geological Survey of India, Liaison Office, New Delhi.
5. The Geological Survey of India, N.H., Faridabad.
6. The Geological Survey of India, Operation Jammu, Jammu.
7. The Geological Survey of India, Operation Punjab Himachal Pradesh, Chandigarh.
8. The Geological Survey of India, Rajasthan Operation, Jaipur.

9. The Geological Survey of India, Madhya Pradesh Operation-I, Bhopal.
10. The Geological Survey of India, M.P. Operation-II, Jabalpur.
11. The Geological Survey of India, Bihar operation, Patna.
12. The Airborn Mineral Survey & Exploration, Western Zone, Geological Survey of India, Jaipur.
13. The Geological Survey of India, Engineering Geology Division-4, Dehradun.
14. The Geological Survey of India, Maharashtra Operation, Pune.
15. The Airborn Mineral Survey and Exploration, Eastern Zone, GSI, Ranchi;
16. Mineral Exploration Corporation, Area Office, Hyderabad.

[No. 11017/1/88-Hindi]
R. CHANDRA MOHAN, Dy. Secy.**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1989

का. प्रा. 749—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में डा. ए. के. तिवारी, आयुर्विज्ञान, प्राचार्य, आयुर्विज्ञान संकाय, एम. एस. मेडिकल कॉलेज, रीवा को ए. पी. सिंह विश्वविद्यालय रीवा (मध्य प्रदेश) के कोर्ट द्वारा इस अधिसूचना को जारी किए जाने की तारीख से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया गया है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसरण में भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. प्रा. 138 (सं. 5-13159-एम आई) तारीख 9 जनवरी, 1960 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित शीर्षक के नीचे, क्रम संख्यांक 43 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“43 डा. ए. के. तिवारी,
आयुर्विज्ञान प्राचार्य,
आयुर्विज्ञान संकाय,
एम. एस. मेडिकल कॉलेज,
ए. पी. सिंह, विश्वविद्यालय
रीवा (म. प्र.)

[सं. बी. 11013/41/87 - एम ई (पी)]

आर. श्रीनिवासन, सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 23rd February, 1989

S.O. 749.—Whereas in pursuance of the provision of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) Dr. A. K. Tiwari, Reader in Medicine in the Medical Faculty of S.S. Medical College, Rewa has been elected by the Court of A.P.S. University, Rewa to be a member of the Medical Council of India with effect from the date of issue of this notification.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. S.O.

138 (No. 5-13/59-MI), dated the 9th January, 1960, namely:—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3" for serial number 43 and the entry relating thereto the following serial number and entry shall be substituted, namely:—

"43. Dr. A. K. Tiwari,

Reader in Medicine,
Medical Faculty of S.S. Medical College,
A.P. Singh University,
Rewa (M.P.)."

[No. V. 11013/41/87-ME(P)]

R. SRINIVASAN, Under Secy.

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1989

का. भा. 750—जबकि कलकत्ता गोदी लिपिकीय और पर्यवेक्षीय श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1970 का ड्राफ्ट गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) में यथापेक्षित, भारत सरकार जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. भा. 2631, दिनांक 18 अगस्त, 1988 को भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 3 सितम्बर 1988 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें उससे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से आपत्तियाँ और सुझाव, उक्त अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने और जनता के लिए सुलभ किए जाने की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर आमन्त्रित किए गए थे,

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता के लिए 8 सितम्बर 1988 को सुलभ कर दी गई थी,

और जबकि उक्त ड्राफ्ट पर जनता से प्राप्त आपत्तियाँ और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है, यथा:—

स्कीम

1. (1) इस स्कीम को कलकत्ता गोदी लिपिकीय और पर्यवेक्षीय श्रमिक (रोजगार का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1989 कह कर पुकारा जाएगा।

(2) यह स्कीम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हो जाएगी।

2. कलकत्ता गोदी लिपिकीय और पर्यवेक्षीय श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1970 में:—

(क) वाक्य खंड 6 के अंतर्गत उप वाक्य खंड (1) में—

(i) मद (ख) में "पंजीकृत नियोक्ताओं और" इन शब्दों में को हटा दिया जाए,

(ii) मद (क) में "समायोजित करते हुए" शब्दों को हटा दिया जाए,

(ख) वाक्य खंड 7 में, उप वाक्य खंड (ख) को हटा दिया जाए,

(ग) वाक्य खंड 10 के अंतर्गत उप वाक्य खंड (क) में, "समायोजित करते हुए" इन शब्दों को हटा दिया जाए।

(घ) वाक्य खंड 13 के अंतर्गत उप वाक्य खंड (1) में, मद (ख) के लिए निम्नलिखित मद रखी जाए, यथा:—

"(ख) लाइसेंस के प्रवर्तित रहने के दौरान, वे व्यक्ति जिन्हें कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के समक्ष प्राधिकारी द्वारा स्टैबेडोर के रूप में कार्य

करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है, इस स्कीम के तहत पंजीकृत समझे जाएंगे।"

(ङ) वाक्य खंड 41 में, उप वाक्य खंड (1) के अंतर्गत मद (II) में, उप मद (ख) के अंतर्गत दोनों जगहों पर जहाँ-जहाँ "बोर्ड" शब्द आया है, इसके स्थान पर "अध्यक्ष" शब्द रख दिया जाए,

(च) वाक्य खंड 45 में—

(i) उप वाक्य खंड (2) को हटा दिया जाए,

(ii) उप वाक्य खंड (4) के अंतर्गत "उप वाक्य खंड (1), (2) और (3)" इन शब्दों, ब्रेकेटों और आकड़ों के स्थान पर इन शब्दों, ब्रेकेटों और आकड़ों "उप वाक्य खंड (1) और (3)" को रखा जाए।

[मिसिल सं. एल बी - 13013/9/88 - एल 4]

बी. शंकर लिगम, निदेशक

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

New Delhi, the 24th February, 1989

S.O. 750.—Whereas draft of a scheme to amend the Calcutta Dock Clerical and Supervisory Workers (Regulations of Employment) Scheme, 1970, was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), with the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport No. S.O. 2631, dated the 18th August, 1988 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 3rd September, 1988, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of 45 days from the date on which the said notification as published in the Official Gazette was made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 8th September, 1988;

And whereas objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following Scheme namely:—

SCHEME

1. (1) This Scheme may be called the Calcutta Dock Clerical and Supervisory Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1989.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Calcutta Dock Clerical and Supervisory Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970:—

(a) in clause 6, in sub-clause (1),—

(i) in item (d), the words "registered employers and" shall be omitted;

(ii) in item (e), the word, "adjusting" shall be omitted;

(b) in clause 7, sub-clause (b) shall be omitted;

(c) in clause 10, in sub-clause (a), the word "adjusting" shall be omitted;

(d) in clause 13, in sub-clause (1), for item (b), the following item shall be substituted, namely:—

"(b) persons who have licenced to function as stevedores by the competent authority of Calcutta Port Trust shall be deemed to have been registered under the Scheme during the currency of the licence."

(e) in clause 41, in sub-clause (1), in item (ii), in sub-item (b), for the word "Board" at both the places where it occurs, the word "Chairman" shall be substituted;

(f) In clause 45,—

(i) sub-clause (2) shall be omitted;

(ii) in sub-clause (4), for the words, brackets, and figures "sub-clauses (1), (2) and (3)", the words brackets and figures "Sub-clause: (1) and (3)" shall be substituted.

[File No. LB-13013/9/88-LIV]

V. SANKARALINGAM, Director

(नीवहन पक्ष)

भारत

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1989

का. आ. 751.—वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44वाँ) की धारा 3 की क्लॉस (32) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कांडला, कोचीन, नव मंगलूर, मुरमुगाव टूटीकोरिन विशाखापत्तनम तथा पारावीप पत्तनों के उप संरक्षकों को 1 मार्च, 1989 से पत्तनों पर उक्त अधिनियम की धारा 443 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए "उपयुक्त अधिकारी" मनोनीत करती है।

[फा. सं. एस डब्ल्यू/13एमएमएल - (4)/85एमए]

राम सनेही, अवर सचिव

(Shipping Wing)

ORDER

New Delhi, the 23rd February, 1989

S.O. 751.—In pursuance of clause (32) of section 3 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby designates with effect from the 1st day of March, 1989 the Deputy Conservators of each of the Ports of Bombay, Calcutta, Madras, Kandla, Cochin, New Mangalore, Marmugao, Tuticorin, Visakhapatnam and Paradip, to be the "proper Officer" at that port for the purposes of sub-section (2) of section 443 of the said Act.

[F. No. SW/13-MSL(4)/85-MA]

RAM SANEHI, Under Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1989

का. आ. 752.—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुसरण में रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड दक्षिण मध्य और उत्तर रेलवे के लिम्नलिखित कार्यालयों/स्टेशनों को, जहाँ के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करता है—
दक्षिण - मध्य रेलवे

1. मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय, लालागुडा
उत्तर रेलवे

दिल्ली मंडल

1. तरधाना
2. यानेसर शहर
3. साजूगा

4. डीजल गेज शक्करखली
5. बरि. बिजली फोरमैन (पावर) नई दिल्ली
6. भिवानी (फैरिज फोरमैन एवं बिजली)
7. पिछारसी
8. पाड़ू पिछारा
9. सिवाहा
10. पिन्डू खेड़ा
11. बुडवा खेड़ा
12. मणीदों
13. कर सिधू
14. मडलोडा
15. आसन
16. भिवानी सिटी
17. वामला
18. कलानीर कलां
19. मकरीनी
20. लाहौरी
21. जसिया
22. भेसवा
23. गोहाता
24. इसराना
25. मुडलाना
26. नौथाया
27. अस्थान बोहर
28. समर गोपालपुर
29. करेठी
30. किलां जफरगढ़
31. जुलाना
32. जय जय बंसी
31. किलाना
34. बिशनपुरा हरियाणा
35. बरमोला
36. उबाना
37. घासी
38. घमसान साहिब
39. टोहाना
40. हिम्मतपुरा
41. खरेटा
42. कोट फतेह
43. बगोदां जटा
44. हीन्ड
45. रामपुर मनिहारन
46. नोली
47. कामिमपुर खेड़ी

[सं. हिन्दी-89/रा. भा. 1/12/89]

एस. एम. शैल, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं पर्यटन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 24th February, 1989

S.O. 752.—In pursuance of sub-rule (2) and (4) of Rule 10 of the Official Languages (User for the Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Ministry of Railways (Railway Board), hereby notify the following offices/stations of South Central Railway and Northern Railway, where the staff have acquired the working knowledge of Hindi :—

SOUTH CENTRAL RAILWAY

1. Office of Chief Works Manager, Lalguda

NORTHERN RAILWAY

DELHI DIVISION

1. Narwana
2. Thaneswar City
3. Sajuma
4. Diesel Shed, Shakurbasti.
5. Senior Electrical Foreman (Power), New Delhi.
6. Bhiwani (Carriage Foreman and Electrical)
7. Pindarsi
8. Pandu Pindara.
9. Siwaha
10. Pilo Khara
11. Buddha Khara
12. Safidon
13. Karsindhu
14. Madloda
15. Asan
16. Bhiwani City
17. Wamala
18. Kalanaur Kalan
19. Makrauli
20. Lahall
21. Jasla
22. Bhaishawa
23. Gohana
24. Isarana
25. Mudlana
26. Naotya
27. Asthan Bohar
28. Samar Gopalpur
29. Karethi
30. Kila Zafargarh
31. Julana
32. Jai Jaibanti
33. Kinana
34. Bishanpura Haryana
35. Barsola
36. Uchana
37. Dhaso
38. Dhamtan Saljib
39. Tohana
40. Himmatpura
41. Bareta
42. Kot Fateh
43. Bazida Jata
44. Heend
45. Rampur Maniharan
46. Noli
47. Kasimpur Khedi

[No. Hindi-89/OI-I/12/2]

S. M. VAISH, Secy.
Railway Board and Ex-officio
Jt. Secy.

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1989

का. आ. 753 :—पूणिया टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र में बदली किए जाने के बावजूद जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है एक सर्वसाधारण सूचना उन सब की जानकारी के लिए जैसा कि भारतीय तार नियमावली, 1951 के नियम 434 (III) (2 ग) में अर्पित है, पूणिया में चालू समाचार पत्रों में निकाली गयी थी और उनसे कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हें कोई आपत्ति हो या उनके कोई सुझाव हों तो वे इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजने का कष्ट करें।

और यः उक्त सूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 5 दिसम्बर, 1988 के "आज" और "द टाइम्स आफ इंडिया" तथा 6 दिसम्बर, 1988 के "हिन्दुस्तान" और 3 फरवरी, 1989 के "हिन्दुस्तान" समाचार पत्र में शुद्धि पत्र के रूप में प्रकाशित कराई गई थी ;

और यतः उक्त सूचना के उत्तर में जनसाधारण से कोई आपत्ति या और सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

इसलिए अब उक्त नियमावली के नियम 434 (III) (2 ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, दूरसंचार एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि तारीख 16-4-89 में पूणिया टेलीफोन प्रणाली का संशोधन स्थानीय क्षेत्र इस प्रकार होगा :—

पूणिया टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली :—

पूणिया टेलीफोन प्रणाली का स्थानीय क्षेत्र बड़ा होगा जो कि पूणिया नगरपालिका क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पड़ता है,

किन्तु वे टेलीफोन उपभोक्ता जो कि पूणिया नगर पालिका सीमा के बाहर स्थित हैं किन्तु जिन्हें पूणिया टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली से सेवा प्रदान होनी है और जब तक वे इस प्रणाली के किसी भी एक्सचेंज से 5 कि. मी. दूरी के भीतर स्थित रहेंगे और इस प्रणाली से जुड़े रहेंगे तब तक स्थानीय शुल्क दर से श्रद्धांगी करते रहेंगे।

[सं. 3/2/88 पी एच. बी]

प्रद्योत कुमार, निदेशक फोन (ई)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Telecommunications Board)

New Delhi, the 28th March, 1989

S.O. 753.—Whereas a public notice for revising the local area of Purnea Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III)(2C) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Purnea, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers ;

And whereas the said notice was made available to the public on 5-12-1988 in 'Aaj' and 'The Times of India', on 6-12-1988 in 'Hindustan' and corrigendum on 3-2-1989 in 'Hindustan' Newspapers ;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434(III)(2C) of the said Rules, the Director General, Telecommunications hereby declares that with effect from 16-4-89,

the revised local area of Purnea Telephone System shall be as under :

Purnea Telephone Exchange System :

The local area of Purnea Telephone System shall cover an area under the jurisdiction of Purnea Municipality, Provided that the telephone subscribers located outside the Purnea Municipal limits but who are served from Purnea Telephone System will continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 kms of any exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-2/88-PHB]

PRADEEP KUMAR, Director Phones (E)

असम मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1989

का.आ. 754.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1-3-89 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्

राजस्व ग्राम का नाम या नगरपालिका	होबली	तालुक	जिला
मारेनाहल्ली	उडाराहल्ली	बंगलोर	बंगलोर
नयाप्पा सेट्टी पालया	बेगूर	बंगलोर	बंगलोर

[संख्या: एस-38013/3/89-एस.एस.-1]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 27th February, 1989

S.O. 754.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st March, 1989 as the date on which the provision of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Karnataka namely :

Name of the revenue Village of Municipal Limit	Hobli	Taluk	District
Marenahally	Uttarahally	Bangalore	Bangalore
Nayappa Setty Palaya	Begur	Bangalore	Bangalore

[No. S-38013/3/89-SS.I]

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1989

का.आ. 755.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 16-3-1989 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय

4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्—

“जिला कूजहार में तहसील बारागाव के आधीन राजस्व ग्राम ब्रह्मनापाल के अन्तर्गत अपने वाले क्षेत्र”

[संख्या एस 38013(4)89-एस एस -1]

New Delhi, the 6th March, 1989

S.O. 755.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 16th March, 1989 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Orissa namely :

“Area within the revenue village of Brahmanpal under the Tehsil Ghatgaon in the District Keenjhar”.

[No. S-38013/4/89-SS.I]

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1989

का.आ. 756.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 16 मार्च, 1989 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध हरियाणा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्—

क्रम सं.	क्षेत्र का नाम	हव.बस्त संख्या	जिला
1	सात रोड कला	153	हिसार
2	मयड़	151	हिसार

[संख्या एस-38013(5)89-एस.एस.-I]

New Delhi, the 7th March, 1989

S.O. 756.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 16th March, 1989 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Haryana namely :

S.No.	Name of the Area	Had Bast No.	District
1.	Sat Road Kalan	153	Hissar
2.	Mayar	151	Hissar.

[No. S-38013/5/89-SS.I]

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1989

का. प्रा. 757.—यह: मैसर्स कनकास्टा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 47-48 जोली सेक्टर, जेम्सर्स II नारीमनपुइंट, बम्बई-400021 और इसकी अजमेरपुर तथा दिल्ली स्थित शाखाएँ।

(इसके अंग्रेज़ी अर्थों की उक्त स्थापना शब्द का प्रयोग हो इससे अधिप्राय उक्त स्थापना से है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (इसके अंग्रेज़ी अर्थों अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट को) धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है।

यह केन्द्र सरकार की राय में उक्त स्थापना के कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए भविष्य निधि नियमों में अंगदान की दर उक्त अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित कर्मचारी अंगदान की दर से कम नहीं है तथा इसके कर्मचारियों को मिलने वाले भविष्य निधि लाभ उक्त अधिनियम तथा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 (इसके अंग्रेज़ी अर्थों की स्कीम शब्द का प्रयोग किया गया है) उक्त अधिनियम से है) में उल्लिखित लाभों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है जो इस वर्ग की स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध है।

अब हमलिये उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा एक के खंड (क) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और संलग्न अनुसूची में वर्णित शर्तों के अधीन केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उक्त स्थापना को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों को लागू होने से छूट प्रदान करती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना ने संबंधित नियोक्ता केन्द्र सरकार के द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देश के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) में उल्लिखित निरीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसे निरीक्षण प्रसार की अदायगी प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर करेगा।

2. न-छूट प्राप्त स्थापनाओं के संबंध में उक्त अधिनियम और उसके अधीन सृजित उक्त स्कीम के अन्तर्गत देय अंगदान के दर से स्थापना के भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत देय अंगदान की दर किसी समय भी कम न होगा।

3. पेशगियों के मामले में छूट प्राप्त स्थापना की स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 से कम हितकर नहीं होगी।

4. उक्त स्कीम में कोई भी संशोधन जो स्थापना के वर्तमान नियमों से अधिक लाभकारी है उन पर अपने आप लागू किया जाएगा। उक्त स्थापना के भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से उक्त स्थापना के कर्मचारियों के हित के प्रतिकूल प्रभाव होने की सम्भावना है वहाँ अपनी अनुमति देने से पूर्व, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का उचित अवसर देगा।

5. यदि स्थापना को छूट न दी जाती तो वे सभी कर्मचारी (जैसे उक्त अधिनियम की धारा 2(ब) में निश्चित किया गया है) जो सदस्य बनने के पात्र होने, सदस्य बनाए जाएंगे।

6. जहाँ एक कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि (कानूनी) या किसी अन्य छूटप्राप्त स्थापना को पहले से सदस्य है, को अपनी स्थापना में काम पर लगाया जाता है तो नियोक्ता उसे निधि का सुरक्षित सदस्य

काएगा और ऐसे कर्मचारी के पिछले नियोक्ता के पास भविष्य निधि लेख में संघर्षों को अन्तर्गत कराने और उसके लेख में जमा कराने की व्यवस्था करेगा।

7. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार के द्वारा जैसे भी मामला हो, समय समय पर किए गए निर्देशों के अनुसार भविष्य निधि के प्रबन्ध के लिए नियोक्ता न्यासी बोर्ड की स्थापना करेगा।

8. भविष्य निधि, न्यासी बोर्ड में निर्दिष्ट होगा जो अन्य बातों के होते हुए भविष्य निधि में आय के उचित लेखों और भविष्य निधि से अदायगियों और उनकी अभिरक्षा में शोषों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उत्तरदायी होगा।

9. न्यासी बोर्ड कम से कम 3 माह में एक बार बैठक करेंगे और केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को अधिकार होगा कि वह किसी अन्य योग्य लेखा परीक्षक से खातों को दुबारा लेखा परीक्षा कराए और ऐसे पुनः लेखा-परीक्षा के खर्च नियोक्ता वहन करेगा।

10. न्यासी बोर्ड द्वारा रखे गए भविष्य निधि लेख अर्हता प्राप्त निष्पक्ष चाटेर्ड अकाउंटेंट द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा के अधधीन होंगे। जहाँ आवश्यक समझा जाए, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किसी अन्य अर्हता प्राप्त लेखा-परीक्षक द्वारा लेखों की पुनः लेखा परीक्षा कराने का अधिकार होगा और इस पर हुआ व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

11. प्रत्येक वर्ष स्थापना के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के साथ लेखा-परीक्षित वार्षिक भविष्य निधि लेखों की एक प्रति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए भविष्य निधि का वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

12. नियोक्ता प्रतिमाह भविष्य निधि के देय अपने कर्मचारियों के अंगदानों की आगामी माह की 15 तारीख तक न्यासी बोर्ड को अंतरित कर देगा। अंगदानों की विलम्ब से अदायगी करने के लिए समान परिस्थितियों में नियोक्ता नुकशानी देने का उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जिस प्रकार एक न-छूट प्राप्त स्थापना उत्तरदायी होती है।

13. न्यासी बोर्ड सरकार द्वारा समय समय दिए गए निर्देशों के अनुसार निधि में जमा राशियों का निवेश करेगा। प्रतिवृत्तियां न्यासी बोर्ड के नाम पर प्राप्त की जाएगी और भारतीय रिजर्व बैंक के जमा नियन्त्रण में अनुसूचित बैंक की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

14. सरकार के निर्देशों के अनुसार निवेश न करने पर न्यासी बोर्ड अलग-अलग रूप से और एक साथ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके प्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए अधिक प्रचार का उत्तरदायी होगा।

15. न्यासी बोर्ड एक वस्तु-व्योरा रजिस्टर तैयार करेगा और ब्याज और विमोचन आय को समय पर वसूली सुनिश्चित करेगा।

16. जमा किए गए अंगदानों निकाले गए और प्रत्येक कर्मचारी ने संबंधित ब्याज को दिखाने के लिए न्यासी बोर्ड विस्तृत लेख तैयार करेगा।

17. वित्तीय/लेखा वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण जारी करेगा।

18. बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण के स्थापन पर पामबुक जारी कर सकता है। ये पामबुक कर्मचारियों की अभिरक्षा में रहेगी और कर्मचारियों के प्रस्तुतीकरण पर बोर्ड के द्वारा इन्हे अद्यतन किया जाएगा।

19. लेखा वर्ष के पहले दिन आदि शेष पर प्रत्येक कर्मचारी के लेख में ब्याज उस दर से जमा किया जाएगा जिसका न्यासी बोर्ड निर्णय करे परन्तु यह उक्त स्कीम के पैरा 60 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट दर से कम नहीं होगा।

20. यदि नियोक्ता किंवा केंद्रगत प्रत्येक अन्य शोषित श्रमिक को दर इस कारण से कि निवेश पर अथवा काम है या किसी अन्य कारण से अर्थात् परन्तु में असमर्थ है तो इस कमी को निराकरण पूर्ण करेगा।

21. नियोजित भविष्य निधि की चोरी के कारण, लुप्तप्रसन्नतय तत्, गवत श्रमिकों किंवा अन्य कारण से हुई हानि को पूर्ण करेगा।

22. नियोजित और न्यूसी बोर्ड, क्षेत्रीय भविष्य निधि प्रयुक्त को ऐसी विवरणों प्रस्तुत करेगा जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि अथवा निर्धारित करें।

23. उक्त स्कीम के पैरा 69 की शर्तों पर किसी कर्षक की निधि के सदस्य न रहने पर यदि स्थापन के भविष्य निधि नियमों में नियोजितों के अंशदानों को जप्त करने की व्यवस्था है तो न्यूसी बोर्ड इस प्रकार जप्त को गई राशि का अलग से लेखा तैयार करेगा और उसे ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि प्रयुक्त की पूर्व अनुमति से सौंपित किया गया हो।

24. स्थापन के भविष्य निधि नियमों में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि किसी स्थापन को सेवा निवृत्ति होने के फलस्वरूप या किसी अन्य प्रसिद्धांत में लौटने पर निधि की सदस्यता समाप्त हो जाती है यह पता लगता है कि प्रसिद्धांत के भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अंशदान की दर समग्रण की दर यदि गैरस्थितिक योजना के अन्तर्गत दी गई दरों की तुलना में कम अनुकूल है तो अन्तर का वृद्धि नियोजित द्वारा किया जाएगा।

25. नियोजित, भविष्य निधि के प्रणयन से संबंधित सभी खर्चों जिसमें लेखों के रखरखाव रिटर्न प्रस्तुत किए जाने, रणियों के अन्तर्गत शामिल है, वहन करेगा।

26. नियोजित समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों की एक प्रति तथा जब भी कोई संशोधन होता है, उसकी मुख्य बातों को न्यूसी रणियों के बहुमत की सभा में अन्तर्गत करके स्थापन के बोर्ड पर समाप्त।

27. "समुचित सरकार" स्थापन की चालू छूट पर और जहाँ लगाने वाली है।

28. यदि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्थापन वर्ग जिसमें उसकी स्थापना आती है, पर अंशदान की दर बढ़ाई जाती है, नियोजित भविष्य निधि अंशदान की दर उचित रूप से बढ़ाएगा, ताकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दिए जाने वाले लाभों से स्थापन की स्कीम के अन्तर्गत किए जाने वाले भविष्य निधि के लाभ किसी भी प्रकार से कम न हों।

29. उक्त शर्तों में से किसी एक के उल्लंघन पर छूट रद्द की जा सकती है।

[संख्या एम्-35015(5)/89-गो मु-2]

New Delhi, the 8th March, 1989

S.O. 757.—Whereas Messrs Concast India Private Limited, 47-48, Jolly Maker Chambers-II, Nariman Point, Bombay 400021, with its branches at Jamshedpur and New Delhi (hereinafter referred to as the said establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas in the opinion of the Central Government the rules of the Provident Fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees than the benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds

Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme) in relation to the employees in any other establishment of a similar character;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of said Act within 15 days from the close of every month.

2. The rate of contribution payable under the provident fund rules of the establishment shall at no time be lower than those payable under the said Act in respect of the unexempted establishments and the said Scheme framed thereunder.

3. In the matter of advances, the scheme of the exempted establishment shall not be less favourable than the Employees Provident Scheme, 1952.

4. Any amendment to the said scheme this is more beneficial to the employees than the existing rules of the establishment shall be made applicable to them automatically no amendment of the rules of the provident fund of the said establishment shall be made without the previous approval of the Regional Provident Fund Commissioner and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees of the said establishment, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

5. All employees [as defined in section 2(f) of the said Act] who would have been eligible to become members of the Provident Fund had the establishment not been granted exemption shall be enrolled as members.

6. Where an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund (Statutory) or a Provident Fund of any other exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the fund and arrange to have the accumulations in the provident fund account of such employee with his previous employer transferred and credited to his account.

7. The employer shall establish a Board of Trustees for the management of the provident fund according to such directions as may be given by the Central Provident Fund Commissioner or by the Central Government, as the case may be, from time to time.

8. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will be responsible for and accountable to the Employees' Provident Fund Organisation inter-alia for proper accounts of the receipts into and payments from the Provident Fund and the balance in their custody.

9. The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner or an officer authorised by him.

10. The accounts of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified independent Chartered Accountant annually. Where considered necessary the Central Provident Fund Commissioner shall have the right to have the accounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.

11. A copy of the audited annual provident fund accounts together with the audited balance sheet of the establishment for each accounting year shall be submitted to the Regional Provident Fund Commissioner, within six months after the close of financial year. For this purpose the financial year of the provident fund shall be from the 1st April to the 31st of March.

12. The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the Provident Fund by himself and the employees by the 15th of each month following the month for which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay damages to the Board of Trustees for any delay in payment of the contributions in the same manner as an un-exempted establishment is liable under similar circumstances.

13. The Board of Trustees shall invest the monies in the fund as per directions that may be given by the Government from time to time. The securities shall be obtained in the name of the Board of Trustees and shall be kept in the custody of a Schedules Bank under the Credit Central of the Reserve Bank of India.

14. Failure to make the investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees severally and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his representative.

15. The Board of Trustees shall maintain a serial-wise register and ensure timely realisation of interest and ensure timely realisation of interest and redemption of proceeds.

16. The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited, withdrawal and interest in respect of each employee.

17. The Board shall issue an annual statement of account to every employee within six months of the close of financial accounting year.

18. The Board may, instead of the annual statement of accounts, issue pass books to every employee. These pass books shall remain in the custody of the employees and will be brought up to date by the Board on presentation by the employees.

19. The account of each employee shall be credited interest calculated on the opening balance as on the 1st day of the accounting year at such date may be decided by the Board of Trustees but shall not be lower than the rate declared by the Central Government under para 60 of the said Scheme.

20. If the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Central Government for the reason that the return on investment is less or for any other reason, than the deficiency shall be made good by the employer.

21. The employer shall also make good any other loss that may be caused to the Provident Fund due to theft, burglary, defalcation, misappropriation or any other reason.

22. The employer as well as the Board of Trustees shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner as the Central Government/Central Provident Fund Commissioner may prescribe from time to time.

23. If the Provident Fund rules of the establishment provide for forfeiture of the employers' contribution in cases where an employee ceases to be a member of the fund on the lines of para 69 of the said Scheme, the Board of Trustees shall maintain a separate account of the amounts so forfeited and may utilise the same for such purposes as may be determined with the prior approval of the Central Provident Fund Commissioner.

24. Notwithstanding anything contained in the provident fund rules of the establishment, if on the cessation of any individual, from the membership of the fund consequent on retiring from service or on taking up the employment in

some other establishment, it is found that the rate of contribution, rate of forfeiture etc. under the provident fund rules of the establishment are less favourable as compared to those under the statutory scheme, the difference shall be borne by the employer.

25. The employer shall bear all the expenses of the administration of the Provident Fund including the maintenance of Accounts, submission of returns, transfer of accumulations.

26. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the fund as approved by the appropriate authority and as and when amended thereto alongwith a translation of the silent points thereof in the language of the majority of the employees.

27. The "appropriate Government" may lay down any further conditions for contained exemption of the establishment.

28. The employee shall enhance the rate of provident fund contributions appropriately if the rate of provident fund contribution for the class of establishment in which his establishment falls is enhanced under the said Act so that the benefits under the Provident Fund Scheme of the establishment shall not become less favourable than the benefits provided under the said Act.

29. The exemption is liable to be cancelled for violation of any of the above conditions.

[No. S-35015(5)/89-SS-II]

कां० अ० 558.—यन: पैसमं टाटा एक्स्पॉर्ट लिमिटेड, बलक-गण्डिवसगर स्टेट, डाक्टर ऐनीबेसेंट रोड बर्ली, बम्बई-400018 और इरकी बलबसा दिवली तथा देवाम स्थित शाखाएं (इसके शागे जहां कहीं भी उक्त स्थापना शब्द का प्रयोग हो इससे अभिप्राय उक्त स्थापना से है) ने कर्मचारी अधिपत्य विधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (इसके शागे उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट) को धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है।

यह केंद्र सरकार की राय में उक्त स्थापना के कर्मचारी के लिए तैयार किए गए अधिपत्य विधि नियमों में अंशदान की दर उक्त अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित कर्मचारी अंशदान की दर से कम नहीं है तथा इसके कार्यवाहियों को मिलने वाले अधिपत्य विधि लाभ उक्त अधिनियम तथा कर्मचारी अधिपत्य विधि स्कीम, 1952 (इसके शागे जहां कहीं भी स्कीम शब्द का प्रयोग किया गया है उससे अभिप्राय उक्त स्कीम से है) में उल्लिखित लाभों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है इस वर्ग की स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उपबंध है।

अब इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा एक के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संलग्न अनुसूची में वर्णित शर्तों के अधीन केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उक्त स्थापना को उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के लागू होने से 1 दिसम्बर, 1986 से छूट प्रदान करती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना से सम्बन्धित नियोजना केंद्र सरकार के द्वारा समय दिए गए निर्देश के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) में उल्लिखित निरीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसे निरीक्षण प्रभाव की अवयवी प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर करेगा।

2. न-छूट प्राप्त स्थापनाओं के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम और उसके अधीन स्तित उक्त स्कीम के अंतर्गत देय अंशदान के दर से स्थापना के अधिपत्य विधि नियमों के अर्थात् 1 से 10 तक के दर किसी समय भी कम न होगा।

3. योजनाओं के सफल में छूट प्राप्त स्थापना की स्वीक कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1932 से कम हितकर नहीं होगी।

4. उक्त स्कीम में कोई भी संशोधन जो स्थापना के वर्तमान नियमों से अधिक लाभकारी है उन पर अपने आप लागू किया जाएगा। उक्त स्थापना के वर्तमान विधि नियमों में कोई भी संशोधन, जैसी भविष्य विधि आयुक्त की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से उक्त स्थापना के कर्मचारियों के हित के अधिकृत प्रभावी होने को सम्भावना है जहाँ अपनी अनुमति देने से पूर्व, जैसी भविष्य विधि आयुक्त, कर्मचारियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का उचित अवसर होगा।

यदि स्थापना को छूट न दी जाती तो वे सभी कर्मचारी (जैसे उक्त अधिनियम की धारा 2 (ज) में निश्चित किया गया है) जो सदस्य बनने के लिए होते, सदस्य ब्राह्मण जाएंगे।

6. जहाँ एक कर्मचारी भविष्य निधि (कानूनी) से विरक्त अन्य छूट प्राप्त स्थापना का पहले से सदस्य है, को अपनी स्थापना में कम पर लगाया जाता है तो नियोजता उसे निधि का मुक्त सदस्य बनाएगा और ऐसे कर्मचारी के विद्यते नियोजता के पास भविष्य निधि लेख में संतुष्टों को अंतरित करने और उसके लेख में जमा कराने की व्यवस्था करेगा।

7. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार के द्वारा जैसे भी मामला हो, समय समय पर दिए गए विवेकों के अनुसार भविष्य निधि के प्रबंध के लिए नियोजता न्यासी बोर्ड की स्थापना करेगा।

8. भविष्य निधि, न्यासी बोर्ड ने निर्दिष्ट होगा जो अन्य बातों के होने हुए भविष्य निधि में आय के उचित लेखों और भविष्य निधि से आवश्यकियों और उनकी अभिरक्षा में शेषों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को उत्तरदायी होगा।

9. न्यासी बोर्ड कम से कम 3 माह में एक बार बैठक करने और केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए मार्ग दिशियों के अनुसार कार्य करेगा। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को अधिकार होगा कि वह किसी अन्य योग्य लेखा परीक्षक से खाता को दुबारा लेखा परीक्षा कराने और पुनः लेखा-परीक्षा के खर्च नियोजता वहन करेगा।

10. न्यासी बोर्ड द्वारा रखे गए भविष्य निधि लेखे ग्रहण प्राप्त निष्पक्ष चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा की अध्यक्षता होगी। जहाँ आवश्यक सहायता प्राप्त केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किसी अन्य ग्रहण प्राप्त लेखा-परीक्षक द्वारा लेखों की पुनः लेखा परीक्षा कराने का अधिकार होगा और उस पर बुद्धि व्यय नियोजता द्वारा वहन किया जाएगा।

11. प्रत्येक वर्ष स्थापना के लेखा परीक्षित तुल्य-पत्र के साथ लेखा-परीक्षित वार्षिक भविष्य निधि लेखों की एक प्रति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छ. माह के अन्तर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए भविष्य निधि का वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

12. नियोजता प्रतिमाह भविष्य निधि के देय अपने कर्मचारियों के संशदाता की आगामी माह की 15 तारीख तक न्यासी बोर्ड को अंतरित कर देगा। संशदाता की विलम्ब से आवासी करने के लिए समान परिस्थितियों में नियोजता मुकदमा देने का उनी प्रकार उत्तरदायी होगा जिस प्रकार एक छूट प्राप्त स्थापना उत्तरदायी होती है।

13. न्यासी बोर्ड सरकार द्वारा समय समय दिए गए विवेकों के अनुसार निधि में जमा राशियों का निवेदन करेगा। प्रतिभूतियाँ न्यासी बोर्ड के नाम पर प्राप्त की जाएगी और भारतीय रिजर्व बैंक के जमा नियन्त्रण में अनुमूचित बैंक की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

14. सरकार के निर्देशों के अनुसार निवेश न करने पर न्यासी बोर्ड समय-समय रूप से और एक मात्र केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके प्रतिनिधियों द्वारा समायुक्त अधिक प्रभार का उत्तरदायी होगा।

15. न्यासी बोर्ड एक वस्तु-व्योता रजिस्टर तैयार करेगा और बराबर और विमोक्षण आय को समय पर वस्तु-व्योता मुनिष्ठित करेगा।

16. जहाँ किए गए संशदाता, निदाने गए और प्रत्येक कर्मचारी से संबंधित बराबर को दिखाने के लिए न्यासी बोर्ड विस्तृत लेख तैयार करेगा।

17. वित्तीय/लेखा वर्ष की समाप्ति के छ माह के पन्द्र बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण जारी करेगा।

18. बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण के स्थान पर पामयुक्त जारी कर सकता है। ये पाम-युक्त कर्मचारियों की अभिरक्षा में रहेगी और कर्मचारियों के प्रत्युत्कीकरण पर बोर्ड के द्वारा इन्हें प्रस्तुत किया जाएगा।

19. लेखा वर्ष के पहले दिन आदि गेय पर प्रत्येक कर्मचारी के लेख में व्यक्त उस दर में जमा किया जाएगा जिसका न्यासी बोर्ड निर्णय करे परन्तु यह उक्त स्कीम के पैरा 60 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित दर में कम नहीं होगा।

20. यदि न्यासी बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित बराबर की दर इस कारण से कि निवेश पर आय कम है या किसी अन्य कारण से असा करने में असमर्थ है तो इस कमी को नियोजता पूरा करेगा।

21. नियोजता भविष्य निधि की चोरी के कारण नुकसानोत्पत्ति, यद्यपि अथवा किसी अन्य कारण से हुई हानि को पूरा करेगा।

22. नियोजता और न्यासी बोर्ड केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त निर्धारित करें।

23. उक्त स्कीम के पैरा 69 की शैली पर किसी कर्मचारी को निधि के सदस्य न रहने पर यदि स्थापना के भविष्य निधि नियमों में नियोजताओं के संशदाताओं को जन्म करने की व्यवस्था है तो न्यासी बोर्ड इस प्रकार जन्म की गई राशियों का अलग से लेखा तैयार करेगा और ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को पूर्व अनुमति से मुनिष्ठित किया गया हो।

24. स्थापना के भविष्य निधि नियमों में निर्दिष्ट किसी बात के होने हुए भी यदि किसी व्यक्ति की सेवा निवृत्ति होने के फलस्वरूप या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नौकरी करने पर निधि की सदस्यता समाप्त हो जाती है यह पता लगता है कि प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत संशदाता की दर समग्रहण की दर आदि संबंधित योजना के अन्तर्गत की गई दरों को तुलना में कम अनुकुल है तो अन्तर का वहन नियोजता द्वारा किया जाएगा।

25. नियोजता भविष्य निधि के प्रणालय में संबंधित सभी खर्च जिसमें लेखों के रख-रखाव रिटर्न प्रस्तुत किए जाने, राशियों का अन्तरण शामिल है, वहन करेगा।

26. नियोजता समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों की एक प्रति तथा जब भी कोई संशोधन होता है उसकी मुख्य बातों को कर्मचारियों के वृद्धत की भाषा में अनुवाद करके स्थापना के बोर्ड पर लगाएगा।

27. "समुचित सरकार" स्थापना की बाबू छूट पर और शर्तें असा सकती है।

28. यदि उक्त अधिनियम के अंतर्गत स्थापना वर्ष जिसमें उक्त स्थापना आती है पर संशदाता की दर बढ़ाई जाती है नियोजता भविष्य

निधि अधिदान की वर उचित रूप में बढ़ावा ताकि उक्त अधिनिधि क द्रव्यगत दिग् जान बाले यार्थों से स्थापना की स्कीम क संशोधन दिग् जान बाले भविष्य निधि के लाभ किसी भी प्रकार से कम न हों।

29. उक्त शर्तों में से किसी एक के उल्लंघन पर दूट रुद्ध की जा सकती है।

[संख्या एस-35015 (4)/89-गो मु-2]

गो. क. भट्टराय, प्रवर सचिव

S.O. 758.—Whereas Messrs Tata Exports Limited, Block A, Shiv Sagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400018, with its branches at Calcutta, Delhi and Dewas (hereinafter referred to as the said establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas in the opinion of the Central Government the rules of the Provident Fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees than the benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme) in relation to the employees in any other establishment of a similar character;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 1st December, 1986.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of said Act within 15 days from the close of every month.

2. The rate of contribution payable under the provident fund rules of the establishment shall at no time be lower than those payable under the said Act in respect of the unexempted establishments and the said Scheme framed thereunder.

3. In the matter of advances, the scheme of the exempted establishment shall not be less favourable than the Employees Provident Fund Scheme, 1952.

4. Any amendment to the said scheme this is more beneficial to the employees than the existing rules of the establishment shall be made applicable to them automatically no amendment of the rules of the provident fund of the said establishment shall be made without the previous approval of the Regional Provident Fund Commissioner and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees of the said establishment, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

5. All employees (as defined in section 2(i) of the said Act, who would have been eligible to become members of the Provident Fund had the establishment not been granted exemption shall be enrolled as members.

6. Where an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund (Statutory) or a Provident Fund of any other exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the fund and arrange to have the accumulations in the provident fund account of such employee with

his previous employer transferred and credited to his account.

7. The employer shall establish a Board of Trustees for the management of the provident fund according to such directions as may be given by the Central Provident Fund Commissioner or by the Central Government, as the case may be, from time to time.

8. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will be responsible for and accountable to the Employees' Provident Fund Organisation inter-alia for proper accounts of the receipts into and payments from the Provident Fund and the balance in their custody.

9. The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner or an officer authorised by him.

10. The accounts of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified independent Chartered Accountant annually. Where considered necessary, the Central Provident Fund Commissioner shall have the right to have the accounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.

11. A copy of the audited annual provident fund accounts together with the audited balance sheet of the establishment for each accounting year shall be submitted to the Regional Provident Fund Commissioner within six months after the close of the financial year. For this purpose the financial year of the provident fund shall be from the 1st April to the 31st March.

12. The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the Provident Fund by himself and the employees by the 15th of each month following the month for which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay damages to the Board of Trustees for any delay in payment of the contributions in the same manner as an un-exempted establishment is liable under similar circumstances.

13. The Board of Trustees shall invest the monies in the fund as per directions that may be given by the Government from time to time. The securities shall be obtained in the name of the Board of Trustees and shall be kept in the custody of a Scheduled Bank under the Credit Central of the Reserve Bank of India.

14. Failure to make the investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees severally and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his representative.

15. The Board of Trustees shall maintain a scriat-wise register and ensure timely realisation of interest and ensure timely realisation of interest and redemption of proceeds.

16. The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited, withdrawal and interest in respect of each employee.

17. The Board shall issue an annual statement of account to every employee within six months of the close of financial accounting year.

18. The Board may, instead of the annual statement of accounts, issue pass books to every employee. These pass books shall remain in the custody of the employees and will be brought up to date by the Board on presentation by the employees.

19. The account of each employee shall be credited interest calculated on the opening balance as on the 1st day of the accounting year at such rate may be decided by the Board of Trustees but shall not be lower than the rate declared by the Central Government under para 60 of the said Scheme.

20. If the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Central Government for the reason that the return on investment is less or for any other reason, than the deficiency shall be made good by the employer.

21. The employer shall also make good any other loss that may be caused to the Provident Fund due to theft, burglary, defalcation, mis-appropriation or any other reason.

22. The employer as well as the Board of Trustees shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner as the Central Government/Central Provident Fund Commissioner may prescribe from time to time.

23. If the Provident Fund rules of the establishment provide for forfeiture of the employer's contribution in cases where an employee ceases to be a member of the fund on the lines of para 69 of the said Scheme, the Board of Trustees shall maintain a separate account of the amounts so forfeited and may utilise the same for such purposes as may be determined with the prior approval of the Central Provident Fund Commissioner.

24. Notwithstanding anything contained in the provident fund rules of the establishment, if on the cessation of any individual, from the membership of the fund consequent on retiring from service or on taking up the employment in some other establishment, it is found that the rate of contribution, rate of forfeiture etc. under the provident fund rules of the establishment are less favourable as compared to those under the statutory scheme, the difference shall be borne by the employer.

25. The employer shall bear all the expenses of the administration of the Provident Fund including the maintenance of Accounts, submission of returns, transfer of accumulations.

26. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the fund as approved by the appropriate authority and as and when amended thereto alongwith a translation of the salient points thereof in the language of the majority of the employees.

27. The "appropriate Government" may lay down any further conditions for contained exemption of the establishment.

28. The employee shall enhance the rate of provident fund contributions appropriately if the rate of provident fund contribution for the class of establishment in which his establishment falls is enhanced under the said Act so that the benefits under the Provident Fund Scheme of the establishment shall not become less favourable than the benefits provided under the said Act.

29. The exemption is liable to be cancelled for violation of any of the above conditions.

[No. S-35015(4)/89-SS-II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1989

क्र.सं. 759.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूची में, केन्द्रीय सरकार, नेशनल इस्थॉयर्स कम्पनी के प्रबन्धन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, प्रबन्धन में निर्विष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई के पंचपट को प्रकटित करती है।

New Delhi, the 27th February, 1989

S.O. 759.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Bombay as shown in the Annexure, in

the industrial dispute between the employers in relation to the management of National Insurance and their workmen.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 BOMBAY

Reference No. CGIT-2/30 of 1987

PARTIES.

Employers in relation to the management of National Insurance Co. Ltd., Nagpur,

AND

Their workman,

Shri Sunil Mahadeorao Kaner

INDUSTRY : General Insurance STATE : Maharashtra
Bombay, the 1st July, 1988

AWARD

The Central Government by their Order No. L-17012/25/86-D.IV (A) dated 12-5-1987 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

"Whether the action of the management of National Insurance Co. Ltd., Nagpur is justified in terminating the services of Shri Sunil Mahadeorao Kaner w.e.f. 14-7-1985? If not, to what relief the workman concerned is entitled?"

2. Pending this reference, the Assistant General Manager of the above said Insurance Company sent a letter dated 22-5-1987 to the office of this Tribunal which is thus :—

"The applicant National Insurance Co. Ltd. begs to submit as under :—

1. That after the initial failure of the conciliation proceedings before the Asstt. Labour Commissioner (Central), Nagpur, due to changed circumstances the Applicant Co. and the non-applicant workman represented through union have come to the settlement of the dispute as per the terms and conditions laid down and agreed by both the parties.
2. That the said settlement of dispute has been duly registered with the office of the Asstt. Labour Commissioner (Central), Nagpur, on 5-6-1987 (copies attached).

It is, therefore, prayed that Consent Award may please be made."

3. A zerox copy of the terms and conditions of the settlement between the said two parties has also been sent to the office of the Tribunal. It seems that as the original document has been filed and registered with the office of the Assistant Labour Commissioner, (C) Nagpur, its zerox copy has been sent to this Tribunal. However, in view of the said letter dated 22-6-1987 by the Assistant General Manager of the said Insurance Company, I rely upon the zerox copy of the terms and conditions of the settlement. The zerox copy is bearing the signatures of the workman Shri Sunil M. Kaner, as well as of the Senior Divisional Manager of the said Insurance Company. The terms and conditions are thus :—

- "1. Agreed that Shri Sunil Mahadeorao Kaner shall be offered a fresh appointment as a sub-staff by the management latest by 15-6-87.
2. Union and workman agree not to make any claims for the past services.
3. Agree that both the parties shall jointly move the Hon'ble Central Government Industrial Tribunal for getting consent award pending with the Hon'ble Court

4. Agreed that both the parties shall get this settlement registered with the Secretary, Ministry of Labour, Chief Labour Commissioner (Central) New Delhi, Regional Labour Commissioner (Central), Bombay and Assistant Labour Commissioner (Central) Nagpur under Rule 58(4) of the Industrial Disputes Act.

5. Agreed that this is a full and final settlement of the dispute."

4. I find that the said settlement is quite in the interest of the said worker. It is further noticed from the record that the worker Shri Sunil M. Kaner joined his service in the said Insurance Company on 15-6-1987 (vide his letter dated 15-6-1987 addressed to the Senior Divisional Manager of the said Insurance Company). As such, award must be and is drawn in terms of the said settlement.

Award accordingly.

P. D. APSHANKAR, Presiding Officer

[No. L-17612/25/86-D.IV (A)/IR (B-I)]

PADMA VENKATACHALAM, Dy. Secy.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/30/87/297/87

Applicant—National Insurance Co. Ltd. Through Asstt. General Manager.

V/s.

Non-Applicant—1. Workman Shri S. M. Kaner

Application to get the Consent Award.

The Applicant National Insurance Co. Ltd. begs to submit as under :

1. That after the initial failure of the conciliation proceedings before the Asstt. Labour Commissioner (Central), Nagpur due to changed circumstances the Applicant Co. and the non-applicant workman represented through union have come to the settlement of the dispute as per the terms and conditions laid down and agreed by both the parties.
2. That the said settlement of dispute has been duly registered with the office of the Asstt. Labour Commissioner (Central), Nagpur, on 5-6-1987 (copies attached).

It is, therefore, prayed that Consent Award may please be made.

For National Insurance Co. Ltd.

Applicant/Company

Dated : 22-6-1987.

FORM H

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

Memorandum of Settlement between the management of National Insurance Company Limited and their workmen represented by Shri V. R. Deshpande, Branch Secretary, General Insurance Employees' Union, West Zone, Nagpur Branch, over the issue of reinstatement in service.

Representing Employer :

Shri G. S. Rajpal Sr. Divisional Manager, National Insurance Co. Ltd. Nagpur Division.

Representing Union/Workman :

1. Shri V. R. Deshpande.
2. Shri Sunil Mahadeorao Kaner.

Short reital of the case

Shri Sunil M. Kaner raised an industrial dispute vide his letter dated 24-3-86 regarding illegal termination of his services by the management of National Insurance Co. Ltd., Nagpur, and demanded reinstatement with back wages. The dispute ended in failure and a report was submitted to the Government. Subsequently both the parties agreed to discuss and settle the issues mutually. After discussions on various occasions and finally on 4-6-87 at length both the parties agreed to settle the dispute on the following terms and conditions.

TERMS AND CONDITIONS

1. Agreed that Shri Sunil Mahadeorao Kaner shall be offered a fresh appointment as a sub-staff by the management latest by 15-6-87.
2. Union and workman agree not to make any claims for the past services.
3. Agreed that both the parties shall jointly move the Hon'ble Central Government Industrial Tribunal for getting consent award pending with the Hon'ble Court.
4. Agreed that both the parties shall get this settlement registered with the Secretary, Ministry of Labour, Chief Labour Commissioner (Central) New Delhi, Regional Labour Commissioner (Central) Bombay and Assistant Labour Commissioner (Central) Nagpur under Rule 58(4) of the Industrial Dispute Act.
5. Agreed that this is a full and final settlement of the dispute.

Representing Employer :

(G. S. RAJPAL)

Sr. Divisional Manager
National Insurance Co. Ltd.
NAGPUR DIVISION

Representing Union :

(V. R. DESHPANDE)

Branch Secretary
G.I.E.U. West Zone
NAGPUR BRANCH

Workman concerned :

(SUNIL M. KANER)

NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED

(Subsidiary of General Insurance Corporation of India)

(Divisional Office : Firdos Chambers, Wardha Road, Post Box No. 218, Nagpur-440012)

Reference : 270400/Personnal/DGP/87

Dated : 12-6-1987

To

Shri Sunil Mahadeorao Kaner,
Baik Road, Near Datta Niwas,
W. No. 17, Mahul,
Nagpur.

Dear Sir,

We are pleased to inform you that you are appointed as Sub-staff in this Company on probation on basic salary of Rs. 430 per month, in the grade of 430-10-450-30-730 with other allowances applicable to existing regular employees in your cadre, on a provisional basis. In addition to the service terms and conditions which govern the existing regular employees in your cadre, you will also be governed by the following conditions :

- 1 Your appointment will take effect from 18th June, 1987.

2. (a) You will be on probation for a period of Six months which may be extended at the discretion of the Management.
- (b) During the probationary period your service will be liable to termination without notice and without assigning any reason by the Company.
3. You will be eligible for confirmation in the services be liable to termination wither notice and without probationary period.
4. On confirmation in the services of the Company you will be eligible for the usual benefits like Provident Fund, Gratuity, etc. etc. per Rules of the Company.
5. Increment in the period is not automatic and will be subject to regular attendance, good conduct, satisfactory work period and performance and will be governed by the Rules of the Company.
6. While in the services of the Company, including probationary period, you will be subject to and conforms to the rules and regulation of the Company, including General Insurance (Conduct, Discipline and Appeal) Rules, as are in force from time to time and carry out instructions given to you from time to time orally and/or writing.
7. During the probationary period if you leave/resign from the services of the Company, you are required to give three full days notice in writing. In default Company shall have right to deduct from dues payable to you/recover from you directly an amount equivalent to three days' salary.
8. On confirmation your appointment is terminable at any time by giving one month's notice in writing on either side without assigning any reason. Breach of this condition will entitle the Company to deduct from the dues payable to you/to recover from you one month's salary in lieu of notice.
9. You are liable to be transferred from one Department to another, from the Company to any subsidiary of the Corporation or from one place to another as and when required to do so.
10. The Company's right at law to take any action against you and/or to recover the dues of the Company from you and/or to claim damage from you and the rights of the like nature will not be affected or deemed to be waived by any reference to the terms and conditions mentioned herein and they are expressly reserved notwithstanding any specific mention herein or some of the rights of the Company.
11. You will have to undergo such training either during probation period or any time thereafter as may be prescribed by the Company.
12. You will be required to undergo a medical examination. In case you are found medically unfit, your appointment will be liable to be terminated forthwith.
13. Your present place of posting is :
Divisional Office,
"Firdos Chamber"
Wardha Road,
Nagpur.

Please report to Shri G. S. Raipal, Sr. Divisional Manager.

Please return the duplicate copy of this letter of appointment duly signed by you, to indicate that you have accepted all the terms and conditions mentioned herein.

Yours faithfully,

Sd/-

Sr. Divisional Manager

I hereby agree to and accept the terms and conditions mentioned hereinabove.

Dated at Nagpur this 15th day of June, 1987.

Senior Divisional Manager,
National Insurance Co. Ltd.,
NAGPUR.

Respected Sir,

As per your appointment letter Ref. No. 270400/Personnel/NGP/87 dated 12-6-1987, I joined the duty today i.e. on 15th June 1987 at 9.30 A.M.

Thanking you,

Yours faithfully,
(SUNIL M. KARNER)

Nagpur,

Dated : 15-6-1987.

प्रदेश

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1989

प्र. आ. 760--एम. ई. सी. एम. का हस्ताक्षर क्षेत्र आकस्मिकताओं के लिए डी. कोलियरी, जिना सरगुजा (मध्य प्रदेश) के प्रशासन में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच विवाद प्रतिनिधित्व, मध्य प्रदेश कोयला मजदूर संघ (हिन्दी मजदूर संघ) आकस्मिकताओं के लिए डी. कोलियरी जिना सरगुजा (मध्य प्रदेश) कर्ता है एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और उक्त नियोजकों और कर्मचारियों के औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1917 का 14) की धारा 10-क की उप धारा (1) के अधीन एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यम से लिए निर्दिष्ट करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यम करार को एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उप धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यम करार को प्रकाशित करती है।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10-क के अधीन प्रकाशित के नाम)

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले युनियन का प्रतिनिधित्व करने वाले

1

2

मध्य प्रदेश का हस्ताक्षर क्षेत्र आकस्मिकताओं के लिए डी. कोलियरी, जिना सरगुजा (मध्य प्रदेश) के प्रशासन में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच विवाद प्रतिनिधित्व, मध्य प्रदेश कोयला मजदूर संघ (हिन्दी मजदूर संघ) आकस्मिकताओं के लिए डी. कोलियरी जिना सरगुजा (मध्य प्रदेश) कर्ता है एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उप धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यम करार को प्रकाशित करती है।

(i) निम्नलिखित विवादार्थे शिप के बतौर कर्तव्य क्षेत्र एम. ई. सी. एम. में डेफेंस के माध्यम से नियोजित दब सम्पन्न करने वाले मजदूरों का सामना।

"क्या हस्ताक्षर क्षेत्र की दब सम्पन्न कार्य के लिए उक्त कार्य/कर्मचारियों के विमोचक के लिए युनियन की योग्यता निर्धारित है? यदि नहीं तो कर्मचारियों के अनुभव के हस्ताक्षर + ?"

- (ii) एम ई सी एल के हस्तक्षेप क्षेत्र के प्रबन्धतंत्र डाकघर-दक्षिणी जे के डी कोलियरी जिला सरगुजा (म प्र) तथा उनके कर्मचारों जिनका प्रतिनिधित्व जनरल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश कोयला मजदूर सभा (हिन्द मजदूर सभा) डाकघर-दक्षिणी जे के डी कोलियरी जिला सरगुजा (म प्र) के बीच औद्योगिक विवाद।
- (iii) यदि कोई संघ प्रयत्नगम कर्म- मध्य प्रदेश कोयला मजदूर सभा कारों या प्रतिनिधित्व करता हो (हिन्द मजदूर सभा) तो उसका नाम डाकघर-दक्षिणी जेकेडी कोलियरी जिला सरगुजा (म प्र)।
- (iv) प्रभावित उपक्रम में नियोजित 175 (एक सौ पचहत्तर) कर्मचारों की कुल संख्या
- (v) विवाद द्वारा प्रभावित या 175 (एक सौ पचहत्तर)। सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मचारों की प्राक्कलित संख्या

मध्यस्थ अपना पचाट तीन मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा।
साक्षी:— पक्षकारों के हस्ताक्षर:

1 -----
ह /— उप मुख्य कार्मिक प्रबन्धक
एम ई सी एल हस्तक्षेप क्षेत्र के
प्रबन्धतंत्र की ओर से।

ह /— जनरल सेक्रेटरी कर्मचारों की
ओर से एम पी के एम एस
(एच एस एस) दक्षिणी
जे के डी।

मध्यस्थ की सहकृति

मैं हस्तक्षेप क्षेत्र के टब की मरम्मत करने के कार्य में लगे कर्मचारों से संबंधित औद्योगिक विवाद में मध्यस्थता करने की अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।

ह /—

2-12-88

(एच जी भावे)

[संख्या एल-22025/4/89-आई आर (कोयला-II)]
आर.के. गुप्ता, डैस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 6th March, 1989

S.O. 760.—Whereas an industrial dispute exists between the employees in relation to the Management of Hasdeo Area of SECL, PO South JKD Colliery, District Surguja (MP) and their workmen represented by Madhya Pradesh Koyla Mazdoor Sabha (Hind Mazdoor Sabha) PO South JKD Colliery, District Surguja (MP).

And whereas, the said employers and their workmen have by a written agreement under sub-section (1) of section 10 A of the I.D. Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government a copy of the said arbitration agreement;

Now therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10 A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement.

AGREEMENT

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)
BETWEEN

Representing Employer:— General Manager, Hasdeo Area, South Eastern Coalfields Ltd., PO South JKD Colliery, Distr. Surguja (MP).

Representing Union:— General Secretary, For and on behalf of workmen, MPKMS (HMS) Union, PO South JKD Colliery, District Surguja (MP).

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri H.G. Bhave, Joint Chief Labour Commissioner (Central) (Retd.), Nagpur.

(i) Case of Tub Repairing Mazdoor s engaged through contractors in Hasdeo Area, SECL, under the following terms of reference.

"Whether the demand of the Union for departmentalisation of contractual work/workers for Tub Repairing jobs of Hasdeo Area is justified? If not, to what relief the workers would be entitled to?"

(ii) I.D. Between the Management of Hasdeo Area of SECL, PO South JKD Colliery, District Surguja (MP) and their workmen represented by General Secretary, Madhya Pradesh Koyla Mazdoor Sabha (Hind Mazdoor Sabha), PO: South JKD Colliery, District Surguja (MP).

(iii) Madhya Pradesh Koyla Mazdoor Sabha (Hind Mazdoor Sabha) PO South JKD Colliery, District Surguja M.P.

(iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected: 175 (one Hundred seventy five).

(v) Estimated number of workmen affected: 175 (one hundred and seventy five).

The arbitrator shall make his award within a period of three months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing.

Witnesses:—

Signature of the Parties

1. SJ/-

Sd/-

2. Sd/-

Dy. CHIEF PERSONNEL
MANAGER, For and on
behalf of Management of SECL,
Hasdeo Area.

Sd/-

GENERAL SECRETARY,
For and on behalf of workmen
MPKMS (HMS), South JKD

CONSENT OF THE ARBITRATOR

H.G. BAVE
M.A., D.S.W. (Cal.)
C.L.A. (London)

Phone : RES
'ANAND', 7 Ambazari
Layout, Near Nag River
NAGPUR-440 010
December 2, 1988.

To

The General Manager (P)
SECL,
Bilaspur.

Subject :—Arbitration u/s 10-A of the ID Act, 1947.

Dear Sir,

Kindly refer to your letter dated 26-11-88 on the above subject.

I hereby give my consent to arbitrate in the industrial dispute relating to workers engaged on tube repairing tubes of Hasdee Area.

Yours faithfully,
Sd/-

(2-12-88)

[No. L. 22025(4)/89-IR (Coal-2)
R.K. GUPTA, Desk Officer

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1989

का.आ. 761:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्वय में, केन्द्रीय सरकार व मैसर्स ई.सी. विम. की चाइनाकुरी कोलियरी के प्रबन्धन के सम्बन्ध में नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच अन्वय में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचसद को प्रकटित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 17-3-89 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 3rd April, 1989

S.O. 761.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Chinakuri 3 Pits Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 17-3-1989.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, ASANSOL

Reference No. 4 of 1988

PARTIES :

Employers in relation to the management of Chinakuri
3 Pits Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers—Sri B. N. Lah, Advocate.

For the Workman—None.

STATE : West Bengal

INDUSTRY : Coal

Dated. the 8th March, 1989

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred by them U/S 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute for adjudication to this Tribunal under Ministry's Order No. L-24012(134) 87-D.IV(B) dated the 23rd December, 1987.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Chinakuri 3 Pits Colliery of M/s. E.C. Ltd., in not recording the age of Sri Pancha Majhi, Dresher in the Form B Register as per identity card issued by the management is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

During the pendency of this Reference case, on 8-12-88 the management as well as the workman submitted a joint petition of compromise regarding the amicable settlement of the dispute by them out of Court. Both the parties have prayed for acceptance of the settlement and to pass an award in terms of the settlement.

3. The terms of compromise appear to be fair and beneficial to the workman. Accordingly the terms of compromise are accepted.

4. The award is made accordingly in terms of the settlement and the terms of the settlement do form part of the award.

5. Requisite copies of the award along with the terms of the settlement be sent to the Ministry.

Encl : Terms of Settlement.

S. K. MITRA, Presiding Officer

[No. L-24012(134) 87-D.IV(B)]

R. K. GUPTA, Desk Officer

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,
ASANSOL

In the matter of Reference No. 4 of 1988

PARTIES :

Employers in relation to the management of China
Colliery of M/s. Eastern Coalfields Limited

AND

Their Workmen

Joint petition of compromise

The humble petition of both the parties herein concerned most respectfully sheweth :

1. That the above matter is pending before the Hon'ble Tribunal for adjudication.

2. That the parties herein concerned discussed the instant matter mutually with a view to coming to amicable compromise and the parties have settled the instant matter on the following terms :

(a) That the employers agree that the workman herein concerned namely Sri Pancha Majhi will be given the opportunity to appear before the Area Age Determination Committee constituted in accordance with the agreed decision of the parties arrived at the Joint Bipartite Committee for the Coal Mining Industry for assessment/determination of his age.

(b) That both the parties agree that the age of the workman as assessed by the Age Determination Committee in terms of paragraph (a) above shall be binding on both the parties and the record of age of the concerned workman will be corrected accordingly in the record of the Form-B Register as well as Identity Card.

(c) That by this settlement the instant matter and any matter arising out of the instant matter stands fully and finally resolved and that his settlement will be effective as on the date the Hon'ble Tribunal accepts the instant settlement.

3. The both the parties pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept the instant settlement as fair and proper

and may be further pleased to pass an award in terms of the settlement.

And for this act of kindness both the parties as in duty bound shall ever pray.

Dated : this the 8th day of December, 1988.
Sd/- Illegible

For and on behalf of the workmen.

Sd/- Illegible
For and on behalf of the Employers

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1989

का० आ० 762.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1917 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार यूको बैंक के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण चंडीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 8th March, 1989

S.O. 762.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the UCO Bank and their workmen, which was received by the Central Govt.

ANNEXURE

BEFORE SHRI M. S. NAGRA, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-
LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I.D. 85/88

PARTIES :

Employers in relation to the management of United Commercial Bank.

AND

Their workman.—Makhan Singh.

APPEARANCES :

For the Workman.—None.

For the Management.—Shri N. K. Zakhmi.

AWARD

Dated : 16-2-1989

On a dispute raised by Shri Makhan Singh as employees of United Commercial Bank, Central Govt. vide letter No. L-12011/29/88-D.2(a) dated 28th October, 1988, has pleased to refer the following dispute to this Tribunal :—

“Whether the action of the management of UCO Bank in transferring Shri Makhan Singh, Armed Guard, from Ludhiana to Khanna is justified? If not, to what relief is the workman entitled?”

2. This reference was received from the Central Govt. and notice was issued to the Secretary Punjab Bank employees Congress House No. 1865, Sector 22-C, Chandigarh who had raised the dispute. Notice has been received back with the report that there is no such addresses at the given address. Sh. N. K. Zakhmi rep. of the Bank has informed

that Makhan Singh is locked in Central Jail LUDHIANA in a murder case. Reference is therefore, returned to the Central Government with comments that no adjudication is possible for want of appearance of workman or his authorised representative.

Chandigarh

Dt : 16-2-1989.

M. S. NAGRA, Presiding Officer

[No. L-12012/29/88-D.II(A)]

का० आ० 763.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1917 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैन्युल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं० 1 बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

S.O. 763.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Bombay, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL

TRIBUNAL No. 1. AT BOMBAY

Reference No. CGIT-34 of 1987

PARTIES :

Employers in relation to the management of Central Bank of India, Pune.

AND

Their Workmen

APPFARANCES :

For the Management.—Mr. L. M. Asrani, Chief Officer.

For the Workmen.—Workman present in person.

INDUSTRY : Banking STATE : Maharashtra.

Bombay, dated the 27th Jay of Junc, 1988

AWARD

The Industrial dispute which is referred to this Tribunal for adjudication arose out of dismissal of the second party workman from service of the Central Bank of India.

2. Shri A. B. Kulkarni, was discharged from service for gross misconduct of :—

(i) Wilful damage or attempt to cause damage to the property of the Bank or any of its customers.

(ii) Doing any act prejudicial to the interest of the Bank or gross negligence or negligence involving or likely to involve the Bank in serious loss which constitute gross misconduct in clause (d) and (j) of paragraph 19.5 of the Bipartite Settlement dated 19-10-1966.

It was alleged that the workman defrauded the Bank and misutilised Bank's money, tampered with the Bank's record, made false entries in the Account Books and even destroyed some record of the Bank such as vouchers while working as a Teller in the Pune City Branch during the period from September 1982 to December 1984. After these misconducts came to light the workman was suspended from service and he was served with the memo (Ex. M-3) dated 15-1-1985, calling upon him to show cause and explain

within 7 days of the receipt of the memo as to why disciplinary action should not be taken against him for the 13 Acts of misconduct enumerated in the said memo.

3. The workman replied to the memo on 28-1-1985, and offered his explanation as follows :—

- "1. I admit what has been stated in your above referred memo.
 2. Regarding Rs. 300 I have already admitted my guilt vide my representation dated 19-12-1984. I against bring to your kind notices that I have posted Rs. 300 in the H.S.S. Account No. 9384 without depositing the cash.
 3. I admit what has been stated in your above referred memo.
 4. I admit what has been stated in your above referred memo I enclose herewith the withdrawal which I have not destroyed.
 5. I admit what has been stated in your above referred memo.
 6. I admit what has been stated in your above referred memo.
 7. I admit what has been stated in your above referred memo. I enclose herewith the cheque which I have not destroyed.
 8. I admit what has been stated in your above referred memo. I also enclose herewith the cheque which I have not destroyed.
 9. Though I admit the charge of mis-appropriation of the Bank's Account I would like to bring to your kind notice that the cheque belonging to account No. 4105 was issued by me through oversight. When the inward clearing was received I realised my mistake. To avoid further complications and mistakes I have already destroyed all other unused cheques.
 10. Regarding what has been stated in your above referred memo I have already admitted my guilt and also I have informed you that I have not deposited the amount of Rs. 5200 which Mrs. Mehta Agencies had handed over to me for depositing in their Account.
 11. I admit what has been stated in your above referred memo.
 12. I admit what has been stated in your above referred memo.
 13. I admit what has been stated in your above referred memo."
4. In respect of 13 Acts of commissions and/or omissions mentioned in the memo (Ex. M-3), he went on to state the circumstances in which he committed the misconducts. He stated as follows :—

"Sir, I have been serving in the Bank since 30th September 1970. During my entire service period I have never disobeyed my superiors. I never refused to carry out any type of work which was allotted to me. I have always co-operated the management to keep the Branch atmosphere healthy and pleasant. Sir, I am having responsibility of my wife and two daughters. My old father and mother are also depending on me. You will agree that I am not a seasoned criminal person but the mis-appropriation which I have committed is out of some frustration and very disturbed situation of mind. I have now realised my mistakes. While agree that disciplinary action should be taken for my act. I request you Sir, to give me opportunity to serve the institution with sincerity and honesty in future."

5. The explanation offered by the workman however, was found to be unsatisfactory and hence the Disciplinary

Authority directed a departmental enquiry into the charges mentioned in the charge sheet dated 29-4-1985, and appointed the Deputy Chief Officer Regional Office, Pune, to act as Enquiry Officer. The enquiry was commenced on 2-8-1985, on which day the workman sought some clarification and after it was given he accepted all the charges mentioned in the charge sheet. He however, requested for a week's time for submitting written arguments. The workman submitted his arguments on 12-8-1985; the enquiry officer also heard both the sides on 16-8-1985, but in view of the gravity and seriousness of the charges levelled against the workman, in spite of the specific admissions given by the workman thought it fit to record management evidence in support of the charges levelled against the workman. As can be seen from the record of the departmental enquiry (which is marked as Ex. M-5 collectively) that further enquiry was held on 28-8-1985 on which day the presenting officer produced 27 documents and also gave a list of witnesses which he proposed to examine to prove the documents. As the workman admitted all these documents after inspecting each of them the management dispensed with the oral evidence of the witnesses whom the Presenting Officer wanted to examine to prove the documents. The enquiry officer then asked the workman what he had to say about the documents produced by the presenting officer. The workman replied as follows:—

"I have already submitted my confession and the acts which were committed by me through error in a particular state of mind for which I am now repenting. If the management takes sympathetic view and gives me a chance I assure that henceforth no such type of acts will be committed by me and I will be loyal to the institution. I therefore, pray to give me a last chance."

Thereafter, the enquiry officer closed the proceedings and submitted his report to the disciplinary authority on 12-9-1985. The report is at pages from 77 to 87 of Ex. M-5. Thereafter, the Disciplinary Authority by letter dated 19-11-1985, called upon the workman to appear before him for personal hearing in respect of the proposed punishment. A copy of the findings of the enquiry officer was also enclosed alongwith the said letter. Accordingly, the Disciplinary Authority heard the workman on 9-12-1985. On that day the workman besides making oral submissions, submitted his written say. The Disciplinary Authority passed the final order on the same day discharging the workman from Bank service with immediate effect. Being aggrieved by this order the workman submitted an appeal to the Appellate Authority namely the Deputy General Manager. The Appellate Authority rejected the appeal and confirmed the punishment conferred by the Disciplinary Authority. The workman thereafter preferred a mercy petition to the Chairman and the Managing Director who declined to interfere with the order passed by the Disciplinary Authority.

4. According to the workman, the enquiry officer did not record any evidence in support of the charges and based his conclusion solely on the confessional statements made by him in reply to the Show Cause Notice and on the admission of guilt given by him before the enquiry officer. Apart from the fact that in view of the specific admissions given by the workman in reply to the show cause notice no enquiry was necessary, in view of sub clause (iii) of Clause (c) of paragraph 19.12 of the Bipartite Settlement the submission is factually incorrect. As mentioned above, the enquiry officer on his own and in spite of the voluntary admission of guilt given by the workman in reply to the Show Cause Notice as well as before him at the outset of the enquiry decided to record evidence to prove the charges. The management placed on the record of the enquiry all the relevant documents and proposed to examine witnesses to prove those documents. The workman was shown each of these documents and after inspecting them he admitted those documents and even gave in writing that the documents were genuine and authentic. It was, therefore, not necessary for the management to lead any more evidence to prove the charges levelled against the workman. It is therefore, difficult to accept the submission that the

enquiry officer did not hold any enquiry into the charges and proceeded to pass his findings on the voluntary admission given by the workmen. Moreover, as observed above, in view of the relevant provision of the Bipartite Settlement it was not even necessary to hold an enquiry because in reply to the Show Cause Notice itself the workman had accepted his guilt. Sub Clause (iii) of Clause (e) of paragraph 19-12 specifically lays down that if the employee makes a voluntary admission of his guilt in his reply to the Show Cause Notice no enquiry need to held. Clause (e) only provides for a personal hearing regarding the nature of the punishment and that too if the employee concerned makes such a request. In this case a personal hearing the nature of the punishment was given even though the employee had not asked for it.

5. Another grievance of the workman is that he was not given personal hearing by the Appellate Authority before disposing of the appeal. The procedure to be followed by the Appellate Authority is laid down in paragraph 19.14 of the Bipartite Settlement. The relevant part of the said paragraph reads as follows :—

"Such appellate authority shall, if the employee concerned is so desirous, in a case of dismissal, hear him or his representatives before disposing of the appeal. In cases where hearings are not required, an appeal shall be disposed of within two months from the date of receipt thereof. In cases where hearings are required to be given and are requested for, such hearings shall commence within one month from the date of receipt of the appeal and shall be disposed of within one month from the date of conclusion of such hearings.

There is nothing to show that the workman was desirous of any such hearing. The appeal memo (Ex. M-10) is completely silent on this aspect of the matter. It does not contain any such request. The Appellate Authority therefore was not bound to give personal hearing to the workman and no prejudice can be said to have been caused to the workman on that account.

6. According to the workman, he himself brought the whole affair to the notice of the management and re-paid the entire amount which he had mis-appropriated. According to him, he had brought to the notice of the management his financial difficulties which compelled him to commit the acts complained of. But the management ignored these factors while inflicting the punishment which under the circumstances is unduly harsh. According to the workman, he should have been given some punishment short of removal from service. There is no substance in this contention. The management has already taken a lenient view of the matter and instead of inflicting the maximum punishment of dismissal which was fully justified, has only discharged him.

7. The workman was charged as follows:—

"Mr. A. B. Kulkarni, Clerk (under suspension), Pune City Branch's explanation dated 28-1-1985, in reply to Bank's Memo No. PC/E/37/BM dt 15-1-1985 has been found unsatisfactory and it has been decided to hold a Departmental Enquiry on the following charges which constitute gross misconduct as laid down under para 19.5 (d) and (j) of the Bipartite Settlement dated 19-10-1966. The charges are as under :—

(1) You have received amounts on various dates (the details are as under) in Recurring Deposit A/c. No. 3677 of Mr. B. S. Bhosale but deposited in bank account only after a very long interval. (the details are as under) The pass book has been entered on initialled by you on the date of receipt of amount. Thus you have defrauded the bank and misutilised bank's money. (The details are as under).

Date on which money received & entry made in pass book.	Post. No.	Date on which the amt. deposited in bank	Period for which the amt. is mis-utilised by you
1982, Sept. 1st	2	1983, March 8th	187
Oct. 1st	3	June 2nd	243
Nov. 3rd	4	July 5th	244
Dec. 29th	5	Aug. 10th	224
1983, Jan. 4th	6	Sept. 20th	259
Feb. 7th	7	Oct. 5th	246
Mar. 8th	8	Nov. 7th	244
April 5th	9	Dec. 2nd	241
May 5th	10	1984, Jan. 3rd	243
June 2nd	11	Feb. 2nd	245
July 5th	12	Mar. 5th	243
Aug. 10th	13	April 9th	242
Sept. 7th	14	May 17th	252
Oct. 5th	15	June 1st	239
Nov. 7th	16	July 23rd	258
Dec. 2nd	17	Aug. 1st	242
1984, Jan. 3rd	18	Sept. 3rd	248
Feb. 2nd	19	Oct. 5th	245
Mar. 5th	20	Nov. 5th	246
April 9th	21	Dec. 1st	236
May 17th	22	Dec. 5th	203
June 1st	23	Dec. 5th	187
July 20th	24	Dec. 5th	138
Aug. 1st	25	Dec. 5th	126
Sept. 3rd	26	Dec. 5th	93
Oct. 8th	27	Dec. 5th	58
Nov. 9th	28	Dec. 5th	26
Dec. 1st	29	Dec. 5th	4

(2) On 30-4-84 while working as Teller, you have with malefide intention given an extraneous credit of Rs. 300 in the HSS A/c No. 9384 of Mr. N. S. Bafna. This amount was neither received by the bank, nor accounted for in the books. To keep the balance and abstract tallied, you have fictitiously inflated the credit side on 30-4-84 in the abstract of ledger No. 28 and debit side of ledger No. 24 and thus tampered with the bank's record and you also destroyed the voucher.

(3) On 10-6-84, while working as Teller, you have passed two withdrawals in the HSS A/c No. 8114 of Mr. M. B. Ghadge for Rs. 1,500 each. These withdrawals were not posted in the ledger but the amounts were paid. To circumvent the rule of payment by Teller you have made two withdrawals of Rs. 1,500 each in the above HSS A/c on the same day. The two withdrawals have been destroyed by you. Thereafter altered the supplementary dt. 10-5-84 and abstract with an ulterior motive to cheat the bank and thus tampered with the bank's record.

(4) On 25-5-84 while working as Teller you have paid Rs. 1,800 to Shri G. S. Potphods despite the fact that there was no balance in his HSS A/c 6166. The withdrawal was also not posted in the a/c. To avoid detection of this fraudulent withdrawal, you have surreptitiously entered the withdrawal in the supplementary on 25-5-84 after the checking was over. You have further removed the withdrawal with an intention to cheat the bank.

- (5) On 28-3-84, while working as Teller, you did not post a withdrawal of Rs. 2,200 in the HSS A/c 6166 of Mr. G. S. Potphode but sent it to the officer for passing and payment by paying cashier. There was no balance also in the account. The withdrawal is filled in by you. Thus you have defalcated the amount.
- (6) On 31-5-84 while working as Teller, you did not post a withdrawal of Rs. 2,000 in the HSS A/c 6348 of Mr. A. R. Borlikar. While the payment has been made by him, there was no available balance in the account. The withdrawal was destroyed by you after the checking was over and also altered the supplementary and thus tampered with bank's record.
- (7) On 28-8-84 a cheque bearing No. 122846 for Rs. 2,000 drawn on Jt. HSS A/c No. 9745 of yourself and Mrs. Archana Arund Kulkarni was presented through clearing. The cheque has been destroyed by you. To avoid detection through the day's clearing, you have fictitiously altered the O/D debit clearing column. To tally the daily balance book, you have inflated the daily balance in an A/c and thus tampered with the bank's record.
- (8) You have removed one cheque bearing Rs. 122850 drawn on Jr. HSS A/c 9745 of yourself and Mrs. A. A. Kulkarni for Rs. 2,000 presented through clearing on 25-9-84. To avoid detection through the day's clearing, you have inflated an item fictitiously in C/D I supplementary on 25-9-84 and thus tampered with the bank's record.
- (9) On 29-9-84, a cheque bearing No. 118940 for Rs. 8,000 drawn on HSS A/c 4105 of Central Bank of India, Reception Committee which is jointly operated by you and Mrs. S. S. Athavale and presented through clearing has been destroyed by you. To avoid detection through the day's clearing you have altered an item in C/D I supplementary on 29-9-84 and thus tampered with bank's record.
- (10) On 13-10-84 you have not posted a cheque bearing No. 17286 of M/s. Mehta Agencies for Rs. 5,147-30 received through clearing in his account but same amount was added up in the debit clearing column against the name of M/s. Javid Tin Suppliers in C/D I Supplementary after the checking was over and thus tampered with bank's record. The cheque has been cancelled by yourself.
- (11) On 29-10-84, a cheque bearing No. 123834 for Rs. 13,000 drawn on Jr. HSS A/c No. 9745 of yourself and Mrs. A. A. Kulkarni and received through clearing has been destroyed by you. To avoid detection through the day's clearing, you have while carrying over C/D I supplementary to summary inflated the debit clearing column by Rs. 13,000.
- (12) On 21-11-84 certain cheque/s for Rs. 1,500 received through clearing has been destroyed by you. To avoid detection through the day's clearing you have added up the item against the name of M/s. Mehta Agencies in C/D I supplementary after the checking was over and thus tampered with bank's record.
- (13) You have destroyed a cheque bearing No. 123840 for Rs. 4,000 drawn on Jt. HSS A/c 9745 of yourself and Mrs. A. A. Kulkarni received on 11-12-84 through clearing. To avoid detection through the day's clearing you have altered in C/D I supplementary and thus tampered with bank's record."

It will be seen from the charges levelled against the workman that it was not a case of solitary instance of misappropriation. The workman did so on several occasions during the period from September 1982 to December 1984 and he retained the mis-appropriated funds for periods rang-

ing from 4 to 259 days as can be seen from the details given in para 2 of the charge sheet. Further not only the workman misutilised Bank's funds for pretty long time in many cases he even made false entries in the record of the Bank and destroyed some record to facilitate his fraud in several cases as mentioned in paragraph 2 to 13 of the charge. There is also no basis for the tall claim that the workman himself made clean breast of the whole affair. It appears that the fraud had come to the notice of the concerned authorities of the Bank through routine inspection of the accounts and that perhaps after coming to note that the fraud was exposed the workman took prompt steps to admit the guilt and to refund the amount. That was not repentance but a strategy adopted to escape serious punishment. The charges levelled against the workman were so grave and were so numerous that dismissal from service would have been proper punishment. The Bank authorities, however, have chosen to take a lenient view and to inflict a lesser punishment of discharge. Further leniency, therefore, is completely un-called for.

8. In the result therefore, the action of the management of the Central Bank in discharging Shri A. B. Kulkarni, from service is up-held. Consequently the workman would not be entitled to any relief. Award accordingly.

M. S. JAMDAR, Presiding Officer

[No. L-12012/55/87-D II(A)]

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1989

का.आ. 764—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पंजाब देशस्थ बैंक के प्रबन्धन के सम्बन्ध में नियोजकों और उनके कर्मकों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिनियम चंडीगढ़, के पक्षों को प्रकटित करती है, जो केन्द्रीय सरकार की 16-3-1989 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 27th March, 1989

S.O. 764.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 15th March, 1989.

ANNEXURE

BEFORE SHRI M. S. JAMDAR, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL—
CUM LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. 42/88

PARTIES :

Employers in relation to the management of Punjab National Bank.

AND

Their workman : S. K. Sharma.

APPEARANCES :

For the workman—None.

For the management—Manjit Singh.

AWARD

Dated 16-2-1989

On a dispute raised by workman S. K. Sharma of Punjab National Bank, Central Government has been pleased to make the following reference vide No. L-12012/829/87-D.II (A) dated 13th July 1988 to this Tribunal :

"If Shri S. K. Sharma being the President of P.N.B. Staff Union is entitled to the special leave during the period 1981 to 1984 as per the bipartite settlement ? If so, to what relief he is entitled to ?"

2. In the presence of Shri S. K. Sharma on 10-1-1989 the case was adjourned for today i.e. 16-2-1989 and he is not present. In view of the absence of the workmen, reference is dismissed for want of prosecution. Central Government may be informed and file be consigned to report.

Chandigarh,

Dated : 16-2-1989.

M. S. NAGRA, Presiding Officer
[No. L-12012/829/87-D.II (A)]

क.अ. 765:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकों के बीच, अनुबन्ध में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चण्डीगढ़ के पंचपट को प्रकटित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-3-1989 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 765.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th March, 1989.

ANNEXURE

BEFORE SHRI M. S. NAGRA, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL
CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I. D 94/88

PARTIES :

Employers in relation to the management of Punjab National Bank.

AND

Their workman : Sohan Lal.

APPEARANCES :

For the workman—None.

For the management—Shri Manjit Singh.

AWARD

Dated 16-2-1989

On a dispute raised by Sohan Lal a dismissed employee of Punjab National Bank, Central Government has been pleased to make the following reference vide No. L-12012/451/88-D.II (A) dated 30th November, 1988 to this Tribunal :—

"Whether the dismissal of service of Shri Sohan Lal w.c.f. 2-1-1987 by the management of Punjab National Bank, Jalandhar is justified? If not, to what relief the employee is entitled?"

2. Notice of the reference was issued to the workman Shri Sohan Lal who has failed to put up appearance inspite of personal service through regd. A.D. for today. The reference is therefore, dismissed for want of prosecution. Central Government may be informed and file be consigned to record.

Chandigarh,

Dated : 16-2-1989.

M. S. NAGRA, Presiding Officer

[No. L-12012/451/88-D.II (A)]

N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1989

क.अ. 766:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, सेंट्रल कार्बोन्स लि. की कारो सप्लाय परियोजना के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकों के बीच, अनुबन्ध में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, सं. 2 धनबाद के पंचपट को प्रकटित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-3-1989 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 23rd March, 1989

S.O. 766.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Karo Special Project of M/s. C. C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 15-3-1989.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 27 of 1986

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Karo Special Project of CCL and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen : Shri J. D. Lall, Advocate.

On behalf of the employers : Shri R. S. Murthy, Advocate.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 9th March, 1989

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No L-24012 (37)/85-D.IV(B), dated, the 24th December, 1985.

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of Karo Special Project of M/s. C. C. Ltd., P.O. Sunday Bazar, Bermo, Dist. Giridih in not regularising S/Shri Manesh Ram Mahto, (2) Dilip Kr Roy, (3) Laljee Manjhi, (4) Nanka Mahto, (5) Jawaharlal Roy, (6) Rashbihari Mahto, (7) Fagu Mahato, (8) Parbati Devi, (9) Tara Prasad, (10) Gulam Ansari Debasis Mitra and Arunkumar when they have been working in regular nature of work, for more than seven years is legal and justified? If not, to what relief the concerned workmen are entitled?"

The case of the workmen is that the management of Karo Special Project of M/s. CCL engaged the concerned workman Shri Manesh Ram Mahato in the year 1977 as petty contractor to manufacture clay cartridges within the premises of the Project @ Rs. 7.25 per 1000 clay cartridges. The said concerned workman Shri Manesh Ram Mahato engaged himself as workman and associated the other 11 concerned workmen on the job of manufacture of clay cartridges. The concerned workman Manesh Ram Mahato was recruited by the management and the other concerned workmen were employed through Manesh Ram Mahato. The management had entered into an oral agreement with Shri Manesh Ram Mahato to the effect that the management would supply earth by transporting it by Dumper or Tipping trucks at the site for the

manufacture of clay cartridges and that the management would ensure supply of water at the storage tank through pipes and the management constructed storage tanks close to the shed where the clay cartridges were to be prepared. The management was also to supply coal for drying up the clay cartridges during the rainy season and that the management had also agreed to supply the materials required for preparation of clay cartridges at the place of work such as baskets kudal etc. The rate for clay cartridges was fixed by the parties @ Rs. 7.25 per thousand cartridges. The management provided all the above materials to Manesh Ram Mahato to prepare the clay cartridges. The management also provided an Open Space along with the shed situated in between cement godown and attendance cabin close to the incline mouth and Seam No. 3 of Karo Special Project Phase-I. The said shed was used for drying up the clay cartridges during the rainy season and during other seasons clay cartridges were dried in the open space and in the open sun. The clay cartridges after being dried up were stored in the store room provided for the storage of clay cartridges situated adjacent to the attendance cabin. The work of manufacture of clay cartridges was being supervised by the overman and the Munshi of the management and they used to give necessary direction whenever required. The duty hours of the concerned workman was fixed from 8 A.M. to 4 P.M. and the concerned workmen were regularly working during the said duty hours in the manufacture of clay cartridges. The clay cartridges are required daily for the purpose of stemming shot wholes used for blasting of coal. The production of coal cannot be done without stemming materials and as such the manufacture of clay cartridges is regular, perennial and permanent nature of job and is directly associated in the production of coal. The management made some paper arrangement to deprive the concerned workmen from getting their legitimate wages as per Wage Board Recommendation read with NOWA-I, II and III. The concerned workman used to divide the amount paid to them by the management or piece rate basis and for all purpose the concerned workmen were the workmen of the management. The concerned workmen have worked continuously from the year, 1977 to be more than 240 days of attendance every year and as such they are entitled to be treated as permanent workmen of the management. On the above facts it is prayed that the concerned workmen are entitled to be regularised as workmen of the management from the year 1977 and they are further entitled for all other benefits since then.

The case of the management is that there is no valid industrial dispute in the present case in as much as there was no relationship of employer and employee between the management and the persons referred to in the order of reference. The dispute referred to the Tribunal does not constitute industrial dispute within the meaning of Section 2(k) of the I.D. Act. Apparently the demand in the present case is for the abolition of the contract system and such a issue cannot be referred to an Industrial Tribunal for adjudication.

Karo Special Project is one of the collieries of the CCL which is a Government company in a public sector undertaking wholly financed by the Central Government and is a subsidiary company of CIL which is a holding company. Karo Special Projects consists of 2 different mines namely Karo Special Project phase I and of Karo Special Project phase-II. These two mines are located at a distance of 7 K.M. from each other in East Bokaro Coalfield and they fall within the Bokaro and Kargali Area of CCL. Karo Special Project Phase I started in 1976 and Karo Special Project phase-II started in 1978-79. Those two mines are under ground mines and in the year 1983 an Open caste mine was also started as a part of Karo Special Project Phase I. The said underground mine in question, like all other underground mine, require clay cartridges for the purpose of being used as a stemming materials in the process of blasting of coal. From the very inception, the management has been purchasing clay cartridges from the suppliers like many other materials required by the management such as Timber, cane baskets, bricks, sand etc. Since few years clay cartridges for the Karo Special Project were purchased from the concerned workman Shri Manesh Ram Mahato and Salim Aktar. It was for this suppliers to make their own arrangement for the manufacture and supply of clay cartridges and to employ their own men for the said purpose. It was open to the management to purchase or not the clay cartridges from the

above suppliers and there was no obligation on the part of the management to purchase the clay cartridges from any particular supplier. The suppliers deliver the clay cartridges to the management according to the requirement and the suppliers submit their bills for the quantity actually supplied by them at the rate at which the purchase of the clay cartridge is agreed upon. The concerned workmen Shri Manesh Ram Mahato was accordingly supplying clay cartridges to the management and submitting his bill and was receiving payment against the bills submitted by him, as supplier. By letter dated 1-9-81 Shri Manesh Ram Mahato approached the management with a request to increase the rate of supply of clay cartridges from Rs. 7.25 P. per thousand clay cartridges to Rs. 10.25 to supply the clay cartridges @ Rs. 7.25 P. per thousand. Again Shri Manesh Ram Mahato demanded higher rate for the supply of clay cartridges. The Project Officer Karo Special Project by his office order dated 14/15-4-1983 constituted a committee of officers for considering the demand of Shri Manesh Ram Mahato and making their recommendation. The committee of officers recommended by their report dated 30-5-83 that the rate for supply of clay cartridges be increased to Rs. 10 per thousand. This recommendation was accepted by the Project Officer Karo Special Project by his order dated 1-6-83 and accordingly with effect from 1-6-83 Manesh Ram Mahato and Salik Aktar were paid @ Rs. 10 per thousand of clay cartridges. The requirement of clay cartridges for Karo Special Project Phase-I is about 4000 to 5000 clay cartridges per day. But normally it was much less. The management for such a quantity of clay cartridges does not require the services of more than 2 to 3 persons per day. It is fantastic to say that as many as 12 persons were engaged for the manufacture of clay cartridges. Shri Manesh Kumar Mahato was only supplier of clay cartridges and his demand for employment from the management was absurd. Shri Manesh Ram Mahato did not employ any of the persons referred to in the reference order. A deliberate and fraudulent attempt has been made by the sponsoring union to induct into the employment of the management and such attempts have to be deprecated. In the Industrial dispute raised before the ALC(C) Hazaribagh by the sponsoring union it was claimed that the persons referred to in the reference order including Manesh Ram Mahato were engaged by a contractor and that the contract system should be abolished and the persons concerned should be provided with employment by the management. The management had disputed and denied the said claim during the conciliation proceeding and had contended that Shri Manesh Ram Mahato was supplier of clay cartridges and that he or any other person had no right to claim employment under the management. Even if it is assumed that Shri Manesh Ram Mahato was a contractor the abolition of contract system cannot be subject matter of an industrial dispute for adjudication by the Industrial Tribunal and as such the issue has to be dealt with by the appropriate Government in accordance with the provision of the contract Labour (Regulation and Abolition) Act. In the facts and circumstances of the case the question of regularising the persons named in the reference order by the management does not arise and the management is not obliged to take any of the persons concerned in its employment. The reference order is based on misconception of the legal and factual position. The management was not required to supply any material such as earth baskets or kudal to Shri Manesh Ram Mahato. They were not required to work at any specific place within the mine premises. The management had not to make any arrangement for storage of water through pipes for the purpose of manufacture of clay cartridges. The concerned persons were also not required to attend duty from 8 A.M. to 4 P.M. and no hours of duty was fixed and work of clay cartridges was not supervised by the Foreman, Munshi or any Officer of the Mine. The only agreement between the parties was that Manesh Ram Mahato would supply the clay cartridges @ Rs. 7.25 per thousand clay cartridges. No agreement was entered into between the management and Shri Manesh Ram Mahato orally. The management did not provide any open space alongwith a shed between the cement godown and attendance cabin close to the incline mouth of seam No. 3 of Karo Special Project Phase I. The shed refers to a cycle shed for the benefits of the workers coming to work by cycle for parking the same. The said shed is also used by the management for storing the clay cartridges after purchase from the suppliers. The management does not supply coal during the rainy season for drying up the clay cartridges inside the shed. The storage tanks existing at the mine

is meant for supply of drinking of water to the workers. It is submitted on behalf of the management that their action is not agreeing to regularise the 12 concerned persons is justified.

The points for decision are (1) whether there was any relationship of employer and employee between the management and the workmen concerned, (2) whether Manesh Ram Mahato was supplier of clay cartridges to the management and (3) whether the claim of regularisation of the workmen concerned is justified.

The workmen have examined 4 witnesses and the management has examined one witness in support of their respective case. The documents of the workmen are marked Ext. W-1 to W-10 and the documents of the managements are marked Ext. M-1 to M-6.

The essence of the case of the management is that Manesh Ram Mahato was a supplier of clay cartridges on fixed price to the management and that the management was not at all required to oblige the supplier to give employment. In this connection the management has denied that any material was supplied to Manesh Ram Mahato for the preparation of clay cartridges. The case of the workmen concerned is that the management had actually engaged them to manufacture the clay cartridges which was necessary requirement for the blasting of coal but the management had contrived a method and had paper transactions to that effect so that the persons concerned may not be paid the regular wages of clay cartridge maker and may appear to be outsider. It is stated in para-2 and 11 of the W.S. of the workmen that the management had recruited Manesh Ram Mahato and engaged him in the year 1977 as a petty contractor to manufacture clay cartridges within the premises of the Project @ Rs. 7.25 per 1000 clay cartridges and that other persons concerned were employed by Manesh Ram Mahato. It is admitted by the management that Manesh Ram Mahato was supplying clay cartridges to the management @ Rs. 7.25 P. per 1000 cartridges. It appears from the evidence in the case which I am discussing now that the management was not placing the entire truth before the Tribunal. WW-1 Trilok Singh is working as Truck Driver in Karo Special Project since 1980. He has stated that clay cartridges are manufactured in Karo Special Project. He has stated that whenever the Management asked him to bring clay on the Tipping Truck he used to bring the clay and unload it at the mouth of 3 inclines for the purpose of manufacture of clay cartridges. He has further stated that in other shifts also the driver used to bring clay for the manufacture of clay cartridges. According to him 8 to 10 persons were engaged for the manufacture of clay cartridges near the 3 incline and that the clay cartridges were manufactured during the general shift from 8 A.M. to 4 P.M. He has stated that the management used to supply water through pump for the manufacture of clay cartridges. He had seen since 1980 Manesh Ram Mahato preparing the clay cartridges alongwith other persons whom he does not recognise. According to him the management used to supply the entire clay for the manufacture of clay cartridges and had denied that the clay was occasionally provided by the management for the manufacture of clay cartridges he was thoroughly cross-examined on behalf of the management but I see no reason to disbelieve him as there was some document to support the fact that the clay was supplied by the management by trucks. Ext. W-2 dated 19-8-85, W-3 dated 24-8-85, W-4 dt. 5-1-85, W-5 dated 10-10-84, W-6 dated 25-11-85, W-7 dated 5-3-86 and W-10 dated 17-6-85 all go to show that slips were issued for supply of earth by the trucks for the manufacture of clay cartridges to Manesh Ram Mahato. WW-2 Shri Jagdish Pd. is an Overman in Karo Special Project Phase-I since 1982. He has stated that clay cartridges are manufactured in Karo Special Project for use in the blasting and that the same is manufactured near the seam No. 3, new seam No. 5 and old seam No. 5 by Manesh Ram Mahato. He has also stated that about 10 persons work alongwith Manesh Ram Mahato in the manufacture of clay cartridges. He has further stated that he sometimes go to see the preparation of clay cartridges and gave instruction to prepare the clay cartridges of the proper size. He further stated that the clay cartridges near the 3 inclines are used in those respective inclines and the clay cartridges are dried up near the place of its manufacture and thereafter it is stored in a room which is located

near each incline. He has stated that he counts the clay cartridges then informs the Mines Incharge. He has further stated that the management supplies trucks to bring clay and supply the clay to Manesh Ram Mahato. WW-3 is Manesh Ram Mahato has stated that since 1977 he is manufacturing clay cartridges in Karo Special Project Phase 1 along with the concerned 12 persons. He has stated that the management supplies clay through their own trucks to him for the preparation of the clay cartridges. He has stated that he manufactures the clay cartridges at 3 places near the 3 inclines of Karo Special Project and they work in group of 3 to 4 persons. He has stated that the management supplies water through pipes baskets kudal etc. for the manufacture of clay cartridges. He has stated that the clay cartridges are dried near the place where it is manufactured. He has also stated about the supervision of work by the offices of the mine. WW-4 Shri H. N. Roy is the Union leader who had raised the industrial dispute and he learnt about the facts from the concerned persons. WW-4 works in the establishment section of Karo Special Project and it is not expected that he would be looking after the manufacture of clay cartridges. The evidence of the workmen witnesses finds some support from the evidence of MW-1 Shri Amarnath Jha working in Karo Special Project Phase 1 from 1-1-79 to March, 1985 in the different capacity as under Manager, Asstt. Manager and Manager. He has stated that Shri Manesh Ram Mahato used to supply clay cartridges to the Mine and was formerly paid @ Rs. 7.25 P. per thousand cartridges and subsequently it was increased to Rs. 10 per thousand clay cartridges. He has stated that Manesh Ram Mahato had applied for increase of the rate of clay cartridges being supplied by him vide Ext. M-1. He has further stated that Manesh Ram used to get the clay cartridges prepared by the side of the mine premises. He does not remember if any materials for the preparation of the clay cartridges was supplied to Manesh Ram Mahato by the management. Thus it appears from his evidence that Shri Manesh Ram was preparing the clay cartridges by the side of the mine premises. He does not specifically deny about the supply of the materials for the manufacture of clay cartridges by Manesh Ram Mahato. In the face of Exts. W-1 to W-7 and W-10 it was not possible for him to deny the fact of supply of baskets (Ext. W-1) and clay by the management to Manesh Ram Mahato. In face of the existing facts he had to admit in his evidence that sometimes the management supplied truck to Manesh Ram for bringing clay. He also stated that Manesh Ram used to get water which was discharged from the coal mine. It is also admitted that occasionally the management supplied basket to Manesh Ram on his request. He has denied that Manesh Ram was a contractor. He did not know about the persons who were engaged by Manesh Ram in the manufacture of clay cartridges. From his evidence in the cross-examination it will appear that Manesh Ram was supplying clay cartridges since before his joining at Karo Special Project Phase I in 1979. He did not know if there was any agreement between the management and Manesh Ram Mahato. He has stated that he cannot say if the duty hours of the concerned persons was fixed from 8 A.M. to 4 P.M. He has denied that the amounts which was paid by the management was labour charge only. He has stated that the clay cartridges were received at the 3 places in Karo Special Projects. According to him Manesh Ram was not registered as contractor under the contract act nor Manesh Ram had any licence for contractor. In view of the evidence of Manesh Ram Mahato, WW-3 Truck Driver WW-1 and the Overman WW-2 coupled with the documents Ext. W-1 to W-7 and W-10 and some of the admission made by MW-1 it is clear that Manesh Ram Mahato was not the supplier of the clay cartridges as is the case in respect of other suppliers of materials of the colliery. The suppliers of materials are not provided different materials from the colliery for the manufacture of the materials being supplied to the colliery. In the case of Manesh Ram Mahato it is evident that Manesh Ram Mahato was manufacturing the clay cartridges near the mouth of 3 incline of Karo Special Projects Phase-I and the materials such as earth, basket, water etc. for the purpose of the manufacture of clay cartridges was supplied by the management. The management was providing space for the manufacture, driving up and storing of the clay cartridges within the premises of the mines.

In this connection I would like also to mention a few documents filed on behalf of the management, Ext. M-1 dated

1-9-81 is the application of Manesh Ram Mahato for increasing the rate of supply of clay cartridges from 7.25 per thousand clay cartridges to Rs. 10.25 per thousand of cartridges. It will appear from office order Ext. M-3 dated 14/15-4-83 issued by the Project Officer Karo Special Project that a committee was constituted for considering the demand for increase in the rate of clay cartridges. Ext. M-4 is the report of the committee set up for considering about the demand for the increase of the rate of clay cartridges after the issuance of the office order Ext. M-3. It will appear that a committee was constituted on 30-5-83 to consider the rate of the labour charge of stemming materials as reported by the party and thereafter the committee recommended the rate of supply of stemming materials at Rs. 10 per thousand clay cartridges established through negotiation. The said rate was approved by the Project Officer and it was made effective with effect from 1-6-83. It is the admitted case of the parties that the rate of supply of clay cartridges was increased from 7.25 per thousand to Rs. 10 per thousand. I have referred to Ext. M-4 for the purpose of showing that the committee had considered the rate of the labour charge of the stemming materials as represented by the party. It goes to show that Manesh Ram Mahato was actually paid the labour charges of manufacturing clay cartridges formerly @ Rs. 7.25 per thousand clay cartridges and subsequently vide Ext. M-4 @ Rs. 10 per thousand clay cartridges. The fact that the amount paid to Manesh Ram was a labour charge and not the complete price of the clay cartridge is supported from Ext. M-4 and also from the fact that the management was itself supplying clay through their trucks and basket, water and space within the mines premises near the mouths of the incline for manufacturing and drying up the clay cartridges. All these go to show that the rate fixed by the management to Manesh Ram Mahato was not the actual price of the clay cartridges but it was only the labour charge in the manufacture of the clay cartridges.

No doubt it is stated in the W.S. of the workmen that Manesh Ram Mahato was engaged as petty contractor to manufacture clay cartridges and the pay order Ext. M-2 series show that Manesh Ram Mahato was paid for supply of stemming materials. The fact remains that Manesh Ram Mahato was not a contractor and was not having any licence for contractor under the contract Labour (Regulation and Abolition) Act and facts and evidence discussed above show that Manesh Ram Mahato was just employed to manufacture the clay cartridges materials and facilities for which were provided by the management and there is no element to establish that Manesh Ram was just a supplier of clay cartridges to the consumer. It appears that the management was providing materials and facilities for the manufacture of the clay cartridges and Manesh Ram was engaged to put his labour force in the manufacture of clay cartridges. A person who puts labour only in the manufacture of clay cartridges cannot be said to be a supplier of clay cartridges in the sense that the management was purchasing the entire manufactured clay cartridges from a seller. In view of the discussions made above I hold that Manesh Ram Mahato was not a supplier of clay cartridges of the management but was only devoting his labour in the manufacture of clay cartridges the materials and facilities for which was provided by the management.

Point No. 1

In view of the finding made above it appears that Manesh Ram Mahato was not a contractor or supplier of manufactured clay cartridges. I have discussed above in details to show that the concerned workman was actually giving his labour for the manufacture of clay cartridges within the premises of the colliery. There is no oral or documentary evidence to show that there was any contract between Manesh Ram Mahato and the management for supplying of clay cartridges manufactured outside the colliery premises. MW-1 has stated that clay cartridges are necessary for blasting of coal mines from day to day. There is no doubt that the clay cartridges are essential material which is required from day to day as stemming materials for the blasting of coal and that unless the coal is blasted, there can be no production of coal. It will thus appear that Manesh Ram Mahato was engaged in the manufacture of clay cartridges which was required for day

to day work as stemming materials for the production of coal and as held above the concerned workman was neither working as a contractor nor as a supplier of clay cartridges. It is more than obvious that Shri Manesh Ram Mahato was manufacturing the clay cartridges as a workman of the Project, and the evidence adduced on behalf of the workmen show that the manufacture of clay cartridges was done under the guidance and supervision of the management. In view of the above I hold that there was relationship of employer and employee between the management and Manesh Ram Mahato.

Point No. 3

It will appear from the case of the workmen that demand is being made for the regularisation of all the 12 concerned persons as an employee of the management, in the discussions made above I have not mentioned about the facts and case of the persons concerned except Manesh Ram Mahato. This was with purpose. It will appear from the evidence of MW-1 and MW-2 that although Manesh Ram Mahato was seen manufacturing the clay cartridges along with others they did not identify the other persons except Manesh Ram Mahato. WW-3 Manesh Ram Mahato had no doubt stated that the other concerned persons were engaged by him in the manufacture of the clay cartridges. It is clear therefore that the management had not engaged directly any other man except Manesh Ram Mahato in the manufacture of clay cartridges. It is no doubt stated by the workmen that the amount of clay cartridges received by Manesh Ram used to be divided to the concerned workmen on the piece rate basis. There is absolutely no evidence on the record to show that the concerned persons other than Manesh Ram Mahato was manufacturing the clay cartridges. There is no evidence to show whether the persons other than Manesh Ram were continuously engaged in the manufacture of clay cartridges since 1977. The other concerned persons have not come forward in support of their case. In the absence of any reliable evidence it is difficult to hold that the persons other than Manesh Ram Mahato were regularly engaged in the manufacture of the clay cartridges. If the other persons were being paid for the clay cartridges prepared by them on the piece rate basis, Manesh Ram must have been paying them different amount for doing different quantity of work and for that he must have been maintaining some records as to give them their proper amount for the work done by them. Manesh Ram did not produce even a chit to show as to who were the persons who were engaged by him in the manufacture of the clay cartridges and since when they were working or that they were working regularly in the manufacture of clay cartridges. In the above view of the matter I hold that there is absolutely no evidence to hold that the concerned persons other than Manesh Ram Mahato were engaged in the manufacture of clay cartridges although Manesh Ram Mahato had engaged some persons for the manufacture of clay cartridges. In view of the above I hold that the claim of Manesh Ram Mahato for regularisation as clay cartridge maker of the management is justified but there is no justification for regularisation of other concerned persons whose case has not been established before me. WW-3 Manesh Ram Mahato has stated in his evidence that in the neighbouring colliery the management have engaged their own workmen to prepare the clay cartridges as time rated Cat. I. Time rated Cat. I is the minimum category and as such the demand of Manesh Ram Mahato appears to be quite moderate.

In the result, I hold that the action of the management of Karo Special Project of M/s. CCL in not regularising Shri Manesh Ram Mahato who was working in the regular nature of work for more than 7 years is not justified but the management is justified in not regularising the other concerned persons. The management is directed to regularise Shri Manesh Ram Mahato in Cat. I with effect from the date when the reference was made to this Tribunal i.e. with effect from 24-12-85 within one month from the date of publication of the Award.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-24012/37/85-D. IV(B)/IR (Coal) 11]

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1989

क.अ. 767—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि. की पूर्वी कटरल कोलियरी के प्रबन्धनत्व में सम्बद्ध निरोधकों और उनके कामगारों के बीच, अतुल्य में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिनियम में, 2 धनबन्ध के पंचाद को प्रकटित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-3-1989 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 29th March, 1989

S.O. 767.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure in industrial dispute between the employers in relation to the East Katras Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 21st March, 1989.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 246 of 1986

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of East Katras Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen—Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

On behalf of the employers—Shri B. Joshi, Advocate.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 14th March, 1989

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(70)/86-D. III(A), dated, the 8th July, 1986.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of East Katras Colliery of Katras Area of M/s. Bharat Coking Coal Limited in superannuating from service their workman, Shri A. K. Bannerjee, Clerk Grade-I in July, 1985 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

The case of the workman is that the concerned workman, Shri A. K. Bannerjee was a permanent workman at East Katras Colliery of M/s. BCCL and he was Clerk Grade-I. The age of the concerned workman in July, 1985 was 55 years. In his School leaving certificate the date of his birth is 15th June, 1930. At the time of his appointment his date of birth was recorded as 15th June, 1930 by the erstwhile management in Form B Register. He had passed the Mining Sirdar Ship examination and was issued with a certificate mentioning his age as 30 years in April, 1957. The said certificate was issued under the Mines Act by the department of Mines. The statutory certificate under the Mines Act is issued to a person after holding medical examination by Doctor. As per Medical examination of the doctor of the department of Mines the age of the concerned workman was assessed as 30 years on

21st April, 1957. The management had published seniority list on 10th February, 1983 in which the date of birth of the concerned workman was mentioned as June, 1928. All the aforesaid documents show that at the time of superannuation the age of the concerned workman was much below 60 years. In spite of the aforesaid facts the management superannuated the concerned workman with effect from 1st July, 1985 illegally, arbitrarily and in violation of the statutory documents and finding of the Medical Board. The concerned workman represented several times before the management to accept atleast the age determination by the Medical Board of the Department of Mines but without any effect. The union of the workmen raised an industrial dispute before the ALC(C), Dhanbad who took up the matter in conciliation. The conciliation failed and thereafter the Ministry of Labour referred the present dispute to this Tribunal for adjudication. On the above facts it is submitted that the action of the management in superannuating the concerned workman with effect from July, 1985 was against their own documents and against the statutory document issued by the Department of Mines under the Mines Act. On the above facts it is prayed that the management be directed to reinstate the concerned workman with full back wages.

The case of the management is that the date of birth of the concerned workman recorded in Form B Register maintained under Section 43 of the Mines Act, 1952 is 1st July, 1925. He was taken over employee and the date of birth was filled up in Form B Register of M/s. BCCL, the present management, on the basis of the entry made in Form B Register of the erstwhile employers. The concerned workman was a clerk and in token of correctness of the entries made in Form B Register had put his signature against the entry of his name. The concerned workman was a members of coal Mines Provident Fund which was filled up at the time when the concerned workman became the initial member of the C.M.P.F. during the period when the colliery was under the erstwhile management. The date of birth of the concerned workman mentioned in the C.M.P.F. record was 1st July, 1925. In the identity card the age of the concerned workman was recorded as 51 years on 1st January, 1977. The calculation of age on 1st January, 1977 was made from 1st July, 1925 and it came to 51 years 6 months but was recorded as 51 years. The concerned workman was superannuated in July, 1985 after he had attained the age of 60 years and as such he cannot have any grievance that he was prematurely superannuated. The concerned workman had not protested regarding their accurate recording of his age in the Form B Register, Identity card and the C.M.P.F. record. He has raised this dispute after his superannuation with the hope of earning money without doing any work.

The concerned workman had produced the Mining Sirdar certificate at the time of raising the present dispute and claimed that his age was 30 years on 21st April, 1947 and that his date of birth should be taken as 21st April, 1927. It is submitted on behalf of the management that the age in the Mining Sirdar certificate is recorded on the basis of a certificate granted by a Gazetted Officer or by the Headmaster of School and such certificates are given on the basis of eye estimation in respect of non-matriculate. In case of Matriculates, the matriculation certificate becomes the basis for recording the age in the Mining Sirdar certificate. A workman after putting a minimum of 3 years Mining Experiences can appear in Mining Sirdar examination. Thus the application submitted for appearing in the Mining Sirdar examination after entry of his date of birth in Form B Register and C.M.P.F. record. The subsequent age in the Mining Sirdar certificate therefore cannot be accepted as correct age when the concerned workman had already declared his date of birth in Form B Register and C.M.P.F. record. The Mining Sirdar certificate merely contains approximate age and not the date of birth. The concerned workman had been asked by the management to show the proof of his age and accordingly the concerned workman produced one certificate purported to be his School Leaving Certificate showing his date of birth as 15th June, 1930. Thus the age/date of birth in two of the documents, namely, the Mining Sirdar certificate and School Leaving Certificate do not tally. The School Leaving Certificate was procured on false representation of facts to suit the need of the concerned workman. On the above facts it is submitted on behalf of the management that the concerned workman is not entitled to any relief.

The point to be considered in this case is whether the concerned workman was correctly superannuated with effect from July, 1985.

The workmen and the management have each examined one witness in support of their respective case. The documents of the management have been marked Ext. M-1 to M-5 and the documents of the workmen are marked Ext. W-1 to W-5.

Admittedly, the concerned workman has been superannuated with effect from 1st July, 1985. It is also admitted case of the parties that the age of superannuation of a workman in the Coal Mine is 60 years. The management has produced Ext. M-3 which is said to be the Form B Register which was prepared by the management after its nationalisation on the basis of the Old Form B Register of the erstwhile management. Sl. No. A-64 of Ext. M-3 shows that no age or date of birth of the concerned workman was recorded but it shows that the employment of the concerned workman commenced from 12th May, 1947. The said entry in Ext. M-3 is signed by the concerned workman. But the concerned workman W-1 has stated that the erstwhile management had entered his age and other particulars in Form B Register at the time of his appointment in which his age was recorded as 15th June, 1930 and that the said date of birth was also noted in Form A of C.M.P.F. The concerned workman is a literate person working as a clerk Grade-I and knew English quite well. The fact that the concerned workman had signed against the entry in his name in Ext. M-3 shows that there was no entry of age/date of birth of the concerned workman in Form B Register of the erstwhile management. W-1 has stated that Ext. M-3 is the photo copy of Form B Register containing the signature of the concerned workman. The signature of the concerned workman appears to have been obtained on 24th June, 1981 as the concerned workman himself has dated it. In this Form B Register Ext. M-2 the date of birth of the concerned workman is shown as 1st July, 1925 as per C.M.P.F. records. Although the concerned workman had signed this Form B Register Ext. M-2 on 24th June, 1981 no objection was raised on his behalf that the date of birth recorded as 1st July, 1925 in Form B Register was incorrect or that it was not in accordance with the entry of his date of birth in the P.F. records. On looking to Ext. M-5 which is Form A of the C.M.P.F. it will appear that the date of birth of the concerned workman was recorded as 1st July, 1925. This Form was filled up on 1st December, 1948 and bears the signature of the concerned workman. The commencement of employment of the concerned workman was with effect from 12th May, 1947 and this Form A was filled up only after about 1-1/2 years. Although Ext. M-5 Form A was signed by the concerned workman in the year 1948, he did not raise any objection regarding his age in Form A of the C.M.P.F. It is thus quite clear that the date of birth of the concerned workman was recorded as 1st July, 1925 in Form A of the C.M.P.F. and Form B Ext. M-2.

Ext. M-4 is the identity card register. There is no record of age against the name of the concerned workman which is entered in Sl. No. 55. Identity card is prepared on the basis of the entry in the identity card Register and the particulars in the identity card register are made on the basis of the entries in the Form B Register. It appears that originally there was no entry of date of birth/age of the concerned workman in Form B Register of the erstwhile management or in the earlier Form B Register prepared by the management and as such there was no entry of age in the identity card register Ext. M-4. Even if the identity card Ext. W-4 is taken into consideration it does not support the case of the workmen that the date of birth of the concerned workman was 15th June, 1930. The age of the concerned workman in Ext. W-4 is recorded as 51 years on the date of its issue 1st January, 1977 and as such the calculation of age in Ext. W-4 is more in consonance with the age/date of birth as that of the management.

The workmen have produced the photo copy of Mining Sirdar Certificate Ext. W-1. In this certificate the age of the concerned workman is mentioned as 30 years on 21st April, 1957. The certificate is no doubt issued under the Mines Act regarding passing of the examination and the age recorded in the certificate is no proof of the fact that the concerned workman was aged 30 years on 21st April, 1957. There is absolutely no evidence to show as has been stated in the

W.S. of the workmen that the age recorded in the certificate Ext. W-1 was mentioned on the basis of any medical report or it was recorded on the basis of any School Leaving Certificate of the concerned workman. Ext. W-5 is the photo copy of School Leaving Certificate issued in the name of the concerned workman. It has been filed to show that the date of birth of the concerned workman was mentioned as 15th June, 1930 in his School Leaving Certificate. The concerned workman has not asserted that he had produced the certificate at the time when he had joined the services with the erstwhile management. This School Leaving Certificate Ext. W-5 was not in existence at the time when the concerned workman had commenced his employment. It appears that the date of issue of Ext. W-5 was 1st July, 1957 and as such it is evident that the concerned workman had not produced his School Leaving Certificate at the time of his appointment. The Form A of the C.M.P.F. Ext. M-5 dated 1st December, 1948 mentions the date of birth of the concerned workman as 1st July, 1925. If the date of birth of the concerned workman in his School Leaving Certificate was 15th June, 1930 he must have mentioned the said age in Form A Ext. M-5. It would have been a different matter if the concerned workman was illiterate person. The concerned workman was quite literate and he would not have kept silent after his date of birth was entered in Ext. M-5 even after he had obtained his School Leaving Certificate Ext. W-5. It will not be wrong to conclude that the School Leaving Certificate Ext. W-5 was subsequently obtained to support the case of the concerned workman although the same was not in existence before.

Ext. W-2 dated 10th February, 1983 is the seniority list of Grade-I clerks issued by the management in which at Sl. No. 66 there is entry of the name of the concerned workman which will show that the date of birth of the concerned workman is recorded in it as June, 1928. The management have, of course, no paper with it to show that the date of birth of the concerned workman was in June, 1928 and this entry was made on unconnected record of the management. Moreover, this does not support the case of the workmen. The date of birth noted in Ext. W-2 is not of much value as it is the case of neither of the parties that the date of birth of the concerned workman was in June, 1928.

The workmen have filed Ext. W-3 which provides the procedure for determination/verification of the age of the employees. It provides about the review/determination of date of birth in respect of existing employees. It provides that whenever there is no variation in the record, such cases will not be reopened unless there is a very glaring apparent wrong entry brought to the notice of the management. The management after being satisfied on the merits of the case will take appropriate action for correction through age determination committee/medical board. The advantage of this provision can be had by the workmen only if there is any variation in the record of the management. There is absolutely no evidence to show that there was any variation in the recording of age of the concerned workman in the record of the management. The documents produced on behalf of the workmen regarding the age/date of birth of the concerned workmen are not statutory records of the management as such they cannot be considered for showing that there is variation of the date of birth/age of the concerned workman in the records. In this view of the matter I do not see the necessity of referring the concerned workman to the Medical Board or the age determination committee for determination of his date of birth.

In view of the evidence discussed above it appears that the date of birth of the concerned workman was 1st July, 1925 and that there was no variation in his date of birth/age in the records of the management. Accordingly the concerned workman appears to have been rightly superannuated with effect from 1st July, 1985 when he attained the age of 60 years calculated from his date of birth as 1st July, 1925.

In the result, I hold that the action of the management of East Katras Colliery of Katras Area of M/s. BCCL in superannuating from service the concerned workman Shri A. K. Banerjee, clerk, Grade-I in July, 1985 is justified and consequently the concerned workman is entitled to no relief.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012/70/86-D. III (A)/IR (Coal-I)]

का.अ. 768:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की लोहापटी कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध निराश्रितों और उनके कर्मकरों के बीच, अनुबन्ध में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकारण, सं. 1 धनबाद के बंचट का प्रकृति करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-3-1989 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 768.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Lohapati Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 20-3-1989.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 30 of 1988

PARTIES :

Employers in relation to the management of Lohapati Colliery of M/s. B.C.C.Ltd.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. N. Prasad, Advocate.

For the Workman—Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

STATE : Bihar.

INDUSTRIAL : Coal.

Dated, the 7th March, 1989

AWARD

The present reference arises out of Order No. L-20012-(185)/87-D.III(A), dated, the 5th February, 1988 passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows :—

“Whether the action of the management of Lohapati Colliery of M/s. B.C.C.Ltd., P.O. Ramnagar Garh, Distt. Dhanbad in dismissing Shri Tarapada Karmakar, Miner/Loader from 29-11-84 is justified? If not, to what relief the workmen is entitled?”

2. The dispute has been settled out of Court. A memorandum of settlement has been filed in Court. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be made on the basis of terms and conditions laid down in the memorandum of settlement. I accept it and make an award accordingly. The memorandum of settlement shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

S. K. MITRA, Presiding Officer

[No. L-20012/185/87-D.III(A)/IR(Coal-1)]

Reference No. 30/88

FORM 'H'

(See Rule 58)

Form for Memorandum of Settlement

Name of the Parties :

General Manager, Mohuda Area
No. 2, M/s. Bharat Coking Coal
Limited.

—Representing the

Employer

1. Sri B. Mahanty
Secretary, Bihar Colliery
Kamgar Union.

—Representing the

Workmen

2. Sri Tarapado Karmakar
Lohapati Colliery.

SHORT RECITAL OF THE CASE

Sri Tarapado Karmakar was dismissed by the Management of BCCL for his alleged unauthorised absence from duty

His Union Bihar Colliery Kamgar Union raised an industrial dispute alleging that the dismissal of Sri Karmakar was wrongful and illegal. After failure of the conciliation and receipt of the failure report the Central Govt. have referred this dispute to the Honourable Tribunal No. 1 Dhanbad on the following terms of reference, vide their order No. L-20012(185)/87-D-III(A) dt. 5-2-1988;

“Whether the action of the management of Lohapati Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. : Ramnagar Garh, Distt. Dhanbad, in dismissing Sri Tarapado Karmakar, Miner/Loader from 24-11-84 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?”

While the matter pending before the Hon'ble Tribunal under Ref. No. 30 dt. 1988, the parties have mutually negotiated as discussed this matter with a view to arriving at an amicable settlement. As a result of the discussion the parties have agreed to settle this dispute bilaterally on the following mutually agreed terms :—

TERMS OF THE SETTLEMENT

- (1) That the workman namely Tarapado Karmakar will be taken back in employment by the management with immediate effect.
- (2) That he will not be entitled for any wages during the period from his date of dismissal i.e. 29-11-84 and the date of his resumption of duty.
- (3) That the workman, however, will be given the continuity of service for the purpose of gratuity.
- (4) That the settlement is full and final in respect of all the claims arising out of this dispute;
- (5) That the parties consider and confirm that this settlement is just fair and beneficial for both of them;
- (6) That the parties shall file a copy of this settlement before the Hon'ble Tribunal No. 1 Dhanbad as a joint compromise petition and also jointly send copies to the Central Govt. Chief Labour Commissioner (C) New Delhi. RLC(C) Dhanbad and ALC(C) Dhanbad.

General Manager,

K. N. SINGH
Mohuda Area No. 2
for the Employer(s)

Sd/- Illegible

1. Secretary BCKU

2. Tarapado Karmakar
for the Workman L.T.I.

Witnesses :—

1. Sd/- Illegible

2. Sd/- Illegible

Copy to:—

1. Asstt. Labour Commissioner(C), Dhanbad.
2. Regional Labour Commissioner(C), Dhanbad
3. Chief Labour Commissioner(C), Dhanbad
4. Secretary to the Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.

Sd/-

General Manager,
Area No. 2

Secretary BCKU
Part of the Award.
Presiding Officer.

Sd/-

Advocate for the employee.

क. अ. 769.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) को धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, सैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की अमलाबाद कोलियरी के प्रबन्धन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकों के बीच, अनुबन्ध से निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, संख्या 2, धनबाद के पंचट को प्रकटित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-3-1989 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 769.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Amlabad Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 21-3-1989.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 55 of 1986

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Amlabad colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workman.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen—Shri S. Bose, Secretary, R.C.M.S. Dhanbad.

On behalf of the the employers—Shri B. Joshi, Advocate.

STATE : Bihar.

INDUSTRIAL : Coal.

Dated, Dhanbad, the 13th March, 1989

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/221/85-D.III(A), dated, the 20th January, 1986.

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Amlabad colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited in punishing and reverting Shri Rajak Mia from Category-I to Category-II is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?”

In this case both the parties made their appearance but did not file their respective W. S. Subsequently both the parties appeared before me and filed a petition of compromise. I heard them on the said petition of compromise and I do find that the terms contained therein are fair, proper and beneficial to both the parties. Accordingly I accept the same and pass an Award in terms of the petition of compromise which forms part of the Award as Annexure.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012/221/85-D.III(A) IR-(Coal-1)]

ANNEXURE A

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 AT DHANBAD

Reference No. 55/86

Employers in relation to the management of Amlabad Colliery

AND

Their Workmen

PETITION OF COMPROMISE

The humble petition on behalf of the parties to the reference most respectfully sheweth :—

1. That the Central Govt. by notification No. L-20012-(221)/85-D.III(2) dated 12-1-86, has been pleased to refer the present case to this Hon'ble Tribunal for adjudication on the issue contained in the Schedule of reference which is reproduced below :—

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Amlabad Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited in punishing and reverting Shri Rajak Mia from Category-III to Category-II is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?”

2. That the above dispute has been amicably settled between the parties on the following terms :—

TERMS OF SETTLEMENT

(a) That the concerned workman Sri Raja Mia will be put back on his original job of Fan Operator in Category-III with immediate effect. The period of his demotion from Category III to Category II will be treated as cancelled.

(b) That the concerned workman will be paid the amount of Rs. 4002.27 (Rupees four thousand two & twenty seven paise only) in full and final settlement of difference of his wages for the period of demotion and he will have no further claim in this regard.

(c) That the continuity of service of the concerned workman in Category-III will be maintained without any break during the period of his demotion.

3. That in view of the above settlement there remain nothing to be adjudicated

Under the facts and circumstances stated above the Hon'ble Tribunal will be graciously pleased to accept the Settlement.

ment as fair and proper and be pleased to pass the Award in terms of the settlement.

For the workman

Sd/-Illegible

Sd/-Illegible

For the Employer

Sd/-Illegible

Sd/-Illegible

Witnesses

1. Sd/-Illegible

2. Sd/-Illegible

L.T.I.

of Mohan Raut, Driller

E.B. 231928

का.प्र. 770:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की गोविन्दपुर कोलियरी के प्रबन्धनत्व से सम्बद्ध नियोक्तों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद से केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 1, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-3-1989 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 770.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Govindpur Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 20-3-1989.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 68 of 1983.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Govindpur Colliery of M/s. B.C.C. Ltd.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri B. Joshi, Advocate,

For the Workmen.—Shri D. Mukherjee, Secretary,
Bihar Colliery Kamgar Union.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dated, the 28th February, 1989

AWARD

By Order No. L-20012(147)/83-D.III(A), dated, the 19th September, 1983, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

“Whether the demand of the workmen of Govindpur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonardih, District Dhanbad that the management should treat the Clay Cartridge Mazdoor specified in the Appendix below as their workmen and pay category-I wages to them is justified? If so, to what relief are these workmen entitled and from what date?”

APPENDIX

Sl. No. name of the workmen

1. Kisto Bouri
2. Gopal Bouri
3. Biju Kamin
4. Kali Kamin
5. Rabani Kamin
6. Netai Bouri
7. Sahadeo Bouri
8. Santi Kamin
9. Mani Kamin
10. Punia Devi
11. Ramlal Bhuiya
12. Siblal Bhuiya
13. Kamli Kamin
14. Santi Kamin
15. Alsawa Kamin
16. Sabiti Kamin
17. Etneria Kamin
18. Ram Baran Mahato
19. Bhago Mahato
20. Sina Bhuiya
21. Jirua Kamin
22. Muturia Kamin
23. Ashok Kumar
24. Ramashish Saw
25. Tanik Saw
26. Bhim Narain Ram
27. Phaguni Devi
28. Lacham Deswani
29. Manoj Singh
30. Nagna Bhuiya
31. Bideshi Bouri
32. Arun Bouri
33. Panchanan Bhuiya
34. Chinta Kamin
35. Bhola Rabidas
36. Panwa Devi
37. Chamalua Kamin
38. Rajo Kamin
39. Shama Bhuiya

2. The case of the concerned workers as appearing from the written statement submitted by the sponsoring union, Bihar Colliery Kamgar Union, details apart, is as follows :—

The management of Govindpur Colliery of M/s. B.C.C. Ltd. has been extracting coal through blasting since long and clay cartridge is absolutely necessary for extracting coal through blasting and that no coal can be extracted without clay cartridge. The concerned workers have been working as Clay Cartridge Mazdoors in the colliery since long. They have been working as permanent Clay Cartridge Mazdoors within the precincts and premises of the colliery and their work is permanent and perennial in nature directly linked with the production of coal. All the necessary implements or making clay cartridges are being supplied by the management and the concerned workers have been working under the direct control and supervision of the management. Central Coal Wages Board recommendations have been implemented by the management and these recommendations contain the job description and category of Clay Cartridge

Mazdoors. As per Wage Board recommendations all the concerned workers are entitled to Category-I wages and other benefits as Clay Cartridge Mazdoors. The management, so it is alleged, has been disbursing their wages through intermediaries with an ulterior motive to deprive the poor workers of their legitimate claim of regularisation and wages as per Wage Board Recommendations. It is also further alleged that the management has not been maintaining statutory records with respect to the concerned workers in order to cheat them. They are active members of Binar Colliery Kamgar Union and the management is biased and prejudiced against them for their union affiliations. The concerned workers and their union demanded several time for treating them as departmental workmen and payment of Category-I wages, but without any effect. In the circumstances, the union raised an industrial dispute which the appropriate Government has been pleased to refer to this Tribunal for adjudication. The action of the management in not treating the concerned workers as departmental workers and payment of less than Category-I wages are illegal, arbitrary and unjustified. In the circumstances, the union has prayed that the concerned workers be regularised as workers of the colliery with effect from 1-5-1972 with all consequential benefits.

3. The case of the management of Govindpur Colliery of M/s. B.C.C. Ltd., briefly stated, is as follows :

The management has introduced solid blasting after obtaining permission from the Director General of Mines Safety, Dhanbad. Clay cartridges are nothing but earth pellets of cylindrical in shape with about 2.5 cm in diameter and 30 cm. in length. These cartridges are prepared from earth drenched with water. For the purpose of stemming the shot holes clay cartridges were required and the management started purchasing the same from local manufacturers. The local people dig earth from surface wherever the same is available, drench the same with water and normally prepare the cartridges by hands. No skill is required as the same can be prepared also by women and children. The local people sell the clay cartridges at the varying rates of Rs. 10 to Rs. 8 per thousand at different collieries. The management of the colliery purchases the clay cartridges at the rate of Rs. 8 per thousand of clay cartridges. Out of the 39 persons given in the list annexed to the reference two persons, namely, Smt. Matarna Kamin (Sl. No. 22) and Lachman Deswali (Sl. 28) supplied clay cartridges to the management during certain period of time. The management also purchased clay cartridges from other, namely, (i) Maloty Kamin and (ii) Sri Mangar Bhuia, (iii) Atwar Bhuia and (iv) Nepal Bhuia. Thus, the management purchases clay cartridges from the aforesaid six persons. The sellers of clay cartridges prepare the same with the help of their family members and others. The management does not supervise their work nor does it exercise any control over their work. Nothing is supplied to them by the management for making clay cartridges. There exists no employer-employees relationship between the management and clay cartridge makers. The suppliers sell clay cartridges and the management purchases the same and such clay cartridge suppliers cannot be employees of the management. Except the two persons, namely, Sl. No. 22 and 28 who are suppliers, all the persons included in the list annexed to the schedule of the reference are strangers. They are not even suppliers, what to speak of being employees. Considering the better service conditions and good pay structure of the management, many persons are trying to enter into the services of the management by adopting unfair means. It is alleged that the concerned persons, posing themselves as workers of clay cartridge suppliers intend to enter into services with the help of litigation. The management has not engaged any machine for manufacture of clay cartridges since the same are available from the local market. The management purchases large varieties of materials from the local market and persons engaged in preparation and manufacture of those materials cannot claim to be employees of the collieries. In the circumstances the management has proved that the instant reference case be dismissed.

4. In rejoinder to the written statement of the management the sponsoring union has asserted that the present re-

ference is maintainable and reiterated that the clay cartridge is absolutely essential for running of the colliery and for production of coal. The union has also asserted that clay cartridge makers are entitled Category-I wages as per Wage Board Recommendations and that the concerned workers dig earth from the surface of the colliery and drenched the same with water supplied by the management. It is alleged that the management with ulterior motive to cheat the poor workmen, have been paying them less wages than recommended by Wage Board recommendations on piece-rated basis though they should be treated as time-rated workmen. Maloty Kamin is permanent worker of Govindpur Colliery and Nepal Bouri a permanent Miner/Loader of South Govindpur Colliery. Hence, it is clear that preparing all bills in the name of the aforesaid workers for payment to the concerned workers is nothing but legal camouflage and unfair tactics adopted by the management, in order to deprive the poor workers of their legitimate claim. The union has reiterated that the management supplies the concerned workmen all materials for preparing of clay cartridges and supervises their work. The union has also asserted that there is no machine to prepare clay cartridges.

5. In rejoinder to the written statement of the workmen the management has denied all the materials averments as made in the written statement of the union. It has been asserted that job of clay cartridge mazdoors is neither permanent nor perennial in nature, but has admitted that extraction of coal is done through blasting and that for the purpose of blasting clay cartridges are absolutely essential.

6. The sponsoring union has examined three witnesses, namely, W.W-1 Kisto Bouri, W.W-2 Bhola Rabidas and W.W-3 Promod Kumar Jadia earlier posted as Labour Enforcement Officer (C), Baghmara and laid in evidence a sheaf of documents which has been marked Exts. W-1 to W-6. On the other hand, the management has examined three witnesses, namely, MW-1 Atul Chandra Ray, now working as Clerk in Govindpur Colliery, MW-2 V. N. Prasad, earlier working as Welfare Officer (Trainee) and now working as Personnel Officer, South Govindpur Colliery and MW-3 M. Jha, Agent of Govindpur Colliery for last four years and laid in evidence a mass of documents which has been marked Exts. M-1 to M-8.

7. One of the main issues taken by the management in opposition to the demand of the sponsoring union is that the present reference is not maintainable. Sri B. Joshi, learned Advocate for the management, has not pressed this point home at the time of hearing of the case. The sponsoring union has, through this reference, demanded of the management for treating the workers listed in the reference as Clay cartridge mazdoors of the colliery. That being so, I come across nothing illegal or irregularity in the demand of the union. Hence inescapable conclusion is reached that the present reference is maintainable.

8. The management, it appears, has casually introduced the story of solid blasting in the colliery without reference to the date and year when such method was introduced. The casualness in the approach of the management in the matter will be evident from the relevant para of the written statement of the management itself which reads as follows :

"Para 3.—that the management introduced solid blasting in the year.....after obtaining permission dated..... from the Director General of Mines Safety, Dhanbad."

No doubt averments in the written statement are considered to be very important matters, but the management has taken the matter very lightly and has kept the space for commencement of the year and date of solid blasting blanks. This is really unfortunate, to say the least. The written statement of the management envisages that clay cartridges are required for stemming the shot-holes and the management purchases the same from local manufacturers.

9. The report of the Central Wage Board for Coal Mining Industry in Appendix V at Sl. No. 26 envisages the designation of Clay Cartridge Mazdoor and job description of such mazdoors which reads as follows :

"Clay Cartridge Mazdoors—a person who makes clay Cartridges of about 1-1/2" diameter and 6" long for stemming shots when shot firing is done (those formerly designated as 'Goli Matti' or 'Mud Pellet' Mazdoors while henceforward be known as Clay Cartridge Mazdoors)."

Thus, it is evident that clay cartridges are used for stemming shots when shot firing is done obviously in order to extract coal by blasting.

It is an irrefragable position that the management of Govindpur Colliery has been extracting coal by blasting method. Para 4 of the written statement of the sponsoring union reads as follows :

"That the management has been extracting coal through blasting since long and for the purpose of extracting coal through blasting clay cartridge is absolutely essential."

In the rejoinder to the written statement of the sponsoring union the management has accepted this position by stating as follows :

"That the contents of para 4 of the written statement of the workmen are substantially correct."

Even MW-3 M. Jhu posted as agent of Govindpur Colliery for the last four years has stated that during his tenure of office at Govindpur Colliery coal has never been raised by having recourse to pick mining method and that coal is extracted from the mine and in development by solid blasting and blasting depillaring. He has admitted that for solid blasting or blasting every shot-hole should be stemmed by non-inflammable method and that all the shot-holes are stemmed by clay cartridge and so clay cartridge is necessary for extraction of coal by solid blasting or blasting. This being the position, the conclusion is reached that the management of Govindpur Colliery of M/s. B.C.C. Ltd. has been extracting coal by the method of blasting or solid blasting and that clay cartridge is absolutely essential for extracting coal by blasting or solid blasting. Hence, it follows that in order to keep up the flow of production of coal there exists constant requirement for clay cartridge in the aforesaid colliery and that clay cartridges are directly linked with the production of coal in the said colliery.

10. Shri B. Joshi has submitted that clay cartridges are supplied to the colliery by the suppliers who are local manufacturers and the management has got no relationship of employer and employee with the suppliers. He has further submitted that only two persons, named at Sl. No. 22 and 28 are the suppliers of clay cartridges and all other persons listed in the reference are strangers. According to him, since the management has got no relationship of employer and employee with the concerned persons the present reference must be answered in favour of the management.

On the other hand, Shri D. Mukherjee, authorised representative of the sponsoring union, has submitted that clay cartridges are made in the precincts of the colliery by the concerned persons for use of the colliery and that the materials and tools for making clay cartridges are supplied by the management and that he management has got supervision and control over the concerned workmen. He has further submitted that apparent shall not be taken to be the real state of affairs and that when a worker or a group of workers labours to produced goods or services and these goods or services are for the business of another, that other is, in fact employer. Sri Mukherjee has cited before me the decision reported in 1978 Lab. I.C. 1264 (Hussainbhai Vs. The Alath Factory Tezhilali Union & others).

Sri Joshi has contended that this decision has got no manner of application in the present case since that was rendered in connection with the case of a contractor's workmen. In my view the ratio of the decision cannot and should not

be circumstances to the case of contractor's workmen only. The decision underlines the principle when a worker or group of workers labours to produce goods or services for the business of another person, that person is the real employer. In the present case it has to be seen if the concerned workmen labour to produce goods or services for the business of the management.

11. I have already held that coal is extracted in Govindpur Colliery by the method of solid blasting and blasting and that for doing so clay cartridges are essential and further that clay cartridges are essential to keep up the momentum of production of coal in the colliery. I have also held clay cartridges are directly linked with the production of coal in the colliery.

12. WW-1 Kisto Bouri, one of the concerned workers, has stated that he has been working in the Govindpur Colliery of M/s. B.C.C. Ltd. since 1980 as Clay Cartridge Mazdoor and that other persons listed in the reference are working in the same capacity in the said colliery. He has further stated that they have been working continuously and on all working days they do their jobs near the side of incline of the colliery. He has emphatically stated that M/s. B.C.C. Ltd. supply that soil required through its dumper and also supply them with picks (gaita), cane-basket (Jhora), shovels (belcha) etc. and that the management has constructed 'Saira' (surface water reservoir) for reservation of water for doing their jobs and that they utilise the water so reserved for their jobs. According to him, clay cartridges are dried by fire of coal supplied by the management and inspection of their job is done by Hazari Babu in order to ascertain if the jobs have been fitfully done or not he has further testified that Labour Enforcement Officer paid a visit to the colliery for inspection and that he could find 31 workmen on the date of his inspection and others were not found present since they went to pay respect to a deceased who died on that date. It is the admitted position that the concerned workers are not treated as regular workmen of the colliery and that the management pays the suppliers of clay cartridges on the basis of bills raised. WW-1 Kisto Bouri has stated that the management has also raised bills in his name. This is also evident from a document of the management relating to statement showing No. of clay cartridges supplied (Ex. M-6). Although grilled in cross-examination this witness has struck to the basic facts as emerging from his evidence. In cross-examination he has stated that the boiler is fed by the water of water reservoir and that it is not a fact that the water to the boiler and not for job of making clay cartridges. No witness for the management has vouched for the fact that water reservoir was constructed only for feeding water to the boiler. WW-2 Bhola Rabidas another concerned workman, has stated that he has been working in Govindpur Colliery for the last ten years as clay cartridge mazdoor and that the other workmen listed in the reference who are known to him have been working in the said colliery in the same capacity. He has further stated that they have been preparing clay cartridges near the incline of the mine and that the soil required for making clay cartridges is supplied by M/s. B.C.C. Ltd. through dumper and water for preparation of clay cartridges is also supplied by M/s. B.C.C. Ltd. and that during rainy season clay cartridges are kept inside the Varandah of the Attendance Room and that baskets and shovels are also supplied by M/s. B.C.C.L. in order to help the process of making of clay cartridge. He has also stated that they have been working as clay cartridge makers in all days except Sunday in every week and that they have been doing their duties for eight hours from 8 a.m. to 4 p.m. every day and get payment of Rs. 5 or Rs. 6 per head from M/s. BCC Ltd. He has denied that they prepare clay cartridges and sell the product to M/s BCC Ltd. and asserted that Hazri Babu supervises their work. He has also testified that one officer from Labour Officer paid a visit one day when some amongst them were absent as they had gone to attend the last rites of Lakshman Deshwali who expired on that day. In cross-examination he has stated that they have got no paper to show that soil is supplied by M/s. BCC Ltd. through dumper, but thereafter he has stated that they have got some papers to show that baskets and shovels are supplied by M/s. BCC Ltd. The sponsoring union has filed a chit or slip signed by Sri N. K. Sinha,

Asst. Colliery Manager to one Md. Alam, P.C. Loader directing him to load a haul-pak and to make over the same to Magru Bhuia to make cartridge (Ext. W-4). The union has also filed a store requisition slip signed by the Time Keeper Dayaram Raja, Asst Colliery Manager Sri N. Verma and Manager P. K. Singh for supply of cane baskets (Ext. W-5). The evidence of this witness has remained unflinched in cross-examination. WW-3 Promod Kumar Jadia was posted as Labour Enforcement Officer (C) to Baghmara from 16-4-84 to 14-6-86. His evidence disclosed that he held spot verification at the direction of A.L.C. (C) Dhanbad and that the A.L.C. (C) directed him to make spot verification. At the instance of A.L.C. (C) who made his endorsement directing him to make the spot verification on the letter of the Secretary of the sponsoring union (Ext. W-2/1). It appears that the Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union wrote to the A.L.C. (C) Dhanbad on 31-1-84 (Ext. W-2) for spot verification at Govindpur Colliery in connection with present workers working as clay cartridge mazdoors and that the A.L.C. (C) directed the Labour Enforcement Officer to make spot verification and submit his report. Accordingly Sri Jadia made a spot verification and submitted his report. Sri Jadia has proved the report submitted by him which has been marked Ext. W-7. He has stated that the representative of the management Sri V. Prasad signed the report at the end in his presence and the signature of Sri Prasad has been marked Ext. W-1/1. Sri Satish Prasad Mondal, representative of the sponsoring union has also signed it with date in his presence which has been marked Ext. W-1/2. Sri Jadia has stated that the names of the workers who were found working in the spot have been noted by him and that the obtained their thumb impression also. The representative of the management signed the sheet containing the names of the workers in his presence which has been marked Ext. W-A/1 and Satish Prasad Mondal, representative of the workers, signed the report also in his presence (Ext. W-A/2).

Sri B. Joshi, learned Advocate for the management, has criticised the report of the Labour Enforcement Officer in various manners his first contention is that the spot verification report (Ex. W-1) does not contain the signature of Sri V. N. Prasad for the management. In order to prove this he gave a suggestion to Sri Jadia that spot verification report does not contain the signature of Sri V. N. Prasad, but Sri Jadia had denied this which means that the verification report contains the signature of Sri V. N. Prasad. The opposing taken by Sri Joshi that the verification report does not contain the signature of V. N. Prasad has become a damp squib because V. N. Prasad figuring as MW-2 has identified his signature Ext. W-1/1 and W-A/1. Thus, it is evident that the spot verification report contains the signature of V. N. Prasad. Then, the next plea of Sri Joshi is that V. N. Prasad was not present at the time of inspection but that his signature was obtained by Sri Jadia, Sri V. N. Prasad figuring as MW-2 has stated that in 1983 he joined M/s. B.C.C. Ltd. as Welfare Officer (Trainee) and that on 29-10-84—the date when spot verification was made by Sri Jadia—he was posted to Govindpur Colliery in the same capacity and that in 1986 he became Welfare Officer and is now posted in South Govindpur Colliery as Personnel Officer. His testimony is that Labour Enforcement Officer came to the Colliery, prepared a report and called upon him to sign and that at first he was reluctant to sign since he was a new entrant and had no authority whatsoever and that on his insistence he signed it. In cross-examination he has admitted that Labour Enforcement Officer did not coerce him to sign the report. Sri Prasad is now aged 30 years and in 1984 he was about 26 years of age presumably having a good education. It is preposterous to believe that a man of his timber simply signed the report at the insistence of Labour Enforcement Officer without being present at the time of inspection and that too without any authority. Sri Prasad seems, according to his testimony, to have eaten out Sri Jadia's hand which is very difficult to believe. Sri Jadia has emphatically stated in his report Ext. M-3 that the representatives of the union and the management were with him during the above spot verification. He has further stated that he made the spot verification after notice to both the union and the management and that Sri Prasad verbally told him that he had got authorisation to represent the management and that he submitted his report to Asst. Labour Commissioner (C) Dhanbad. It appears that Sri Jadia forwarded copies of his report to the Secretary of the sponsoring union and to the Manager, Govindpur Colliery as well. WW-3

M. Jha Agent of the Govindpur Colliery, has stated that as Agent of the Colliery he had no information about the inspection of Sri Jadia and that he came to know about his inspection after the case was referred to in this Tribunal and the person purported to have signed the inspection report on behalf of the management i.e. Sri V. N. Prasad was not competent to do so since he was Welfare Officer (Trainee). In cross-examination he has stated that when he came to know that Welfare Officer (Trainee) signed the report of Sri Jadia, he did not take any action against him or warned him in writing, but that he was warned verbally. But V. N. Prasad has not stated that he warned verbally by the Agent of the Colliery for signing the report of the Labour Enforcement Officer without authorisation. It appears that Sri Jadia has submitted a copy of this report to the Manager, Govindpur Colliery and in spite of this MW-3 M. Jha has feigned his ignorance about the report. The management has not produced any documentary evidence in support of the fact that Sri Prasad was not authorised by the management to attend and sign the verification report of Labour Enforcement Officer. That being so, I am not prepared to believe that Sri V. N. Prasad, Welfare Officer (Trainee) did not attend the spot verification of Sri Jadia and that he had no authority for having done so.

13. WW-3 Sri P. K. Jadia has stated in his testimony that he found workers listed in his report working at a place adjacent to the pit of the mine and that he also saw M/s. B.C.C. Ltd. providing working implements to the workmen and also providing them material i.e. earth required for their work. His report discloses the names of the most of the workmen listed in the reference. In his report he has also stated that he found the workmen working near the mouth of various pits of Govindpur Colliery that they are paid Rs. 8 per thousand clay cartridge by vouchers and that vouchers are usually prepared in the name of one of the senior workmen of the group. In his report (Ext. W-1) Sri Jadia has stated that the working places of the concerned workers are fixed and that 'Mati' for the purpose of making clay cartridges is dumped by M/s. B.C.C.L. equipment at the work site. MW-1 Atul Chandra Ray has not stated anything about the job performance of the concerned workers. So is also the evidence of MW-2. MW-3 M. Jha has denied that the concerned persons are employed for making clay cartridges for the Colliery. According to him, the suppliers prepare clay cartridges at their respective houses and supply the same to the Colliery and that an employee if M/s. BCCL cannot enter into a contract for supply of materials to M/s. B.C.C. Ltd. In the written statement of the management it has been stated that Maloti Kamin, Maegar Bhuia and Nepal Bhuia are some of the suppliers of clay cartridges to the management MW-1 Atul Chandra Ray has stated that all of them are regular employees of the Colliery. If that be so, it has remained inexplicable as to why Sri Jha has not taken any action against them for having entered into a contract for supply of clay cartridges to the Colliery or has not revoked or cancelled their contract.

14. It appears from the statement showing the number of clay cartridges supplied by the suppliers (Ext. M-6) that the names of Kisto Bouri (Sl. No. 1), Siblal Bhuia (Sl. No. 12), Netai Bouri (Sl. No. 6), Muturia Kamin (Sl. No. 22), Lacham Deswali (Sl. No. 28), Mani Kamin (Sl. No. 9) and Bideshi Bouri (Sl. No. 31) appear therein as suppliers. Besides, MW-1 M. Jha has admitted that Kali Kamin and Phaguni Devi are suppliers of clay cartridges to the Colliery. Thus, in all, it appears that there are nine suppliers of clay cartridges to the Colliery as per statement of the management. It appears that of these nine persons Lacham Deswali is admittedly dead as appears from the evidence of WW-2 Bhola Rabidas. That being so, there are only eight persons left whose names appear in the annexure to the schedule of reference. Sri Jadia has found name of the other persons listed in the reference working in the Colliery premises for making clay cartridges. There is no cogent evidence that these persons, apart from the persons named above, have been regularly doing the work of making clay cartridges. Hence, the claim of other workers except the persons named above to treat them as clay cartridge mazdoors is not sustainable. But the persons named above, namely, Kali Kamin (Sl. No. 4), Siblal Bhuia (Sl. No. 12), Phaguni Devi (Sl. No. 27), Muturia Kamin (Sl. No. 22), Nitai Bouri (Sl. No. 6),

Muni alias Mani Kamin (Sl. No. 9), Bideshi Bouri (Sl. No. 31) and Kist Bouri (Sl. No. 1) have been working for making clay cartridges for the Colliery. I have pointed out above that clay cartridge is linked with the production of coal in the Colliery and that the same is essential for production of coal in that Colliery. I have also pointed out that the workers have been working near the pits of the Colliery and that their work tools and materials are supplied by the management and that the management has got supervision over their work by selection of clay cartridges. That being so, it cannot but be concluded that they labour to produce goods for the business of the Colliery and hence the management of the Colliery is their real employer.

15. Perhaps, the management is not oblivious to this position. By letter dated 4-12-86 Personnel Manager (WJD). B. N. Jha wrote to the General Manager, Govindpur Area, that Bihar Colliery Kamgar Union demanded that this reference case should be settled amicably as per Company's policy decision and that after examining the matter it has been decided by the Director (Personnel) that in view of the Company's policy the dispute may be settled on the following lines :

"The workload for one clay cartridge maker will be 1000 cartridges per day of 9"×1½" size. They will be paid Category-I wages and will be treated as time-rated workers. (Ext. M-4)."

Another document—Notes on review meeting with B.C.K.U. at D(P)'s level held on 16-12-86, Area No. 3 (Ext. W-6) discloses that guideline for regularising clay cartridge makers in connection with this case has already been issued and the matter will be disposed of through settlement depending upon the merit of the case. MW 1 M. Jha has stated that the requirement of clay cartridge for the Colliery is 1000 to 5000 pieces per day. But this position the management has not taken in its written statement. In any view, the aforesaid persons, by right of their own, is entitled to be treated as Clay Cartridge Mazdoors and also entitled to get Category-I wages with effect from the date of the present reference i.e. 19-12-1983.

16. Accordingly, the following award is rendered—

the demand of the workmen of Govindpur Colliery of M/s. BCCU, P.O. Sonardih, Dist. Dhanbad that the management should treat the following clay cartridge mazdoors as their own workmen and pay Category-I wages to them is justified. The workmen named hereinbelow are entitled to be treated as Clay Cartridge Mazdoors with effect from 19th September, 1983 and back wages :

- (1) Kisto Bouri,
- (2) Kali Kamin,
- (3) Netai Bouri,
- (4) Muni alias Mani Kamin,
- (5) Siblal Bhuiya,
- (6) Mutnia Kamin,
- (7) Phagun Devi, and
- (8) Bideshi Bouri.

In the circumstances of the case, I award no cost.

S. K. MITRA, Presiding Officer
[No. L-20012/147/83-D.III (A)/IR (Coal-II)]
K. I. DYVA PRASAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1989

उ.क. 771:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इंजीनियर टर्नशाफ माइक्रोवेव, अम्बाला के प्रबन्धन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबन्ध में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चण्डीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-3-1989 को प्राप्त हुआ था।

910 GI/89—12

New Delhi, the 29th March, 1989

S.O. 771.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Engineer, Telegraph Microwave, Ambala and their workmen, which was received by the Central Government on 16-3-1989.

ANNEXURE

BEFORE SHRI M. S. NAGRA, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL
CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I. D. 49/88

PARTIES :

Employers in relation to the management of Engineer
Telegraph Microwave, Ambala.

AND

Their workman : Shangara Singh.

APPEARANCES :

For the workman—None.

For the management—None.

AWARD :

Dated : 20-2-1989

On a dispute raised by Shangara Singh workman of Engineer Telegraph Microwave Ambala, Central Government has been pleased to make the following reference vide No. L-40012/27/86-D.II (B) dated 25th March 1988 to this Tribunal :

"Whether the action of the management of Engineer Telegraph Microwave Ambala in terminating Shri Shangara Singh from service with effect from 7-3-1983 is legal and justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

2. Notice of the reference was issued to the workman Shri Shangara Singh who has failed to put up appearance inspite of service through regd. A.D. for today. The reference is therefore, dismissed for want of prosecution. Central Government be informed and the file be consigned to record.

Chandigarh,

Dated : 20-2-1989.

M S NAGRA, Presiding Officer
[No. L-40012/27/86-D.II (B)]
HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1989

उ.क. 772:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. आर.सी. एस. एस. एन कारीगार बल्लारी जिला की संकायापुस्तक आर्ट्स और माईन्स में टेक्नोलॉजी और पाठ्यपुस्तक के प्रबन्धन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबन्ध में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बंगलूर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-3-89 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 29th March, 1989

S.O. 772.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure,

in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Shri Pachappa, Contractor in Sankalapuram Iron Ore Mines of M/s. RBSSN, Kariganur, Bellary Distt. and their workmen, which was received by the Central Government on the 21-3-1989.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT BANGALORE

Dated, first day of March 1989

Central Reference No. 26. 51. 52. 36. 35. 37. 48. 49 & 50/88

In C.R. No. 26/88
I PARTY
Smt. Galemma
W/o Yamunappa Hospet
In C.R. No. 35/88
I Party
Shri Govendappa
S/o Rangaiah Hospet.

In C.R. No. 36/88
I PARTY
Shri Themnappa
S/o Govindappa Hospet.
In C.R. No. 37/88
I PARTY
Shri S. Obaleshi
S/o Sri Ningsappa Hospet.
In C.R. No. 48/88
I PARTY
Smt. Ramanjeneyamma,
W/o Themnappa Hospet.
In C.R. No. 49/88
Smt. Govindamma,
W/o S. Obaleshi, Hospet.
In C.R. No. 51/88
I PARTY
Shri Sanjeevappa,
S/o Hulivappa, Hospet.
In C.R. No. 52/88
I PARTY
Smt. Ramulamma,
W/o Sanjeevappa Hospet.
In C.R. No. 50/88
Smt. Sunkamma,
W/o Govindappa Hospet.

VS. II PARTY.

- (1) The Managing Partner
Sankalapuram Iron Ore Mines of M/s. RBSSN Kariganur P.O. Hospet Talq. Bellary Dt.
- (2) Shri T.G. Raghavulu Contractor, Sankalapuram Iron Ore Mines of M/s. RBSSN, Kariganur P.O. Hospet Taluk. Bellary District.

APPEARANCES

For the I party Shri U.B. Threitha Rao, President,
MML & Mines Employees Union
Sri Panduranga Swamy Temple, Hospet.
For the II Party Shri M.K. Ajjampur, Personnel Manager
Sankalapuram Iron Ore Mines, Hospet

AWARD

Government of India, Ministry of Labour has made the following references by orders shown below

Sl. No.	C.R. No.	Order No. and Date	Name of the Employee
1.	26/88	L 26012/4/88-D.III(B) Dt. 22.4.1988	Smt. Galemma
2.	35/88	L 26012/6/88 D.III(B) dt. 1.8.1988	Shri Govendappa
3.	36/88	L 26012/5/88 D.III(B) dt. 1.1.1988	Shri Themnappa
4.	37/88	L 26012/8/88 D.III(B) dt. 1.8.1988	Shri S. Obaleshi

5.	48/88	L-26012/10/88 D.III(B) dt. 13-9-88	Smt. Ramanjeneyamma.
6.	49/88	L-26012/15/88-D.III(B) dt. 13-9-88	Smt. Govindamma
7.	51/88	L-26012/16/88-D.III(B) dt. 13-9-88	Shri Sanjeevappa
8.	52/88	L-26012/17/88-D.III(B) dt. 13-9-88	Smt. Ramulamma
9.	50/88	L-26012/18/88-D.III(B) dt. 13-9-88	Smt. Sunkamma

2. The point referred in all these cases is whether the II party management was justified in terminating the services of the aforesaid I party workmen.

3. Common questions of fact and law have been involved in these matters and therefore a common award has been passed.

4. During the course of the hearings on 7-2-1989, the I party employee filed an affidavit. After the affidavit was taken on record, the parties were permitted to make their submission. The I party employee submitted that he or she is still continuing in the employment of the II party and that he/she is still in possession of the quarters of the employer and an award may be passed accordingly. The representative of the II party Shri M. K. Ajjampur stated that the employee is still continued in their service.

5. In view of the aforesaid submission, the workman were told that they may continue to work with the II party and the matter will be again verified on 24-2-1989 at Bellary camp.

6. On 24-2-1989 at Bellary camp, the workman and the representative of the management were present and the workmen submitted that they still continue in the service of the II party on the same terms and conditions that the amount paid under cheque by the II party has been realised by them in satisfaction of the claim for back wages etc., and that an award may be passed, closing the reference.

7. The said submissions of the parties have been recorded and their signatures have been obtained.

8. The matter was not at all posted for any purpose on 28-2-1989. However, on 28-2-1989, memos have been filed by the agent for the II party. The I party workmen were not at all called on 28-2-1989 and though the memos are kept in the file, no note of the same has been taken.

9. In the result, awards are passed in all the aforesaid cases to the effect that since the parties admit that all these workmen still continue to be in the service of the II party on the same terms and conditions and since the workmen have no grievance regarding back wages or any other claim, it is ordered that the reference stands closed with an observation that all these workmen continue to be in the employment of the II party on the same terms and conditions and that they are not entitled to any other relief or compensation, back wages etc.

(Dictated to the Stenographer, taken down by her, got typed and corrected by me).

B. N. LAIGE, Presiding Officer
[No. L-26012/4/88-D III (B)]

का.आ. 773:—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार अधिनियम लाईस, बम्बई के प्रबन्धमन्त्र में सम्बद्ध नियोजकों और उनके नर्मागों के बीच, अनुसूच में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार अधिनियम अधिकांश बम्बई-1 के पंचपट को प्रकटित करने के लिए, जो केन्द्रीय सरकार को 21-3-89 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 773.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Indian Airlines, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 21-3-1989

ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

REFERENCE NO CGIT-38 OF 1987

PARTIES :

Employers in relation to the management of Indian Airlines, Bombay.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Management : Mr. M. M. Verma, Advocate.
For the workmen : Mr. Gadkari, Advocate.

INDUSTRY : Airlines STATE : Bombay

Bombay, dated the 15th day of March, 1989.

AWARD

The Central Government in exercise of the powers conferred by Clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, has referred by Clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) tion :—

"Whether the action of the management of Indian Airlines, Bombay in relation to its Main Booking Office at Nariman Point, Bombay in dismissing Shri R. K. Patel, Loader, with effect from 27-11-1978 is justified ? If not, what relief the workman concerned is entitled to ?"

2. Shri R. K. Patel, was dismissed from service for the misconduct of —

"Leaving work without permission after checking in" "theft, fraud and dishonesty in connection with business or property of the Corporation;" abetment of or attempt at abetment of the above misconduct; and

"breach of any Standing Order or any law or rules applicable to the establishment."

3. It was alleged that Shri R. K. Patel was on duty in the T. P. section on 20-7-1978, from 09.45 hours to 17.20 hours and while on duty at about 16.30 hours he removed the Indian Airlines Validity Date Stamp clandestinely from the 'Endorsement Counter and put it in a brief case which belonged to an outsider.

4. The workman was dismissed from service, after an elaborate enquiry, with effect from 27-11-1978. The present reference was made by an order dated 25-8-1987. Before that the workman expired on 6-7-1986. Therefore, his heirs were brought on record.

5. At the hearing of the reference the parties arrived at an amicable settlement and prayed for an Award in terms of the settlement which are as follows :—

"It is agreed that the Employer viz. Indian Airlines, shall pay a sum of Rs. 5,000/- as ex-gratia payment to the widow of the deceased workman in full and final settlement of all claims made by the workman

in the pending adjudication before this Hon'ble Tribunal in the above Reference.

The said payment shall be made within four weeks from the date of this settlement.

In view of the aforesaid settlement reached by and between the parties, the parties submit that the Hon'ble Tribunal be pleased to pass an award in terms of the settlement."

6. As the workman is dead, there would not have been any question of his reinstatement in service even if he would have succeeded in this Reference. In view of this position and also in view of the nature of the accusation levelled against him the settlement appears to me to be fair and just under the circumstances. I, therefore, pass an award in terms of the settlement which are re-produced above. Award accordingly.

M. S. JAMDAR, Presiding Officer
[No. L-11012/18/86-D. II(B)] [D. III(B)]

का. घा. 774 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार अधूरा शक्ति उर्जा विभाग के अधूरा शक्ति खनिज प्रभाग के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबन्ध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2, धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-3-89 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 774.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Atomic Mineral Division of Deptt. of Atomic Energy and their workmen, which was received by the Central Government on the 21-3-1989.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD.

REFERENCE NO. 304 OF 1987

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1) (d) of the I. D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Atomic Mineral Division of Deptt. of Atomic Energy and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen : Shri J. P. Singh, Advocate.
On behalf of the employers : Shri Samiran Paul, Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY : Atomic Energy

Dated, Dhanbad, the 13th March, 1989

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-29012/25/87-D. III(B), dated, the 8th December, 1987.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Atomic Minerals Division of Deptt. of Atomic Energy,

A.M.D. Complex, Begampet, Hyderabad in terminating the services of Shri Ram Naresh Singh w.e.f. 2-12-1986 was justified? If not, to what relief is the workman entitled to?"

The case of the concerned workman Shri Ram Naresh Singh is that in August, 1984 he was appointed as a Mazdoor by the Officer Incharge of the Department of Atomic Energy Atomic Mineral Division, Govt. of India, Camp Nagnaha district Palamau, Bihar. He has been working regularly since then to the satisfaction of all concerned till the date of termination of his services. On 21-11-86 the concerned workman was directed by the Officer Incharge of Nagnaha Camp to report for duty at Mohaldih camp district Singbhum (Bihar). The concerned workman reported for duty to the Officer Incharge of Mohaldih camp everyday after 21-11-86. The Officer Incharge simply used to listen to the concerned workman every day but did not allow him to join duty. Finally on 2-12-86 the Officer Incharge of Mohaldih Camp verbally told the concerned workman that his services were no more required and that his services stood terminated. The Officer-incharge did not communicate any reason for the termination of his services of the concerned workman. The concerned workman is idle since 2-12-86. After the termination of the services the concerned workman approached the authorities several times for allowing him to resume his duties but he was not allowed. The concerned workman had put in 154, 296 and 296 days attendance in the year 1984, 1985 and 1986 respectively excluding the authorised leave during the period from August, 1984 to the date of the termination of his services. The concerned workman has thus put in more than 240 days attendance in the year 1985, 1986 and the concerned workman deemed himself to have been made permanent in his services as per Model Standing Orders and decisions of different courts and Supreme Courts. The termination of the services of the concerned workman in not allowing him to resume his duties without assigning any reason was illegal, arbitrary and unjustified action of the management. The concerned workman raised an industrial dispute regarding his illegal and unjustified termination of services before the ALC (C) Chasibasa Singbhum vide his representation which was received in the office of the management on 6-3-87. The management submitted its comments before the ALC(C) in which the management admitted that the concerned workman had put in 240 days attendance in 1986. The conciliation before the ALC(C) ended in failure and thereafter the present reference was made to this Tribunal for adjudication. The concerned workman, before raising the industrial dispute, sent a Lawyer's notice upon the management to which the management replied vide its letter dated 11-2-87 denying that any reason of the name of Ram Naresh Singh was worked during the period from August, 1984. The management has thus given contradictory facts with a mala fide intention in order to deprive the concerned workman of his legitimate claim for continuance in employment. The services of the concerned workman were terminated in violation of the legal provision and principles of social justice. It is further stated in the rejoinder of the concerned workman that there was relationship of employer and employees between the management and the concerned workman. The concerned workman had nothing to do with the research and development activities of the atomic energy division. The Atomic energy mineral division is mainly concerned with the obtaining of materials for scientific research and as such it comes within the definition of Industry as given in the Industrial Disputes Act. The management of atomic energy division is not qualified for exemption from the purview of the definition of Industry as per judgement of the Hon'ble Supreme Court reported in SCLJ (15) page 121 (Bangalore Water Supply Works Vrs. A. Rajagopalan). The termination of the services of the concerned workman will amount to retrenchment as defined under Section 2(cc) of the I.D. Act and since the provision of Section 25F of the I.D. Act have not been complied with by the management the order of his termination is invalid and consequently the concerned workman is entitled to reinstatement and back wages. On the above facts it is prayed that it be held that the action of the management in terminating the services of the concerned workman is unjustified and that the concerned workman is entitled to reinstatement with full back wages and other benefits from the period of his idleness.

The case of the management is that the Atomic Mineral Division is entrusted with the responsibility of survey and exploration of atomic mineral for the peaceful use of nuclear energy. This is a sovereign function and cannot be eliminated from the state. For obvious reason of the security of the State this function cannot be allowed to be carried out by the private parties. The sovereign function of the state qualified for exemption from the purview of the definition 'Industry' as per judgement of the Hon'ble Supreme Court in Bangalore Water Supply-Vrs-A. Rajappa. The application of the concerned workman cannot be entertained basically on the ground that the atomic mineral division is not an industry and does not fall within the scope of the I. D. Act. The concerned workman was engaged purely on temporary and casual basis on Muster roll for a job of very temporary nature intermittently for short duration. No appointment letter was issued to the concerned workman and no appointment was given to him. He was engaged with a clear understanding that his engagement was for a very short period and for the specific period only and not on regular arrangement. The concerned workman was not working regularly at the camp. It is false to say that the concerned workman was directed by the Officer Incharge of Nagnaha Camp to report at Mahaldih Camp. There was no work to be assigned to the concerned workman at Mohaldih Camp and as such there was no question of directing the concerned workman for reporting for duty to the Officer Incharge at Mohaldih Camp. The concerned workman had already been disengaged at Nagnaha camp on 21-11-86 when the camp was closed and nobody had asked him to join at Mahaldih camp. The concerned workman was employed for a short period for some specific work and the moment the work was over he was dispensed with and as such there was no question of serving him with any notice. The concerned workman was not holding any post in the department at Nagnaha camp. The concerned workman had put in 147 days, 282 days and 237 days in the year 1984, 1985 and 1986 respectively including the paid rest days. The atomic mineral division conducts survey and preliminary drilling work in selected areas and the officers move from place to place depending upon the nature of work assigned to them and to meet the local needs some daily rated labourers are engaged and are paid wages from contingency the moment the particular assignment is over they are dispensed with. The atomic mineral division is not an industry and there is no question of keeping any person as a workman. The management had taken a stand before the ALC(C) Chaibasa that the atomic mineral division is not an industry but even then the ALC(C) sent a failure report to the Ministry of Labour Govt. of India. The concerned workman had sent a Lawyer's notice giving the address of the concerned person as Ramnaresh Singh, Dealing Asstt. atomic energy division camp, Nagnaha. The management had sent a reply to the said notice informing that there was no such person by name Shri Ram Naresh Singh appointed by the management on its rolls. The designation of Dealing Asstt. given in the Lawyer's notice indicated that the concerned person was employed in a clerical post. The management has not violated any legal provision and there was no mala fide intention on the part of the management in non-engaging the concerned workman as Atomic Mineral Division is not an "Industry". There was no question of giving any notice or wages in lieu of notice under Section 25-F of the I.D. Act. On the above facts it is submitted on behalf of the management that it be held that the reference is invalid and without jurisdiction and that the action of the management is justified in terminating the services of the concerned workman.

The points for determination in this reference are (1) whether this Tribunal has jurisdiction to decide this case in view of the definition of Section 2(j) of the I. D. Act and (2) whether the termination of the services of the concerned workman was justified.

The concerned workman examined himself in support of his case. The management examined two witnesses in support of their case. The documents of the concerned workman are marked Ext. W-1 to W-12 and the documents of the management is marked Ext. M-1.

Point No. 1

During the course of hearing of the case the management has laid emphasis on the point whether this Tribunal has jurisdiction to decide this case in as much as in accordance with the submission made on behalf of the management, Atomic Mineral Division does not come under the purview of "Industry" as defined in Section 2(j) of the I. D. Act. If it is held that Atomic Mineral Division is not an industry under Section 2(j) of the I.D. Act there will be no jurisdiction for this Tribunal to decide the case whether the termination of the services of the concerned workman was justified or not. The learned counsel for the workman has laid great emphasis on the principles decided by their Lordship of the Supreme Court in Bangalore Water Supply case reported in Supreme Court SCLJ-15 121 for deciding that Atomic Mineral Division is Industry within the meaning of Section 2(j) of the I. D. Act. The said decision in Bangalore Water Supply was made by their Lordship on 21-2-78. Their Lordship said "So we proceed to formulate the principles, deducible from our discussions, which are decisive, positively and negatively, of the identity of "Industry" under the Act. We speak, not exhaustively, but to the extent, authoritatively until overruled by a larger bench or superseded by the legislative branch." It will thus be apparent from the quotations made above that the decision was authoritative until superseded by legislative branch. "Industry" is defined in Section 2(j) of the I.D. Act and their Lordship had dwelt upon the subject "Industry" with reference to the definition of Section 2(j) as then existed i.e. on February, 21-2-76 and their Lordships had themselves stated in Bangalore Water Supply case that the decision authoritative until superseded by the legislative branch. The legislative branch of the Government indeed made a change in the definition of "Industry" in Section 2(j) of the I.D. Act. The definition of Industry under section 2(j) of the I. D. Act formerly was "Industry" means any business, trade undertaking, manufacture or calling of employers and includes any calling services, employment, handicrafts, industrial occupation or avocation of workmen. The said definition has been superseded by the new definition of "Industry" in Section 2(j) of the I. D. Act vide Act 46 of 1982. The definition of Industry in Section 2(j) now stands as follows (I will refer to the relevant portion of the definition) "Industry" means any systematic activity carried on by Corporation between an employer and his workmen (where such workmen are employed by such employer directly or by or through any Agency including a contractor) and for the production supply or distribution of goods or services with a view to satisfy human wants or wishes (not being wants or wishes which are merely spiritual or religious in nature) whether or not (i) any capital has been invested for the purpose of carrying on such activity or (ii) such activity is carried on with a motive to make any gain or profit and, includes (a) any activity of the dock labour board established under Section 5(A) of the Dock Workers Act, 1948 (b) any activity relating to the promotion of the scales or business or both carried on by an establishment but does not include: [(i) to (v) :—Not necessary] (i) any activity of the Govt. relating to the sovereign function of the Government including all the activities carried on by the department of the Central Govt. dealing with defence research, atomic energy and space. Thus it will appear from the superseded definition of "Industry" in Section 2(j) of the I. D. Act that any activity of the Government relating to the sovereign function of the Govt. including all the activities carried on by the department of Atomic Energy cannot be included in the definition of Industry. Admittedly atomic mineral division is in the department of Atomic Energy. MW-1 who was Resident Geologist of Atomic Mineral Division at Nagnaha Camp has stated that they first do survey work for Atomic Minerals in the camp and if atomic mineral is found they report about it to the Atomic Mineral Division. He further stated that the work of Atomic Mineral Division is confined to the research and not to the production of the atomic Minerals Division. MW-2 Shri Ramchandran is presently working as Section Incharge of Rare Metal and Rare earth investigation. He was coordinator of Nagnaha camp from 1984 to 1986. He has stated that their work is only to survey atomic mineral and they do not produce, supply or distribute any materials. He has stated that uranium and thorium are used in the nuclear programme of the atomic energy of the

Govt. of India. Thus the evidence of the two management's witnesses shows that atomic mineral division does only survey work for atomic mineral and when any atomic mineral is found the matter is reported to the atomic mineral division and thereafter the work of atomic mineral division ends. Their work is only confined to the research and they do not work in the production of atomic minerals. The work done by the atomic minerals division as stated by the management's witnesses and the definition of "Industry" in Section 2(j) of the Act 46 of 1982 clearly excludes the activities carried on by the atomic energy and accordingly the atomic mineral division of the department of Atomic Energy will not come within the definition of Section 2(j) of the I.D. Act. The activities of the atomic mineral division, of the department of Atomic Energy is not an Industry and as much the dispute raised by the concerned workman is not an industrial dispute thereby ousting the jurisdiction of the Tribunal to adjudicate upon the matter referred to by Government. As I have held above that the matter relating to the Atomic Mineral Division of the department of Atomic Energy, Govt. of India is not an industry the subject matter referred to this Tribunal for adjudication is outside the jurisdiction of this Tribunal and the matter cannot be adjudicated by this Tribunal.

Point No. 2

In view of the fact that this Tribunal has no jurisdiction to adjudicate the matter referred to this Tribunal, it will not at all be wise to discuss the facts on merit of the case. The merit of the case can have value only when this Tribunal has jurisdiction to decide the dispute referred to this Tribunal. As such I refrain to discuss the other matters relating to the facts of this case.

An Award is passed accordingly.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-29012/25/87-D. III(B)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

प्रादेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1989

का. आ. 775 :—तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व पेट्रोलिएम इम्प्लाइज यूनियन, बंबई, आ. एन. जी. सी. इम्प्लाइज यूनियन, अहमदाबाद, आ. एन. जी. सी. इम्प्लाइज एम्प्लॉयर्स, अकलेखर, आ. एन. जी. सी. पूर्वोक्त इम्प्लाइज एम्प्लॉयर्स, शिव सागर (असम) तथा नेशनल यूनियन आफ आ. एन. जी. सी. इम्प्लाइज, देहरादून कर्मों है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और उक्त नियोजकों और कर्मचारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के अधीन एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थ्य के लिए निर्दिष्ट करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थ्य करार का एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त करार को एतद्वारा प्रकाशित करती है।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन) पक्षकारों के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, प्रायः : तेल भवन, देहरादून।
कर्मचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1. पेट्रोलिएम इम्प्लाइज यूनियन, तेल रसायन भवन, सामने बैरट वर्कशाप, त्रिजक नं० दादर, बंबई।

2. श्री. एन. जी. सी. इम्प्ला-
डज यूनिशन, कालोनी रोड,
रोड, साबरमती, अहमदाबाद।

3. श्री. एन. जी. सी. इम्प्ला-
डज एसोसिएशन, बी-11, बी.
श्री. एन. जी. सी. कालोनी,
अकलेश्वर।

4. श्री. एन. जी. सी. पूर्वांचल
इम्प्लाडज एसोसिएशन, श्री.
एन. जी. सी. कालोनी
काम्पलेक्स, शिवासागर (असम)

5. नेशनल यूनिथन आफ श्री.
एन. जी. सी. इम्प्लाडज,
36/13, चक्रवर्ती रोड,
देहरादून।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित विवाद को श्री बी. एस. देशपांडे,
भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, ए-19 गीताजी, नई
दिल्ली-110017 के माध्यमस्थ के लिए निर्दिष्ट करने का करार
किया गया है।

(1) निम्नलिखित विवादग्रस्त विषय: क्या उपरोक्ता मूल्य सूचकांक
200 तथा 492 के मध्य
अंतर को प्रस्तुत करने वाले
292 प्वाइंटों के रेंज ग्रुप के
लिए प्रति प्वाइंट 1.30
रुपय की मंहगाई भत्ते की दर
में उत्तरोत्तर संशोधन करने
का कर्मकारों का दावा उत्पन्न
होता है और वह मंहगाई भत्ता
दर में यथा पूर्व स्थिति की
अवधि से संबंधित खंड संख्या
4.5, जिसे एक पक्षकार के
रूप में तेल एवं प्राकृतिक गैस
आयोग के प्रबंधन और दूसरे
पक्षकार के रूप में उनके कर्म-
कारों के मध्य विनांक 18-11-
83 को हुए समझौता आपन
में समाविष्ट किया गया है, के
अनुसरण में, और केन्द्रीय
सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों
के लिए तथा तेल एवं प्राकृतिक
गैस आयोग द्वारा उसके कार्या-
न्वयन के लिए साप्ताहिक
मंहगाई भत्ता फार्मुला की पुन-
रीक्षा करने के लिए गठित
त्रिपक्षीय मंहगाई भत्ता समिति
का रिपोर्ट पर विनांक 16
अप्रैल, 1985 के भारत
सरकार के निर्णय के संदर्भ में
समर्थनीय है।

कर्मकार यह तर्क करते हैं कि
दिनांक 18-11-83 का समझौता

आपन का खंड 4.5 उसी
विषय पर दिनांक 20-11-
79 को हुए समझौते आपन
में यथा समाविष्ट खंड 4.2.2
के अम में है और इसे
उसके साथ पढ़ा जाना
चाहिए। प्रबंधन का
यह तर्क है कि विनांक 22-
11-79 को समझौता आपन के
उक्त निदिष्ट खंड का विनांक
18-11-83 के तहत करार के
संदर्भ में अधिक्रमण होता है।

इसलिए माध्यस्थ के लिए
निम्न विषय हैं:—

(1) क्या कर्मकारों का दावा
उत्पन्न होता है और कायम
रखने योग्य है, तथा

(2) यदि हा, तो किस सीमा तक
और किस तारीख से?

(2) विवाद के पक्षकारों का विव- जैसा कि ऊपर पृष्ठ 1 पर
रण, जिसमें अंतर्बलित स्था- दर्शाया गया है।
पन या उपक्रम का नाम और
पता भी सम्मिलित है।

(3) मामले में कर्मकार का नाम जैसा कि ऊपर पृष्ठ 1 पर दर्शाया
यदि वह स्वयं विवाद में अंत- गया है।
र्गस्त हो या यदि कोई संघ
प्रस्तुत कर्मकारों का प्रति-
निधित्व करता हो तो उसका
नाम

(4) प्रभावित उपक्रम में नियोजित
कर्मकारों की कुल संख्या 27,534

(5) विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भा-
व्यतः प्रभावित होने वाले
कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या 27,534

माध्यस्थ अपना पंचाट छह मास की कालावधि या इतने और
समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया
जाय, देगा।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले: ह०/—(बी. एस. सचदेव)
महाप्रबंधक (कार्मिक),
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग,
तेल भवन, देहरादून।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले ह०/—(गजा कुलकर्णी) अध्यक्ष,
पेट्रोलियम इम्प्लाडज यूनिशन बंबई।
ह०/—(ओ. पी. श्रीवास्तव),
संयुक्त सचिव, श्री. एन. जी.
सी. इम्प्लाडज यूनिशन, अहमदा-
बाद।

साक्षी

BETWEEN

1. ह०/- (जे पी माथुर) महा-
संयुक्त प्रबंधक (आई आर)
ह०/- (सी एस नायर) महा-
मन्त्रि, ओ एन जी सी
इम्प्लाइज एमोसिगेशन,
अंक्लेश्वर।
ह०/- (अपठनीय) अध्यक्ष,
ओ एन जी सी पूर्वांचल
इम्प्लाइज एमोसिगेशन, शिव
सागर, (असम)।
ह०/- (डी एन श्रवत) अध्यक्ष,
नेशनल यूनियन आफ ओ एन
जी सी इम्प्लाइज देहरादून।

क.री.सं 14-3-89

माध्यस्थ्य की सहमति

वी एम देशपांडे

भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश विल्ली ए-19 गीतान्जलि नई दिल्ली-110017
उच्च न्यायालय उपाध्यक्ष इंडि- फोन नं 663132
यन काउन्सिल आफ आर्बीट्रेशन 2-26-2-89
फैक्टो चार्टर्ड इंडस्ट्रीयूट आफ
आर्बीट्रेशन लंदन तथा उनकी
भारतीय शाखा के अध्यक्ष भूत-
पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, इंडियन
नॉ इंडस्ट्रीयूट

मैं एतद्वारा परिवर्तनीय संहगार्ड भस्ते के संबंध में सेन एवं प्राकृतिक
गैस आयोग और उनके कर्मचारों के मध्य औद्योगिक विवाद अधिनियम
की धारा 10-क के अधीन माध्यस्थ्य के रूप में कार्य करने की सहमति
देता हूँ

ह०/-

(वी एम देशपांडे)

[संख्या एम 30013/1/89-आई. आर. (बिबिध)]

बी. के. गर्मा, डैम्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 30th March, 1989

S. O. 775.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the Management of Oil and Natural Gas Commission, Dehradun and their workmen represented by Petroleum Employees Union, Bombay, ONGC Employees Union, Ahmedabad, ONGC Employees Association, Ankleswar, ONGC Purbanchal Employees Association, Sibsagar (Assam) and National Union of ONGC Employees, Dehradun.

And whereas, the said employers and their workmen have by a written agreement under sub section (1) of section 10A of the I.D. Act. 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government a copy of the said arbitration agreement;

Now therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10-A of the said act, the Central Government hereby publishes the said agreement.

AGREEMENT

(Under Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947)

Name of the parties :

Representing Employer : Oil & Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun.

- Representing Workmen: 1. Petroleum Employees Union, Tel Rasayan Bhavan, Opp. BEST Workshop, Tilak Road, Dadar, Bombay.
2. ONGC Employees Union, Kalol-Koba Road, Sabarmati, Ahmedabad.
3. ONGC Employees Association, B-11-B ONGC Colony, Ankleshwar.
4. ONGC Purbanchal Employees Association, ONGC Colony Complex, Sibsagar (Assam).
5. National Union of ONGC Employees, 36/13, Chakrata Road, Dehradun.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri V.S. Deshpande, former Chief Justice, Delhi High Court, A-19 Gitanjali, New Delhi-110017 :-

(i) Specify matters in dispute :

Whether the claim of the workmen to seek upward revision in D.A. rate of Rs. 1.30 per point for the range group of 292 points representing the difference between CPI 200 and 492 arises and is maintainable in pursuance of the clause No. 4.5 relating to the period of status quo in the DA rate as incorporated in Memorandum of Settlement dated 18-11-1983 between the Management of the Oil & Natural Gas Commission on one side and their workmen on the other and in the extent of the Govt. of India's decision dated 16th April, 1985 on the report of the Tripartite DA Committee constituted for reviewing the then existing DA formula for employees of Central Public Enterprises and its implementation by ONGC.

The workmen contend that the clause 4.5 of the Memorandum of Settlement dated 18-11-1983 is in continuation of and should be read with clause 4.2.2 on the same issue as incorporated in the Memorandum of Settlement dated 22-11-1979. The Management contends that the above referred to clause

of Memorandum of Settlement dated 22-11-1979 stands superseded in the light of the fresh agreement dated 18-11-1983.

Therefore, the points for arbitration are :-

(i) Whether the claim of the workmen arises and is maintainable; and

(ii) if so, to what extent and with effect from which date ?

(ii) Details of the parties to the dispute including name and address of the establishment or undertaking involved. As indicated above at page 1.

(iii) Name of the workmen in case he himself is involved in the dispute or the name of the union, if any, representing the workmen in question; As indicated above at page 1.

(iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected. 27,534

(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute. 27,534

The arbitrator shall make his award within a period of six months from the date of reference or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing.

Witnesses : Signature of the Parties

1. Sd/- (J.P. Mathur) Representing employer :
Joint Manager (IR)

2. Sd/- Illigible. (B.S. SACHDEV)
General Manager (Personnel)
Oil & Natural Gas Commission.
Tel Bhavan, Dehradun.

Representing workmen :
Sd/-
(RAJA KULKARNI)
President.

Petroleum Employees Union,
Bombay.

Sd/-
(O.P. SRIVASTAVA)
Jt. Secretary.

ONGC Employees Union,
Ahmedabad.

Sd/-
(C. S. NAIR) Gen. Secretary,
ONGC Employees Association
Ankleshwar.

Sd/-
Illigible President.

ONGC Purbanchal Employees
Association, Sibsagar (Assam).

Sd/-
(D.N. DHAWAN)
President.

Delhi, Dated 14-3-1989

National Union of ONGC
Employees, Dehradun.

CONSENT OF ARBITRATOR

V.S. DESHPANDE A-19, GITANJALI,
Former Chief Justice, Delhi High Court NEW DELHI
Vice President, Indian Council of 110017
Arbitration Fellow Chartered Institute of Phone : 663132
Arbitrators London and Chairman of its 26-2-89
Indian Branch Former Executive Chairman
Indian Law Institute.

I hereby consent to act as Arbitrator under S.10-A
of the Industrial Disputes Act between ONGC and its work-
ment regarding variable dearness allowance.

Sd -

(V.S. DESHPANDE)
[No. L-30013/1/89-IR (Misc)]
V.K. SHARMA, Desk Officer.